हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

01-09-2025/1400/NS-AG/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री त्रिलोक जम्वाल : **अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।**

अध्यक्ष : अगर प्रश्न से जुड़ा हुआ मामला है तो प्रश्न काल के बाद ही डिस्कस होगा। स्थगित प्रश्न की सूचना एकत्रित की जा रही है। I have ordered my Secretariat कि सूचना एकत्रित की जा रही है और उसमें शीघ्र सूचना एकत्रित करके उपलब्ध करवाने बारे लिखा जाए। कल तक सूचना आ जाएगी तो उसको यहां लगा देंगे। ...(व्यवधान) अभी मैंने अलाउ ही नहीं किया है। पहले आप नियम बताओ फिर मैं अलाउ करूंगा। आप इसको पढ़ो। श्री त्रिलोक जम्वाल जी आप बोलिए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पिछले सत्र में पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में जो एक्साइज पॉलिसी है उसके तहत हमारे रिसीट्स व पेमैंट्स क्या हैं? मैंने इसकी जानकारी चाही थी लेकिन जवाब में आया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह प्रश्न जब परसों लिस्ट हुआ और मैंने इस प्रश्न को लिस्ट ऑफ बिजनैस में देखा था लेकिन आज सुबह इस प्रश्न को वहां से हटा दिया गया था। जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसमें रूल-53 है।

अध्यक्ष : आप इस रूल को पढ़ें।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, **Withdrawal or postponement of questions.**
A member may, with the consent of the Speaker, by notice, given at any time before the sitting for which his question has been placed on the list, withdraw question, or make a request to postpone it to a later day to be specified in the notice, and on such later day, the question shall subject to the provision of Rule 43 be placed on the list after the questions tabled for the day:
Provided that a postponed question shall not be placed on the list until two clear days have expired from the day when the notice of postponement has been received by the Secretary.

01-09-2025/1400/NS-AG/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो आप बोल रहे हैं उसको मैंने रिजैक्ट नहीं किया है। आप इसकी डॉयरैक्शन भी पढ़ लो। डिलीट नहीं हुआ और न ही विलोप किया है। It will be listed for tomorrow in any case. Since there was no information, - information is being collected - so I have given them more chance to collect the information by tomorrow.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्थाओं से संबंधित है। जब एक बार लिस्ट हो गया और अगर सचिवालय ही डिसीजन कर लेगा। ...(व्यवधान) श्री त्रिलोक जम्वाल जी, आप बैठ जाएं, एक मिनट बैठ जाएं।

Speaker: Even if the question is listed and the reply is on the Table of the House and still a Hon'ble Member desires that he wants to withdraw this question ...(Interruption) the discretion is with the Speaker whether to allow, not to allow. Many Hon'ble Members have requested this Secretariat and personally to me also, at the various stages, in some questions, I allowed, and in some questions, I disallowed. So it is the sole discretion of the Chair. I have to watch the interests of the Hon'ble Members vis-à-vis the time of the House also. This is a very precious time for one hour. Certainly, tomorrow I will be taking a decision again that why the information is not supplied to the Vidhan Sabha Secretariat.

I would also like to refer Rule 346 - Residuary Powers- which is very specific.

Residuary powers.—All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner, as the Speaker may, from time to time, direct.

So it is sole discretion of mine, which I have used and applied in the larger interest - ...(Interruption) Please, please, let me complete - of the House because Question Hour is important Hour where, you see, interests of lot of Members are involved. So I have to see the interests of other Members also

vis-à-vis your interest also. I assure you that I will make the Government to supply that information to this Secretariat. This much assurance I can give you. Thank you. आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

01.09.2025/1405/RKS/AG-1

अध्यक्ष.... जारी

...(Interruption) यह तो interpretation of law/rule था। वकील होने के नाते मैंने आपको अलाउ कर दिया। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, ये interpretation of Rules हैं। आप प्रश्न काल के बाद बोल लेना। ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी when I am assuring all the Hon'ble Members that I will be watching your interests, then you don't have faith on me. ...(Interruption) You have no faith on me. ...(Interruption) You have no faith on the Speaker. ...(Interruption) Listen. Trilok ji, don't be enraged. Please. I am listening to you. The mic is with you. So you need not to increase your Blood Pressure. You can speak slowly/lightly also, in a good mood also. What I am trying to say is ...(Interruption) ठाकुर साहब यह मेरी sole discretion है। मैंने सारे नियम पढ़ लिए हैं। Still I am assuring the Opposition including the Hon'ble Leader of the Opposition plus the Hon'ble Members, I will see to it that the information is supplied. ठाकुर साहब क्या आपने बोलना ही है? ...(व्यवधान) आपने कहीं जाना तो नहीं है? अगर आपने कहीं जाना है फिर मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। ...(Interruption) Please, please. I am so decoratively dressed up today that this neck tie may attract you to sit here. Please. श्री जय राम ठाकुर जी आप अपनी बात रखिए।

01.09.2025/1405/RKS/AG-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत विचित्र परिस्थिति है कि विधान सभा के एक प्रश्न का दो साल तक उत्तर नहीं आ रहा है। आपने पिछले सत्र में भी और इस सत्र में

भी यह कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आज आपने उस प्रश्न को डिलीट कर दिया है लेकिन यह बात रिकॉर्ड में नहीं है।

अध्यक्ष : हमने इस प्रश्न को आज की सूची से डिलीट किया है।

श्री जय राम ठाकुर : हमें यह इंफोर्मेशन नहीं आई थी। जब विधान सभा सचिवालय ने स्वीकार कर लिया कि प्रश्न लग गया है और उसके बाद यह कहा जाए कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रश्न पोस्टपोन में चला गया। आपने फिर से स्वीकार कर लिया कि हम इस प्रश्न की सूचना एकत्रित कर रहे हैं। हमें इस प्रश्न की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आप आज भी यह कह सकते थे कि सूचना एकत्रित की जा रही है लेकिन आपके बिजनैस से वह प्रश्न ही गायब है। ...(व्यवधान) उसके बाद आर0टी0आई0 में जवाब आ जाता है। अगर हमें आर0टी0 आई0 के माध्यम से ही जवाब लेना है तो फिर हम चुने हुए प्रतिनिधि कहां जाएं? इनके पास आर0टी0 आई0 की इंफोर्मेशन है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2025/1410/बी.एस./ए.एस.-1

व्यवस्था का प्रश्न जारी
श्री जय राम ठाकुर जारी...

लेकिन इस विधान सभा में हमें लोगों ने चुनकर भेजा है परंतु यहां पर हमें सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हम इसके अलावा कहा जाएं? अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका जो प्रोटेक्शन और दायित्व चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति है, कृपया उसका निर्वहन करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जो डिस्क्रिशन की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिशन rare of the rarest chances में लिया जाता है। परंतु आप अपनी तरफ से डिस्क्रिशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में विपक्ष के विधायक कहां जाएंगे और कहां अपनी बात रखेंगे? इस प्रश्न का आर.टी.आई. में जवाब आ चुका है लेकिन विधान सभा में इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। यह हमारे अधिकारों के ऊपर भी प्रश्नचिन्ह है और

उसके साथ-साथ विधान सभा सचिवालय के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। आर.टी.आई. के माध्यम से हम स्वतंत्र हैं और कभी भी उस सूचना को ले सकते हैं। लेकिन विधान सभा के अंदर हम प्रश्न का उत्तर नहीं ले सकते हैं। आप अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारे अधिकार वहीं-के-वहीं धरे-के-धरे रह जाएंगे।

अध्यक्ष : आदरणीय ठाकुर साहब, आपकी बात आ गई है, कृपया बैठ जाइए।

श्री जय राम ठाकुर : यह हमारे अधिकारों के ऊपर बहुत कुठाराघात है और यह हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को सहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो सूचना आपके सचिवालय के माध्यम से सरकार से आनी थी उस सूचना को हम माननीय सदन में अपने आप ही उपलब्ध करवा देंगे क्योंकि यह सूचना हमारे पास है। हम चाहते हैं कि आप हमारे माननीय सदस्य को इसके लिए अनुमति दें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी और श्री केवल सिंह पठानिया जी, कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) This is my issue. I have the capacity to deal all such kind of issues. आदरणीय ठाकुर साहब, मैंने पहले ही आपको विश्वास दिला दिया है कि आपने जो प्रश्न किए हैं उन्हें विलोप नहीं किया

01.09.2025/1410/बी.एस./ए.एस.-2

जाएगा। वे सूचनाएं देनी ही पड़ेगी। अब किसी ने इन डिस्क्रिशन्ज, डायरेक्शन्ज और रुल्ज की एप्लिकेशन अलौ की या नहीं की that is apart from the issue. Since I am a legal and well versed with the Rules also. तो मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि आप मेरे ऊपर फेथ रखिए, मैं आपका विश्वास कैसे टूटने दूंगा मैं एक और रूल, रूल-15 पढ़ रहा हूं। पहले तो मैंinherent powers का मैंने जिक्र कर दिया which this Chair has inherent powers under the Constitution also. No court can take any cognizance of the issues which we are discussing inside this House and the Hon'ble Members too have the full immunity for that also. However, that immunity to be exercised in a reasonable manner and the discretion is also to be used in a reasonable manner, which I have used. Rule-15 of the Directions

by Speaker regarding Postponement of the Questions says that: When an answer is given that the information is being collected, it would be taken as if the Government have asked for postponement. When the information is collected, it otherwise mean the Government itself has asked for the postponement under Rule-15. Such questions will normally be re-fixed after one week or even earlier if so decided by the Speaker, तो ये डिम्ड है कि जब सूचना नहीं है तो postponement of question डीम्ड है। तो मैंने जो डिम्ड डिस्क्रिशन है उसका इस्तेमाल किया है कल कोशिश करेंगे कि दोबारा से टेबल कर देंगे उनको अगर नहीं आएगी तो then you have a prerogative to take your actions, whatever you feel like. आज तो हो गया न, कल कर देंगे, कल इसको लिस्ट कर देंगे I am ensuring this House tomorrow we will list it. Please now, let's take today's Business. Now Question Hour, Question No. 3389. मैं एक प्रश्न ले लेता हूं, आपने कुछ बोलना है मुख्य मंत्री जी, अच्छा आप बोलिए।

01.09.2025/1410/बी.एस./ए.एस.-3

मुख्य मंत्री : मैं प्रदेश में आई बाढ़ के संबंध में स्टेटमेंट देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आप स्टेटमेंट प्रश्न काल के बाद दे दीजिएगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रिंसिपल तोड़ा है। आपने पहले प्रश्न काल आरंभ नहीं किया। इसलिए मैं अपनी स्टेटमेंट पहले देना चाहा रहा हूं। यह स्टेटमेंट बाढ़ और आपदा पर है। जब प्रश्न काल के बीच में आपने विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका दिया तो हमें भी मौका दीजिए। इसलिए मैं बाढ़ पर स्टेटमेंट अभी देना चाहता हूं

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

1.09.2025/1415/डी0टी0/ए0एस0 -1
मुख्य मंत्री जारी

जिसके लिए नियम-67 के तहत विपक्ष के हमारे साथी काम रोको प्रस्ताव लेकर आए थे और प्रश्न काल को सस्पेंड कर दिया गया था। आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि नियम-130 के तहत चर्चा के लिए कहा। लेकिन फिर विपक्ष के साथी नहीं माने और हमनें उसको भी एक्सेप्ट किया और आज उसी आपदा से संबंधित मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप प्रश्नकाल के बाद अपनी स्टेटमेंट दे देना।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी डिस्क्रेशनेरी है, आप विपक्ष वालों को एक छोटे से सवाल के लिए बोलने दे रहे हैं, जिसका आप जवाब इन्हें दे चुके हैं लेकिन आपदा के लिए आप मुझे स्टेटमेंट नहीं देने दे रहे। मैं आपसे बोलने की आज्ञा चाहा रहा हूं, आपने अपनी डिस्क्रेशनेरी प्रश्न काल में यूज की आपको मेरी स्टेट मेंट के लिए भी यूज करनी चाहिए।

अध्यक्ष : मैं अपनी डिस्क्रिशन को यहां इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं because this is the Question Hour and this issue was pertaining to Questions only. Hon'ble Chief Minister please. ...(Interruption) I am requesting you क्योंकि यह प्रश्न काल इसमें प्रश्न को पूछने दो उसके बाद आप स्टेटमेंट दे देना।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आपदा पर मुझे स्टेटमेंट देने दीजिए।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आप प्रश्न काल के बाद अपनी स्टेटमेंट दे देना। ...(व्यवधान) आप उसके पास स्टेटमेंट दे देना। अभी प्रश्न काल होने दो।

मुख्य मंत्री : मैं बोल तो सकता हूं ...(व्यवधान) आप मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे। ...(व्यवधान) आप सदन के नेता को स्टेटमेंट देने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे।

Speaker : The House is adjourned and we will reassemble at 3 O'clock.

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

01.09.2025/1500/डी.सी.-एन.जी./1

(माननीय सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 03:00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : इससे पहले की मैं शून्य काल आरम्भ करूं, माननीय मुख्य मंत्री wants to give a statement.

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

हिमाचल प्रदेश में मौजूदा आपदा से उत्पन्न स्थिति पर चल रहे राहत कार्यों पर वस्तु-स्थितिः-

1. अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मॉनसून प्रारंभ होने के साथ ही प्रदेश में कई जिलों में बादल फटने, अचानक बाढ़ व भूस्खलन की घटनाएं हुईं जिस पर राहत एवं बचाव कार्यों, सड़क, पेयजल योजनाओं, बिजली आपूर्ति की पुनः बहाली के कार्य व सिंचाई योजनाओं में युद्ध स्तर पर गति प्रदान की जा रही है।
2. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 21 अगस्त से मॉनसून पुनः सक्रिय हुआ। उक्त तिथि से आज दिनांक 1 सितम्बर, 2025 तक प्रदेश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि, बादल फटने व भूस्खलन की कई घटनाएं हुईं। इस दौरान सबसे अधिक प्रभावित जिले, चम्बा, कुल्लू, लाहौल-स्पिति, मण्डी, शिमला, कांगडा व हमीरपुर हुए और किन्नौर जिले में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं।
3. इस वर्ष मॉनसून में अब तक (दिनांक 31 अगस्त 2025 तक) 3 हजार 56 करोड का प्रारंभिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सबसे अधिक नुकसान सड़कों, पुलों, पानी व बिजली की संरचनाओं को हुआ है।

01.09.2025/1500/डी.सी.-एन.जी./2

सबसे अधिक प्रभावित जिले इस प्रकार हैं :-

जिला चम्बा :-

4. अध्यक्ष महोदय, जिला चम्बा में मणिमहेश यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष सभी प्रतिक्रिया बलों व जिला प्रशासन चम्बा से लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस दौरान मणिमहेश यात्रा के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 50 जवान, राज्य आपदा मोचन बल के 40 जवान, पर्वतारोहण संस्थान मनाली का सुरक्षा दल, पुलिस के 100 जवान तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि स्थल पर तैनात हैं। मणीमहेश यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं तथा प्रशासन द्वारा उनके रहने व खाने-पीने की व्यवस्था कर दी गई है।
5. अध्यक्ष महोदय, मणिमहेश यात्रा में फंसे तीर्थ यात्रियों के लिए निकासी अभियान (Evacuation Ops) संचालित किया गया। भरमौर में फंसे कुल 15 हजार तीर्थ यात्रियों में से 10 हजार तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित उनके गन्तव्य स्थान पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के बसों द्वारा भेज दिया गया है। शेष यात्री जोकि अपनी आस्था व अन्य कारणों से रुके हुए हैं, उन्हें भी शीघ्र भेज दिया जाएगा। पिछले दिन तक 5066 यात्री 117 एच0आर0टी0सी0 बसों के माध्यम से निःशुल्क नूरपुर स्थान पर भेज दिया गया है।
6. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार प्रदेश में आई इस आपदा से निपटने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निरंतर स्थिति पर निगरानी बनाए हुए थी तथा राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में संबंधित उपायुक्तों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश लगातार प्रदान किए जा रहे हैं।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

01.9.32025/1505/DC-PB/1

मुख्य मंत्री ...जारी

7. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में उत्पन्न इस आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने हेतु मैंने दिनांक 29 अगस्त, 2025 को

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों, विभागों एवं संबंद्धित एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश लगातार दिए।

8. अध्यक्ष महोदय, इस दौरान जिला चम्बा में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री, श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय आप स्वंय भी सारे कार्यों का जायजा व्यक्तिगत तौर से देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मण्डल आयुक्त कांगड़ा एवं पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को चंबा भेजा गया।

9. अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 30 अगस्त, 2025 को हेलीकॉप्टर माध्यम से घटना की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए चम्बा का दौरा किया। पठानकोट एयरबेस से प्रभावितों को प्रदान करने के लिए राशन, दवाइयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री भी ले गया। इस दौरान मैंने कांगड़ा जिला के फतेहपुर और इन्दौरा क्षेत्र तथा चम्बा जिला के भरमौर क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया।

10. अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला चम्बा में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों पर जिला प्रशासन चम्बा के साथ बैठक की, जिसमें एन0एच0-154A (चम्बा-भरमौर) सड़क तथा अन्य सड़कों की स्थिति पर चर्चा की तथा राहत और पुनःस्थापन कार्यों को युद्ध स्तर पर शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के भी दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय विधायक श्री नीरज नैय्यर, माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार तथा पूर्व मंत्री आशा कुमारी उपस्थित रहे। इस दौरान मेरी आपसे भी फोन पर बात हुई और तब आप रास्ते में फंसे हुए थे। आप उसी दिन शाम को अपने विधान सभा क्षेत्र पहुंचे और आपने वहां पहुंच कर विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

11. अध्यक्ष महोदय, इस बैठक के उपरांत मैंने चम्बा-भरमौर एन0एच0 के कलसुई क्षेत्र का दौरा किया और वहां हुए नुकसान तथा राहत एवं पुनःस्थापन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मेरी भणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं से भी भेंट हुई तथा उनका दुःख- दर्द भी जाना ।

01.9.32025/1505/DC-PB/2

12. अध्यक्ष महोदय, चम्बा-पठानकोट सड़क अब सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया था। आज चम्बा से भरमौर की तरफ 25 किलोमीटर तक सड़क को खोल दिया गया है तथा बाकि जगह भी सड़क खोलने का कार्य प्रगति पर है। चम्बा-सलूणी-

पधरी जोत मार्ग को भी खोल दिया गया है तथा जम्मू व कश्मीर के यात्रियों को इस मार्ग से भेजा जा रहा है।

13. कांगड़ा की तरफ से भरमौर में चल रहे बचाव कार्यों कि प्रभावी निगरानी के लिए 3 सैटेलाइट फोन चम्बा भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त भरमौर में एयरटेल का 2-जी नेटवर्क भी बहाल कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस चीज से भी प्रदर्शित होती है कि हमारे राजस्व मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी जो दिनांक 28 अगस्त, 2025 को बनीखेत पहुंच गए थे और अगले दिन उन्होंने चम्बा से पठानकोट सड़क मार्ग खुलने के बावजूद चम्बा से भरामौर का रास्ता पैदल तय किया। मंत्री जी तीन दिनों से भरमौर में है। मेरी आज सुबह उनसे सैटेलाइट फोन के माध्यम से बात हुई है। उनकी संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा इस बात को इंगित करती है कि आजादी के बाद के इतिहास में कोई मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी की तरह इतने पैदल नहीं गये होंगे जितने श्री जगत सिंह नेगी जी मंत्री के रूप में पैदल गए हैं। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जिनके दिल में दर्द होता है और जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है वे किसी-न-किसी रूप में कहीं-न-कहीं पहुंच ही जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आज सैटेलाइट फोन के माध्यम से मालूम हुआ कि कुगती में चार श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है लेकिन भारी बारिश के कारण उन्हें वहां से लाने का कार्य रुका हुआ है। मुझे माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी का भी मेसेज आया था कि भरमौर में भारी बारिश हो रही है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार के राजस्व मंत्री जी वहां मौजूद हैं और पूरे कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। भरमौर से दुगती तक 20 किलोमीटर का रास्ता खुल चुका है और श्रद्धालुओं को केवल 15-20 किलोमीटर ही चलकर आगे आना पड़ता है। मेरी उप-मुख्य मंत्री जी (परिवहन मंत्री) से भी बात हुई है कि उसके बाद उनके लिए बसें उपलब्ध करवा दी गई हैं। इसके साथ सरकार की तरफ से भरमौर से कुगती तक टैक्सियों का अरेंजमैंट किया गया है। खाने-पीने के लिए लंगर में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थीं उसके लिए प्रशासन के अधिकारी, उपायुक्त इत्यादि कार्य कर रहे हैं और जहां लंगर के लिए सामान नहीं है उसे भी उपलब्ध करवा रहे हैं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी ....

01.09.2025/1510/HK/AP/-01

मुख्य मंत्री जारी .....

प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता इस तरीके से दर्शाती है।

अध्यक्ष महोदय जिला कुल्लू-मंडी से राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कमांद-कटौला मार्ग पर छोटे वाहनों को चलाया जा रहा है। कुल्लू की तरफ से फंसे सब्जी एवं अन्य सामग्री के वाहनों को लगातार निकाला जा रहा है। बिजली की व्यवस्था अधिकांश स्थानों पर बहाल कर दी गई है और सुचारू रूप से चल रही है। मनाली की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग बहाली का कार्य भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी ने क्षेत्र का दौरा किया है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर सड़क बहाली के कार्य में जुटे हुए हैं। पुरे कूल्लू क्षेत्र में दूर संचार व्यवस्था (बंजार के अतिरिक्त) सुचारू रूप से बहाल कर दी गई है। पुराना मनाली पुल जो कि त्रासदी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था उसे छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जिला लाहौल एवं स्पिति में मोबाईल नेटवर्क बहाल होना शुरू हो गया है। थिरोट पावर हाउस में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है तथा बिजली व्यवस्था में सुधार हो रहा है। कल भारतीय वायु सेना ने दो हेलीकॉप्टर के माध्यम से केलांग में राशन पहुंचाया है तथा पांच मरीजों को, जिसमें एक गर्भवती महिला व एक बच्चा शामिल हैं, को प्रशासन द्वारा हैलीकाप्टर से सुरक्षित क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया है। सीमा सड़क संगठन के अधिकारी लाहौल एवं स्पिति में सड़क बहाली के कार्य में लगे हैं। मुख्य अभियन्ता सीमा सड़क संगठन शिमला मौके के लिए निकल गए हैं। लाहौल-से-रोहतांग होते हुए रास्ता मनाली के लिए खोल दिया गया है। पक्का हुआ भोजन, लंगर, सूखा राशन, कंबल, रजाई, स्लीपिंग बैग वितरित किए गए है। प्रभावित लोगों को होटल, होमस्टे, महिला मंडलों व विश्राम गृहों में

01.09.2025/1510/HK/AP/-02

ठहराया गया है। दूरसंचार सेवा (जियो व एयरटेल) 27 अगस्त को बहाल और बिजली 28 अगस्त को बहाल कर दी गई है। लाहौल उप-मण्डल के गोम्पाथांग नाला में भूमि धंसने का मामला सामने आया है, जहां पर सीमा सड़क संगठन निरन्तर कार्य कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में इस आपदा से हुई त्रासदी के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिलों, राज्य व केंद्र सरकार के विभागों को राहत एवं बचाव कार्यों, आधारभूत ढांचों के पुनर्निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर बहाल करने के निर्देश भी जारी किये गए हैं।

मैं माननीय सदन के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री शांता कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे भी एक पत्र लिखा और देश के प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। उस पत्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दिनांक 27 अगस्त, 2025 को आपका पत्र प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। इसके लिए मैंने उनका बहुत-बहुत धन्यवाद किया था। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे भयंकर आपदा में तड़फ रहा है और झटपटा रहा है। आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाचार पत्रों में इस आपदा के समाचार पढ़ते हुए दिल दहल जाता है, रूह भी कांपने लगती है और आंखों के आगे अन्धेरा छा जाता है।

मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी राजनैतिक दल तथा कुछ दानी लोग राहत कार्यों में सहायता कर रहे हैं। परन्तु यह सब सहायता "ऊँट के मुंह में जीरे" के बराबर भी नहीं है। इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दो लाख करोड़ रुपये को राष्ट्रीय आपदाओं में खर्च करने का सुझाव दिया, जो कई वर्षों से लावारिसों का धन सरकार के पास पड़ा है। मैंने इस सम्बंध में केन्द्र के कुछ प्रमुख मन्त्रियों और हिमाचल प्रदेश के सांसदों को भी पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री महोदय जी से मिलकर यह निर्णय करवाने का प्रयत्न करें।

01.09.2025/1510/HK/AP/-03

इस पत्र द्वारा में आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप इस सम्बंध में हिमाचल प्रदेश विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित करवा कर केन्द्र सरकार को भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि विधान सभा के सर्वसम्मति प्रस्ताव के बाद भारत सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी और हिमाचल प्रदेश की इस अत्यन्त कठिन समय में सहायता होगी। यह जो पत्र हमें माननीय शांता कुमार जी ने लिखा है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपये आपदा राहत पैकेज के लिए हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए, सड़क संरचना के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाए। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 20 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का अनुमोदन करने के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : संकल्प को नियम-102 के अंतर्गत पास किया जा चुका है, जो उनकी मंशा है।

मुख्य मंत्री : लेकिन 20 हजार करोड़ रुपये के लिए नहीं बोला होगा। वह भी उसमें ऐड किया जाए।

अध्यक्ष : उसमें राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2025/1515/AT/HK/01

मुख्य मंत्री जारी ..

ठीक है, यह काम केंद्र सरकार करेगी। परंतु श्री शांत कुमार जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि 20,000 करोड़ ऐड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में आज से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 की धारा 24 के अंतर्गत पूरे प्रदेश को आपदा-ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी उपयुक्तों को धारा-34 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आज से पूरा प्रदेश आपदा-ग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है और जब तक यह आपदा का समय चलेगा तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। जैसे ही बरसात के बाद मौसम साफ होगा, उसी समय इस नोटिफिकेशन को आगे withdraw करने पर निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भी यहां बैठकर नेशनल हाईवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आपदा से संबंधित मीटिंग की थी। उसका सकारात्मक असर हुआ और चंबा से पठानकोट रोड तुरंत खुलवाया गया। अधिकारियों ने मुझे बताया कि स्पीकर साहब का फोन आने पर तुरंत कार्रवाई हुई और इस रोड को खोलकर हम भरमौर के श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने में सफल हुए। धन्यवाद।

01.09.2025/1515/AT/HK/02

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में जो स्टेटमेंट दी है उसमें कहा कि आपदा के कारण पूरा प्रदेश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और बड़े स्तर पर जान-माल की क्षति हुई है। यह बात सब जानते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष रूप से कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि यह तथ्य पूरी तरह सही नहीं है।हमें जो समाचार के माध्यमों से जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं जैसे लैंडस्लाइड, बारिश, हार्ट अटैक अदि। लेकिन आपका यह कहना कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं इस पर मैं और प्रदेश की जनता आपके माध्यम से स्पष्ट जानकारी चाहते हैं कि सही मायने में क्या सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं या कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है? यदि मृत्यु हुई है, तो कितने लोगों की हुई है? दूसरा मुद्दा यह है कि इसी माननीय सदन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आपकी अनुपस्थिति में स्टेटमेंट दी थी। You are not present on that day. उस समय आप दरभंगा की यात्रा पर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में थे

जबकि प्रदेश संकट में था। उस समय हमने कहा था कि हमारी जानकारी के अनुसार 10,000 से भी ज्यादा लोग मणिमहेश में फंसे हुए हैं लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 3,000 लोगों का जिक्र किया। आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 15,000 से ज्यादा यात्री गए थे और लगभग 10,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। आपने यह स्वयं स्वीकार किया है। इससे स्थिति बहुत confusing हो रही है क्योंकि आंकड़ों में स्पष्टता नहीं है। कभी 3,200 या 3,300, कभी 15,000, कभी 10,000 कहा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस समय भी हमने कहा था कि कम्युनिकेशन की दिक्कत के कारण सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब सदन चल रहा हो, तो अधिकारियों का पहला दायित्व होता है कि माननीय सदन को सही जानकारी दें। चाहे कैबिनेट का फैसला हो या सरकार का कोई निर्णय,उसका पहला अधिकार इस सदन का बनता है। आज जब स्टेटमेंट दी जा रही है तो उससे और अधिक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि सही मायनों में स्थिति क्या है कि 3,200-3,300, लोग थे,15,000, लोग थे या 10,000 लोग थे। अध्यक्ष महोदय, अभी तक जानकारी यह है कि चंबा पूरी तरह से बाकी दुनिया के शेष भागों से कटा हुआ है। आपके मंत्री वहां गए, यह अच्छी बात है जाना चाहिए

एम0डी0द्वारा जारी....

01-09-2025/1520/YK/MD/1

श्री जय राम ठाकुर---जारी :

लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक मंत्री वहां पर बैठे हैं। आपने वहां पर कुछ का जिक्र किया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी वहां पर गए हैं। माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज जी, डी0एस0 ठाकुर जी वहीं पर है। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर गया था और मेरे साथ रेवेन्यू मिनिस्ट, पी0डब्लयू0डी0 मिनिस्टर उसके बाद कुछ विधायकों का जिक्र इन्होंने किया। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में यह त्रासदी सबसे पहले हमने झेली है और हमारे यहां पर भी लोग मरे हैं। आज पूरा प्रदेश उस आपदा से ग्रसित है। हम इस बात को कह रहे हैं कि आपदा किसी के हाथ में नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार दोषी है, और हमने किसी को पनौती भी नहीं कहा। जिस मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं कि वह पैदल चले। मुझे मालूम है कि वह कितना चले, वह कुछ जगह चले और कुछ

जगह गाड़ी में गए। इस तरह से वह वहां पर पहुंचे। जहां वह पहुंचे हैं, उससे ज्यादा वहां पर हमारे विधायक जाकर चल रहे हैं। जो श्रद्धालु वहां से वापस आए हैं, वहां पर सरकार की व्यवस्था का आलम आप उनसे सुनिए, आप क्लेम मत कीजिए कि बहुत कुछ किया है। हम ईमानदारी से प्रत्यन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वहां सारी चीजें जो जिस प्रकार से हुई है उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बोल सकते थे। परंतु आप बोल रहे है हमने यह कर दिया, वह कर दिया ऐसा मत कीजिए। आप तो पठानकोट से चंबा जहाज में गए। वहां उतरे और आप जो सब्जी लेकर गए थे वह भी आपने चौगान में उतारी है। लेकिन मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए चिंता का विषय बना है कि अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 500 से ज्यादा लोग भरमौर में फंसे हैं। फंसे हुए लोगों का कहना है कि जब तक रास्ता नहीं खुलता हम पैदल नहीं चल सकते। ये वो लोग हैं जो पैदल नहीं चल सकते, तो गाड़ी को प्राथमिकता के आधार पर वहां पर पहुंचाने के लिए आप जो प्रत्यन कर रहे हैं उस पर प्रयास कीजिए। उसके बाद राशन, बिजली सप्लाई, वाटर सप्लाई यह बहुत बड़े इश्यूज हैं। जिनके ऊपर आपको फोकस होकर काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय,

01-09-2025/1520/YK/MD/2

इस बारिश के कारण पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 32 लोगों की जिंदगियां गई हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में 30 जून की रात को 42 लोगों की जिंदगियां गई है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप गंभीरता से प्रत्यन कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बच्चों के 7 तारीख को एग्जाम्स है वे लगातार डिस्ट्रेस्ड कॉल्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐ0सी0एफ0, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है और काउंसलिंग भी है। अपने जो उसमें टाइम शेड्यूल जारी किया है आप इसको टेकअप करें और उन बच्चों के बारे में थोड़ा सा विचार करें। रास्ते अवरूद्ध और टूटे पड़े हैं। उनके जीवन को कोई संकट ना हो उस पर भी विचार करें कि उस एग्जाम को क्या हम स्थगित कर सकते हैं या कोई अगली तारीख तय कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ कर्मचारी ऐसे भी है जिनकी प्रमोशंस हुई है और उनको जॉइनिंग करनी है। जॉइनिंग का पीरियड एग्जास्ट होता जा रहा है, रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसी चीजों पर भी विचार करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है जो चंबा में सड़कों की, पेयजल योजना, वाटर सप्लाई

की जो क्षति हुई इसके साथ-साथ जो कम्युनिकेशन, बिजली की सप्लाई तहस-नहस हुई है। जिसके कारण वहां पर आम जनजीवन अस्त-व्यस्त पड़ा है। उस पर आप फोकस करें प्रत्यन करें, मेहनत करें मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्रीमती के0एस0 जारी -----

01.09.2025/1525/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री जी पर बहुत दबाव है। ये एक बात को दो-दो, तीन-तीन बार रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है कि यह दबाव राजनीतिक हो। ...(व्यवधान) मैंने पूरे प्रदेश के मामले में स्टेटमैंट दी है और इनका क्षेत्र भी उसमें शामिल है। आपने अपने क्षेत्र में डैथ्स के बारे में बात की तो उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हम सभी लोग भी सम्मिलित हैं और जय राम जी, आपके क्षेत्र के लिए तो हमने सबसे पहले आपदा राहत पैकेज दिया। आप मणिमहेश से कहां पहुंच गए? मेरी बात ध्यान से सुन लेना। लगता है कि रात को आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी। आपको आराम से सोना चाहिए। मैं आपको मणिमहेश के बारे में पूरी जानकारी दे दूं। आप डैथ की बात कर रहे हैं। उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 3297 मणिमहेश के यात्रियों को हमने मणिमहेश से भरमौर सुरक्षित पहुंचाया। असली बात यह है और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेटमैंट को ध्यान से सुनें। कुगती में 4 डैड बॉडीज़ पड़ी हैं और इसी विधान सभा के अंदर मैंने इस बारे में कहा। टोटल डैथ्स के बारे में जो आपने पूछा, मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक वहां 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है । कल मैं चम्बा में था। मैं हेलीकॉप्टर से गया या कैसे गया, ये सारी बातें मायने नहीं रखतीं। मैं लोगों का दुख बांटने के लिए गया था और 28 अगस्त से श्री जगत सिंह नेगी जी, हमारे रेवन्यू मिनिस्टर वहां हैं। क्या आपकी सरकार के समय कोई कैबिनेट मिनिस्टर चार दिन भरमौर बैठा है? आज भी वे वहां पर हैं और कल भी होंगे। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए, जिस दिन वहां बारिश कम हो जाएगी, जो आपने 400-500 श्रद्धालुओं की बात की, उनको मुफ्त हेलीकॉप्टर से चम्बा छोड़ेंगे और बस के माध्यम से घर छोड़ेंगे और ये दिशा-निर्देश हमने दे दिए हैं। हमने जगत सिंह नेगी जी को

कहा है कि वहां की परिस्थिति के हिसाब से इन श्रद्धालुओं के लिए जो आप फैसला करना चाहेंगे, करें। श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, भरमौर, पांगी, चम्बा, डलहौजी, चुराह और चुवाड़ी आदि क्षेत्रों में लोगों का जो नुकसान हुआ है, उस बारे में जो आप फैसला करना चाहें, करें। लोगों का ख्याल रखने के लिए कोई मंत्री पैदल

01.09.2025/1525/केएस/वाईके/2

नहीं जाता, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं लेकिन हमारी सरकार में संवेदनशीलता पहले भी थी और अब भी है। ...(व्यवधान) जय राम जी, आपका उनके साथ व्यक्तिगत विरोध हो सकता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पूर्व मुख्य मंत्री हैं। आपको थोड़ी तो प्रशंसा करनी चाहिए। यह कहना कि थोड़ा पैदल चले, कम चले, अगर मैं यही बात आपके लिए कहूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको थोड़ी सी प्रशंसा तो करनी चाहिए। ठीक है कि जगत सिंह नेगी जी से आपका व्यक्तिगत विरोध है क्योंकि वे सच बोलते हैं तो थोड़ा दर्द होता है। ...(व्यवधान) मैं अभी हंस नहीं रहा हूं । जय राम जी, आप बैठिए ...(व्यवधान) वह शब्द निकाला है, आपके सामने निकाला है और सारे शब्द अध्यक्ष महोदय ही निकालते हैं। हमको बोलने ही नहीं दिया...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे द्वारा किया गया, जो लोग भरमौर से निकाले गए, उनके बारे में मैंने अपनी स्टेटमैंट में कहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग पैदल नहीं चल सकते, जैसे उनमें काफी बुजुर्ग भी हैं तो उनको हम हेलीकॉप्टर की सुविधा देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं डैथ्स के बारे में कहना चाहता हूं। जय राम जी, आप गम्भीरता से मेरी बात सुनिए। मुझे पंजाब से एक विधायक का फोन आया कि 26 साल की उम्र में वहां के एक श्रद्धालु का ऑक्सीजन लैवल कम हो गया और उसकी डैथ हो गई। वे तीन साथी थे और तीनों की ही डैथ हो गई। उनकी डैड बॉडीज़ ढूंढने के लिए उनके माता-पिता हमसे अनुरोध कर रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

01.09.2025/1530/AV/AG/1

मुख्य मंत्री------ जारी

हम उसको भी ढूंढ रहे हैं और उसके लिए पुलिस वाले भेज दिए गए हैं। मेरी आज ही माननीय राजस्व मंत्री तथा डी0सी0 साहब से बात हुई है। जिलाधीश महोदय ने कहा कि उन डैड बोडीज को लेने के लिए हमने 20 पोर्टर्ज का इंतजाम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर पिछली रात से बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। शिमला में भी यही हाल है और यहां पर भी देहान्त हुए हैं। अब इस बारिश से तो कोई नहीं लड़ सकता, भगवान और प्रकृति के आगे तो हम सब लोग मजबूर है। **मैं इस सदन के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही बारिश खत्म होगी, हम भरमौर में फंसे एक-एक श्रद्धालु को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद प्रदेश के चम्बा, मण्डी इत्यादि जिन-जिन जिलों में डिजास्टर हुआ है, हम कुछ कट लगाएंगे और आर्थिक तंगी के बावजूद भी उन परिवारों को बसाएंगे**। हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और माननीय श्री शांता कुमार की चिट्ठी पर शायद हमें कुछ मिल जाए तो अच्छी बात होगी। कुछ कट लगाने तथा केंद्र से राशि मिलने के बाद हमारा सबसे पहला दायित्व सड़कों को जोड़ने और उजड़े हुए घरों को बसाने का होगा। हमें इसमें सभी विधायकों का योगदान भी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक तंगी के बावजूद हम उन सारे परिवारों को बसाएंगे।

01.09.2025/1530/AV/AG/2

अध्यक्ष : अब प्रश्न काल और जीरो आवर; दोनों समाप्त हो गए हैं।

अब अगर सदन की अनुमति हो तो जो 8 महत्वपूर्ण इश्यूज आए हैं, मैं इन सबको दो-दो मिनट्स के लिए अलाउ करता हूं और इन इश्यूज को 10-15 मिनट्स में समाप्त कर लेते हैं?

विधायकगण : अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा, आपका सातवें नम्बर पर लिस्टिड है। इसलिए सबसे पहले श्री लोकेन्दर कुमार जी अपना इश्यू उठाएंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपदा से संबंधित विषय पर ही बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 28 अगस्त, 2025 को भूस्खलन के कारण दो महिलाओं की मृत्यु हो गई जिसमें एक का शव मिल गया है तथा दूसरी का अभी तक नहीं मिला है। मैं उन परिवारों के लिए अपनी सांत्वनाएं भी व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आपदा हो रही हैं उसके चलते हमारे आनी विधान सभा क्षेत्र में बुछैर, दयोठी, कमान्द, नोर, राहणू इत्यादि पंचायतों में 10-15 गांव पूरी तरह से बैठ गए हैं। उनमें से दो-तीन गांव ऐसे हैं जहां पर प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे हैं। मैं दो-तीन जगह खुद भी जाकर आया हूं और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर राशन सामग्री बांटी गई है। मैं इस सदन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मेरा आनी विधान सभा क्षेत्र जिला कुल्लू के तहत आता है। वैसे तो आपदा पूरे प्रदेश में आई है और जैसे इसकी वजह से हमारे सिराज़, भरमौर, मनाली इत्यादि क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, वैसे ही मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में भी हुआ है। लेकिन मीडिया में वहां की कवरेज नहीं हो रही है और मीडिया के माध्यम से वहां का विषय नहीं उठाया गया है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि वहां पर हुए नुकसान का जायजा लिया जाए और वहां के लोगों को भी राशन सामग्री, घर व जमीन मिले। धन्यवाद।

01.09.2025/1530/AV/AG/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र की जो बात उठाई है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि **पूरे प्रदेश में जहां-जहां पर भी नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारी सरकार हर सम्भव प्रयत्न करने के लिए**

तत्पर है। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में जो-जो भी नुकसान हुआ है, उसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन करने के उपरांत वहां सभी प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

01.09.2025/1530/AV/AG/4

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा, अब आप अपना इश्यू उठाइए।

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

हमारे पंचायत भतेर रत्तल, गांव रत्तल का एक लड़का जिसकी आयु लगभग 27 वर्ष है, वह चण्डीगढ़ में टैक्सी चलाता है। उस व्यक्ति का नाम श्री अनिल कुमार ऊर्फ हैप्पी, पुत्र श्री रमेश कुमार दिनांक 29 अगस्त, 2025 की रात को लगभग 09.50 बजे जिसकी टैक्सी ओला कम्पनी में अटैच है। उसकी टैक्सी ऑनलाइन हायर होती है लेकिन

टी सी द्वारा जारी

01.09.2025/1535/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री प्रकाश राणा ... जारी

उस दिन से लेकर आज एक सितम्बर, 2025 यानी 4 दिन हो गए हैं फिर भी उस टैक्सी चालक का कोई पता नहीं चल पाया है। मैंने भी नया गांव मोहाली (खरड़) में कल 3-4 बार एस0एच0ओ0 साहब से भी बात की। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि अभी तक इस मामले की एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं हुई थी और वह कल हुई है। हिमाचल प्रदेश के टैक्सी चालकों के साथ इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आजकल जब ऑनलाइन बुकिंग होती है तो कम-से-कम उस व्यक्ति को तो पकड़ा ही जाना चाहिए था जिसने टैक्सी बुक की थी। कॉल डिटेल के अनुसार रात 10:15 बजे उसकी धर्मपत्नी ने उसे फोन किया था। उस समय उसने कहा था कि वह रेलवे स्टेशन सवारी छोड़ने जा रहा हूं और

उसके बाद घर आ जाऊंगा लेकिन उसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया और जब फिर 1.30 बज़े फोन किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला तथा आज तक उसका कोई पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कम-से-कम इस बारे में पंजाब सरकार से बात करें। यह बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। डी0जी0पी0 साहब अपने स्तर पर बात करें ताकि इसका सही पता चल सके कि वह कहां है क्योंकि अभी तक न गाड़ी का पता है और न ही चालक का पता लग पाया है।

01.09.2025/1535/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रकाश राणा जी ने जो विषय उठाया है वह जोगिंदरनगर विधान सभा क्षेत्र का है। एक टैक्सी चालक अनिल कुमार ऊर्फ हैप्पी, निवासी पंचायत बागान रोल जोगिंदरनगर, मंडी, जो ओला-उबर वाहन संख्या पी0बी01डी6299 चंडीगढ़ में चलाता है, दिनांक 28.08.2025 से लापता है। अनिल कुमार के परिवार ने अभी तक मंडी पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी थी लेकिन माननीय विधायक ने मुझे इसकी जानकारी दी है और अनिल कुमार का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इस संबंध में डी0जी0पी0 हिमाचल ने डी0जी0पी0, पंजाब और डी0जी0पी0 चंडीगढ़ से फोन पर संपर्क स्थापित कर चालक की खोजबीन के लिए हर संभव सहयोग मांगा है। डी0जी0पी0 स्तर पर बातचीत चल रही है और जैसे ही कोई परिणाम आता है तो उससे माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जाएगा।

01.09.2025/1535/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

करुणामूल आधार पर नियुक्तियों में 62,500 आय-सीमा बारे ।

श्री आर0एस0 बाली : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए वर्तमान सरकार ने जो आय-सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तय की है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 62,500 रुपये की पुरानी शर्त को खत्म करके 3 लाख रुपये की आय-सीमा

लागू कर दी है या अभी भी 62,500 रुपये की आय-सीमा लागू है। प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा अंतिम 8 महीने में लिए गए सारे निर्णय रद्द कर दिए हैं लेकिन क्या दिनांक 28.08.2022 की नोटिफिकेशन भी रद्द कर दी गई है जिसके तहत करुणामूलक को बाहर किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या अब 3 लाख रुपये की आय-सीमा के अंदर आने वाले करुणमूलक अभ्यर्थियों को नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी या नहीं? कृपया सरकार स्थिति स्पष्ट करे और यह भी बताए कि तीन लाख रुपये आय-सीमा की नोटिफिकेशन कब जारी की जाएगी? मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि यदि मुख्य मंत्री महोदय ने 3 लाख रुपये की लिमिट तय कर दी है तो ऐसे केस कब से कंसीडर होंगे और यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?

01.09.2025/1535/टी0सी0वी0/ए0जी0-4

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आर0एस0 बाली जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इन्होंने जानना चाहा है कि 3 लाख रुपये की आय-सीमा तो बढ़ा दी गई है लेकिन यह आय-सीमा प्रति व्यक्ति 62,500 रुपये हैं और ये चाहते हैं कि परिवार की कुल आय तीन लाख रुपये कर दी जाए। यह कंसीडर न किया जाए कि यदि किसी परिवार में 3 व्यक्ति है तो उसकी आय 1.80 लाख रुपये होगी। **अध्यक्ष महोदय, इस पूरे विषय की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् माननीय सदस्य ने जो यह विषय उठाया है इस पर गौर किया जाएगा।**

श्रीमती एन0एस0 द्वारा.... जारी

01-09-2025/1540/NS-AS/1

शून्य काल -----जारी

अध्यक्ष : अब श्री सुधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुधीर शर्मा : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : अब श्री भवानी सिंह पठानिया जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से बारिश हुई है और इस बारिश के चलते जो फ्लड आए हैं तो इस फ्लड से फतेहपुर, इन्दौरा और पंजाब के 5 अन्य जिले ब्यास नदी से प्रभावित हुए हैं। मैं जिस इश्यू को शेयर करने जा रहा हूं तो यह ऐसा इश्यू है अगर इसको हमने टाइम पर एड्रैस नहीं किया तो हम सबकी लाशें पाकिस्तान के अंदर जाकर मिलेंगी। कुछ अवैध क्रशर्ज एक ऐसे एरिया में चल रहे हैं जहां पर ये कानून के हिसाब से परमिटिड नहीं हैं बल्कि उनमें से एक क्रशर तो टोटली इलीगल है जिसका न लाइसेंस है और न ही बिजली का कनैक्शन है और यह लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। समस्या यह है कि यह क्रशर हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। रूल यह कहता है कि जो हमारा शाह नहर का बैराज है और यह बहुत बड़ा वाटर स्टोरेज है तथा यहां से पानी रूपगढ़, गंगा नगर आदि को कैनाल के थ्रू जाता है तथा इसके 3 किलोमीटर के डाउन स्ट्रीम पर क्रशर का कोई लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन यह क्रशर ऐसा है जिसकी 4 या 5 आर्म्स हैं और यह शाह नहर के बैराज पर सिर्फ 750 मीटर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि टोटली इलीगल है। इसकी पंजाब सरकार से कोई परमिशन नहीं है और न ही किसी और सरकार से परमिशन है। इसका बिजली से कनैक्शन भी नहीं है और यह केवल जेनरेटर से चलता है। मेरा निवेदन है कि अगर यह क्रशर वहां से नहीं हटा तो आज या कल शाह नहर का बैराज डेमेज होगा और अगर शाह नहर बैराज डेमेज होगा तो पूरे-का-पूरा फतेहपुर, इन्दौरा, जिला होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन पट्टी तक इसकी मार जाएगी तथा अमृतसर जिले के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने इस क्रशर की पूरी फाइल (हाथ में फाइल दिखाते हुए) तैयार की है और मैं इसे सदन के पटल पर रख भी देता हूं।

01-09-2025/1540/NS-AS/2

(माननीय सदस्य ने संबंधित कागजात सदन के पटल पर रखे।)

यह सिचुएटिड है 31° 57′ 45″ North or 75° 53′ 40″ East Longitude or Latitude पर स्थित है। इस गांव का नाम चंगड़वां है, इसकी

तहसील तलवाड़ा और जिला होशियारपुर है। यह एक इश्यू है जो टोटली इलीगल क्रशर है। इसके अलावा एक जगह चक मीरपुर पड़ती है जो 2 से अढ़ाई किलोमीटर ऊपर है। वहां पर इस समय पंजाब के अंदर 7 क्रशर चल रहे हैं और समस्या यह है कि पंजाब की माइनिंग पॉलिसी के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि आपके पास माइनिंग लीज हो। पंजाब सरकार एक क्रशर को लाइसेंस दे देती है और उसके बाद कहा जाता है कि आपने जहां से उखाड़ना है आप उखाड़िए। पंजाब के 7 क्रशर्ज हैं और ये रेहपतन, बेली, रियाली, मंड भागपुर के अंदर अवैध क्रशिंग करते हैं। इन्होंने लोकल लोगों के साथ टाई अप किया हुआ है और उनकी जमीनों को उखाड़ रहे हैं। वहां पर 8,10 व 15 फुट की जमीनें उखड़ गई हैं। ये माल फिर पंजाब जाता है और पंजाब के अंदर इसकी क्रशिंग करके पंजाब में ही बेचा जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश को कोई फायदा नहीं है और न ही किसी और को फायदा है क्योंकि यह टोटली अवैध गतिविधियां चल रही हैं लेकिन इससे फ्लडिंग का खतरा है। हमारी सॉयल लूज हो रही है चाहे सरकारी जमीनों की हो या प्राइवेट जमीनों की हो। इसमें ये समस्या पैदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ये क्रॉस बॉर्डर एक इश्यू है। पंजाब में एक कट्टर व ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और मैं चाहता हूं कि श्री भगवंत मान जी के साथ मुख्य मंत्री जी का कार्यालय या तो मुख्य सचिव के स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर बातचीत करे। अगर यह नहीं हो सकता तो सरकार के एडवोकेट जनरल पंजाब एंड हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करें तथा इसको बंद करवाएं। माइनिंग पॉलिसी फॉल्टी है और उसके साथ अवैध क्रशर 750 मीटर शाह नहर बैराज के ऊपर चल रहा है उसको शीघ्र बंद करवाएं। मैं चाहूंगा कि इसके अंदर डी0सी0 व एस0पी0, होशियारपुर को भी पार्टी बनाया जाए। मैं इस फाइल को इस माननीय सदन के सभा पटल पर रखता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

01-09-2025/1540/NS-AS/3

अध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय भवानी पठानिया जी ने अवैध क्रशर्ज के बारे में जिक्र किया है। जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं विशेष कर पठानकोट के पास चक्की बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर पंजाब के लोगों के अवैध क्रशर्ज चल रहे हैं और समय-समय पर हिमाचल प्रदेश के एरियाज में आकर रात के समय पत्थर निकालते हैं। जब हिमाचल प्रदेश की पुलिस या माइनिंग डिपार्टमैंट आता है तो वे पंजाब की तरफ भाग जाते हैं। यह सीमा डिसप्यूटिड है। कई बार नूरपुर पुलिस ने वहां पर अवैध खनन करने वाले लोगों को पकड़ा है। मगर लेटर स्टेजिज में क्लेम करने के बाद यह पता लगा कि

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.09.2025/1545/RKS/AS-1

उद्योग मंत्री... जारी

वह बॉउंड्री डिस्प्यूटिड है, वह डिमार्केटिड बॉउंड्री नहीं है। मैंने इसके लिए उपायुक्त कांगड़ा को निर्देश दिए हैं और एक वक्त वहां डिमार्केशन का प्रोसैस भी स्टार्ट हुआ था लेकिन अब वह कार्य रुक गया है। वहां कई अवैध क्रशर्ज हैं। आपने ठीक कहा कि वे हिमाचल वाले पोर्शन से दो नंबर में पत्थर निकाल कर ले जाते हैं। इस काम में कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं। हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा आपने जिक्र किया अगर जरूरत पड़ी तो हम पंजाब गवर्नमेंट से भी टेक-अप करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट पीटिशन फाइल कर इसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश में सभी पैरामीटर्स का पालन करते हैं लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड राज्य में मैंने खुद देखा है कि वे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं मानते। हिमाचल

प्रदेश में कानून का पालन होता है। माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया है, हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी क्या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं?

व्यवस्था का प्रश्न

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब श्री जय राम ठाकुर जी आपदा पर चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने मुख्य मंत्री जी के लिए कहा कि 'आप हंस रहे हो'। मैं चाहूंगा कि आप इन शब्दों को आज की कार्यवाही से बाहर निकाल दें।

01.09.2025/1545/RKS/AS-2

Speaker: That was in a lighter way, that is not a part of record. It was in a lighter way. अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपना विषय रखेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान श्री नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या खड़ी हुई है। हमें यह बात समझ आती है कि आपदा में कई पंचायतों में भारी बारिश होने के कारण काफी लैंडस्लाइड्स हुए हैं जिसके कारण बिजली गुल होना स्वाभाविक है। लेकिन जब बारिश नहीं थी, गर्मियों में भी वहां बिजली बार-बार जाती है।

हमारे विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में बिजली की समस्या बनी रहती है जिसके कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को बहुत दिक्कत आती है। कई मरीज आजकल घरों में ऑक्सीलेटर लगाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं लेकिन बिजली चले जाने से वे ऑक्सीलेटर बंद हो जाते हैं जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह घरों में बहुत से उपकरण बिजली न होने के कारण चल नहीं पाते जिसके कारण भयंकर समस्या खड़ी होती है। जब बिजली नहीं होती तो पेयजल स्कीमों की मोटरें भी नहीं चलती जिससे पीने-के-पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। इन समस्याओं का मुख्य कारण यह है कि बिजली विभाग में फील्ड स्टाफ की बहुत कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टी-मेट,

ए0एल0एम0 और लाइनमैन के पदों पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। ये सारे पद खाली पड़े हैं। वैसे तो बाकी विभागों में भी फील्ड स्टाफ की काफी कमी है। जल शक्ति विभाग में भी फील्ड स्टाफ की कमी है लेकिन वहां पर कुछ कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर रखे हैं और कुछ स्कीमें ठेकेदारों को दी गई हैं। बिजली विभाग में न तो कोई कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर रखे हैं और न ही रेगुलर बेसिज पर। जब बिजली चली जाती है तो हमें रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करना पड़ता है कि आप जाकर देखें कि वहां क्या समस्या आ रही है। हमें यह दिक्कत स्टाफ की कमी के कारण आ रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए रिक्त पदों को भरा जाए लेकिन आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब आपने स्थाई तौर पर भर्ती करना बंद कर दी है। लेकिन मेरा आगह है कि जो आप 'पशु मित्र' भर रहे हैं उसी तर्ज पर बिजली मित्र भी भर दीजिए। हमारे विधान सभा

01.09.2025/1545/RKS/AS-3

क्षेत्र से बहुत से कर्मचारी हैं जो दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में टी-मेट या ए0एल0एम0 का कार्य कर रहे हैं। वे अपने घरों के नजदीक काम करना चाहते हैं और इससे वहां स्टाफ की कमी भी दूर होगी लेकिन बिजली विभाग उनकी ट्रांसफर अलाउ नहीं करता। कहीं कैडर की समस्या है और कहीं आप यह काम नहीं होने देते। मेरा आग्रह है कि भले ही आप हमारे नोट पर उनकी ट्रांसफर न करें, आप उनसे लिखित रूप में ले लें कि जो कर्मचारी श्री नैनादेवीजी विधान सभा क्षेत्र में आना चाहता है उसे आप अलाउ कर दीजिए ताकि हमें जो समस्या आ रही है वह दूर हो सके। दूसरा, वहां पर लॉ-वोल्टेज की भी काफी समस्या है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2025/1550/बी.एस./डी.सी.-1

शून्य काल जारी..

श्री रणधीर शर्मा जारी...

कर्मचारी और बिजली हो तो भी वोल्टेज इतनी कम है कि लोगों के जो ऐ.सी. हैं वे नहीं चलते, कई जगह तो पंखें तक नहीं चलते। आज कल हर घर में ऐ.सी. है और वाशिंग मशीनें हैं, हर घर में किसानों के पास घास काटने की मशीनें बिजली से चलती हैं। मैंने पहले भी सुझाव दिया था की जगह-जगह कार्य करने की बजाय, स्टेप वाइज करने की बजाय सभी क्षेत्रों में, सभी गांव को थ्री फेस से जोड़ दिया जाए ताकि जो लो वोल्टेज की समस्या है उसका समाधान हो सके और इस ओर सरकार कदम उठाए। यह मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह है।

एक विषय मैंने पिछले सत्र में जीरो अवर में उठाया था। हमारे एक नकराना पंचायत से श्री लाल सिंह जी है, भाखड़ा बांध विस्थापित हैं, जल शक्ति विभाग के रिटायर्ड स्टूडेंट है। उसके गांव में वहां सड़क की समस्या है, जो कैंची मोड़ से नैना देवी सड़क है उस सड़क पर अपना घर बना लिया क्योंकि उनकी जमीन वहां पर थी। अब वहां मीटर नहीं लग रहा है। वहां का थोड़ा सा पोर्शन पंजाब बॉर्डर में आता है। मैंने पिछली बार भी आपसे आग्रह किया था और आपने आश्वासन दिया था कि वह मीटर लगा दिया जाएगा। पहले भी अनेक घरों में पंजाब के ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में हिमाचल से बिजली बोर्ड ने मीटर लगाए हैं। अब पता नहीं क्यों दो ढाई साल से श्री लाल सिंह जी और अन्य जो ऐसे कुछेक केसिज हैं, वहां पर मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। आपके आश्वासन के बाद भी मीटर नहीं लगा है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय, से आग्रह है कि इसके साथ-साथ और भी जो ऐसे बॉर्डर पर केसिज हैं वहां कोई ऐसा तो है नहीं कि वे पाकिस्तान में है, ये हिंदुस्तान की बात है, पंजाब की बात है और पंजाब का बिजली बोर्ड लिख कर दे रहा है कि हम वहां मीटर नहीं लगा सकते क्योंकि उनको बहुत दूर पड़ता है। पंजाब के बिजली बोर्ड के अधिकारियों के लिखने के बावजूद भी उनके द्वारा कहने के बावजूद भी मीटर नहीं लग रहे हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी यह भी निर्देश दें, यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

01.09.2025/1550/बी.एस./एच.के.-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिजली के मीटर की बात की थी और पिछली बार हमने हाउस में अश्वासन भी दिया था लेकिन उनका घर है पंजाब की

बाउंड्री पर बना हुआ है। हमने पंजाब सरकार से मैटर उठाया है और जैसे उनकी मीटर की परमिशन आ जाएगी तब हम उसमें मीटर लगा देंगे क्योंकि उनकी बाउंड्री में वह घर है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि बिजली मित्र नियुक्त कर दिया जाएं। मैं आपके सुझाव को मानता हूं और आपका बहुत अच्छा सुझाव है। निश्चित तौर पर जब अच्छे सुझाव आते हैं तो उसको हम स्वीकार भी करते हैं। आपने अच्छा कहा कि जहां अभी स्टाफ ही नहीं है और इतनी जगह स्टाफ नहीं है जहां लो वोल्टेज है और कई जगह तो ठीक करने में दिक्कत आ रही है। जल्द ही सरकार बिजली मित्रों की नियुक्ति करेगी। तब तक जो हो सकता है वह देख लेंगे। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, ऐसे सुझाव आप और माननीय सदस्यों से भी कहिए कि देते रहिए। बिजली मित्र इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे अभी इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमिशन में जाएंगे और इन्हें भरने में टाइम लगेगा जब तक उनके इंटरव्यू नहीं हो जाते तब तक हम बिजली मित्रों की नियुक्ति करेंगे और जरूर करेंगे।

01.09.2025/1550/बी.एस./एच.के.-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी, कृपया अपनी बात संक्षिप्त रूप में रखिए क्योंकि 2-3 मिनट का समय बाकी बचा है।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पिछली 28 तारीख को गग्गल एयरपोर्ट के पास जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें अक्षय कुमार सुपुत्र श्री चुनी लाल, निवासी भटेच ठारू, शाहपुर का रहने वाला था और इसकी उम्र 29 साल थी। दूसरा पवन कुमार सुपुत्र श्री रमेश कुमार टुंडू यह 36 साल का था। ये किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करके रात को जब अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे तो उनको एयरपोर्ट के पास मृत पाया गया और कहा गया की बेल के साथ इनकी टक्कर हुई है और दोनों की सपोर्ट में ही मृत्यु हो गई। मैं पिछले कल इनके घरों में था। नेशनल हाईवे का मामला भी इसी जीरो पॉइंट के अंदर था। जब मैंने यहां के स्थानीय एस.एच.ओ. से बात की और इन दोनों परिवारों के घर गया और वहां पर इन दोनों नौजवानों के परिवार से मिला। जब मैंने पुलिस वालों को पूछा कि क्या इस घटना की सी.सी. टी.वी. फुटेज है? उन्होंने कहा कि गग्गल से ले करके एयरपोर्ट

तक की कोई भी फुटेज उनके पास नहीं है। जब मैंने पूछा कि यह हमारा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का जो कैमरा है वह पिछले तीन दिन से खराब है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

1.09.2025/1555/डी0टी0/डी0सी0 -1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

परिवार को शंका है कि किसी के साथ यह गाड़ी टकराई है। मैं इस मामले को भी माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस दुर्घटना में जो लोग हताहत हुए हैं उनके मोबाइल भी अभी तक उनके परिवार को नहीं मिले हैं और उनकी धर्मपत्नियों की भी यही पीड़ा है। गगल का एयरपोर्ट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है जिस तरह का भूस्खलन वहां हो रहा है, अध्यक्ष जी कल आप भी उसी मार्ग से गुजरे होंगे, पिछले चार दिनों से लगभग चार-पांच बार वह मार्ग अवरूद्ध हुआ है। जहां पर फ्लाइटस लैंड करती है उस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर भी भूस्खलन हो रहा और अगर 10-15 दिन वर्षा का दौर यूंही जारी रहा तो गगल एयरपोर्ट के आस-पास काफी भूस्खलन हो सकता है। वहां पर एन0एच0ए0आई0 के द्वारा रिटेनिंग वॉल लगाई जानी है। इस सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि जिला कांगड़ा के उपायुक्त की अध्यक्षता में, जिसमें मैं भी विशेषतौर पर आमंत्रित रहूंगा, एक कमेटी उस क्षेत्र के निरीक्षण पर जाएगी । उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए वह कमेटी भी वहां गई थी लेकिन अभी तक एन0एच0ए0आई0 द्वारा वहां पर रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई गई। एन0एच0 ए0आई0 इस रिटेनिंग वॉल के संबंध में यह जवाब दे रही है कि वह इसके लिए ऑल्टरनेट साइट देख रहे हैं कि क्या एयर पोर्ट उस वॉल के ऊपर जाएगा या नीचे से जाएगा, उसके बाद वे ये रिटेनिंग वॉल लगाएंगे। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह रिटेनिंग वॉल वहां पर जल्दी लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश का यह एक मात्र ऐसा एयरपोर्ट हैं जहां पर नियमित रूप से फ्लाइटस आती हैं। जो एयरपोर्ट पर इतने अधिक रूप में भूस्खलन हो रहा है उसके लिए एन0एच0ए0आई0 को कहा जाए कि वे वहां पर शीघ्र रिटेनिंग वॉल लगाएं, अगर यह रिटेनिंग वॉल वहां पर तुरंत न लगाई गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर इसी प्रकार से वहां पर भूस्खलन होता रहा तो चार-पांच दिन वहां पर फ्लाइटस आना बंद हो जाएंगी। यह बहुत संवेदनशील विषय है क्योंकि इस

एयरपोर्ट में पिछले चार-पांच दिनों में कई बार स्लाइडिंग हो चुकी है। रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए एन0एच0ए0आई0 को आदेश भी दिए गये थे लेकिन अभी तक भी यह रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई गई है और अगर यह वॉल नहीं लगाई गई तो फिर कुछ समय बाद इसके लिए ऑलटरनेट रूट की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ सकती है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 561

1.09.2025/1555/डी0टी0/डी0सी0 -2

करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण हेतु लोगों को दिए गये हैं। अगर यह रिटेनिंग वॉल न लगाई गई तो यह एयरपोर्ट एक ओर से बंद हो जाएगा। यही बात मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी को कहना चाहता हूं कि जो सुझाव उनके द्वारा दिया गया है, उस पर गौर किया जाएगा।**

1.09.2025/1555/डी0टी0/डी0सी0 -3

अध्यक्ष : अब श्री त्रिलोक जम्वाल जी in a very short and brief manner अपना मामला इस सदन में रखें।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिलासपुर में बन रही रेलवे टन्नल के संबंध में मामला इस सदन में उठाना चाहता हूं। जो यह टन्नल वहां बन रही है उस टन्नल के ऊपर एक गांव है और उस गांव के घरों में दरारे आई चुकी हैं। उन लोगों ने इसके विरोध में हड़ताल भी की थी जिसके कारण 25 दिन तक रेलवे प्राजैक्ट का काम बंद रहा। जब वह काम बंद रहा तो वह कंपनी जो वहां काम रही थी उसने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल की और इस याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किए गए कि इस गांव को उस साइट से हटा दिया जाए और रेलवे प्रोजैक्ट का काम चलता रहे। लेकिन उस गांव के वे लोग जो आई0आर0डी0पी0 में आते हैं, कल्याण विभाग

की ओर से उनके घर बनाए गये हैं; वे अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, उन लोगों के घरों में बहुत बड़ी-बड़ी दरारे आ गई। लेकिन उन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वे लोग जो गरीब है और आज उच्च न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। वेल्फेयर से उनके घर बने है। वहां के चार घरों के संबंध में जिला प्रशासन ने एन0आई0टी0 हमीरपुर को पत्र लिखा है कि इन घरों का सर्वे किया जाए और यह कारण बताया जाए कि इन घरों में किस कारण से दरारे आई हैं? लेकिन उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उन्होंने एन0आई0टी0 के साथ आई0आई0टी0 मंडी को भी पत्र लिखा है। लेकिन उस गांव के गरीब लोग आज भी स्ट्राइक पर हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने वाला नहीं है। मैं उन चार घरों के मालिकों के नामों का उल्लेख भी करना चाहता हूं वे हैंः श्रीमती सावित्री

1.09.2025/1555/डी0टी0/डी0सी0 -3

देवी, श्री राम लाल, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री गरजा राम जी। ये वे परिवार हैं जिनके घरों में बहुत बड़ी-बड़ी दराने आई हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार यह तय कर दे कि उनके घरों में आई दरारे केवल रेलवे टन्नल की वजह से आईं हैं। अगर ऐसा प्रदेश करेगी तो तो प्रदेश सरकार पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मुआवजा आर0बी0एन0एल0 और रेलवे विभाग देगा। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ भी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही माननीय उपमुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : उपमुख्य मंत्री महोदय,

उपमुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में आज एक प्रश्न, प्रश्न संख्या 3442 के तहत इस सदन में लगा था और इसका विस्तृत उत्तर सरकार ने इस सदन में दिया है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य उस प्रश्न के संदर्भ में दिए गए उत्तर का अवलोकन कर लें उसके उपरांत इनकी कोई शिकायत होगी तो हम उसे देख लेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि पिछले काफी प्रश्न पेंडिंग पड़ें हैं और सभी माननीय विधायक उन प्रश्नों को उत्तर भी जानना चाहते हैं। यदि इस विधान सभा के वर्तमान सत्र को अगर आप तीन दिन और बढ़ा देते तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर इस माननीय सदन में दे देंगे। इसलिए आप मेरे अनुरोध पर जरूर गौर फरमांए।

Speaker : We will take proper decision at a relevant time after discussing this issue with the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister and the Leader of the Oppostion.

Now we take Item No.-2

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

01.09.2025/1600/एच.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष........जारी

अब आईटम नम्बर-2 होगी। अब माननीय मुख्य मंत्री सदन को इस सप्ताह की साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की साप्ताहिक कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जोकि इस प्रकार है :-

सोमवार, 01 सितम्बर , 2025 : शासकीय/विधायी कार्य।
भाद्रपद, 10

मंगलवार, 02 सितम्बर, 2025 : शासकीय/विधायी कार्य।
भाद्रपद, 11

01.09.2025/1600/एच.के.-एन.जी./2

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब श्री विनय कुमार (माननीय उपाध्यक्ष), सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति, (वर्ष 2025-26), अधीनस्थ विधायन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधायन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का पंचम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की अधीनस्थ विधायन समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित किए वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है।

01.09.2025/1600/एच.के.-एन.जी./3

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना की जाएगी।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगे।

01.09.2025/1600/एच.के.-एन.जी./4

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

01.09.2025/1600/एच.के.-एन.जी./5

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

01.09.2025/1600/एच.के.-एन.जी./6

अनुमति दी गई।

अब माननीय शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करेंगे।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 18) पुरःस्थापित हुआ।

Bill No. 19...........श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

01.9.32025/1605/PB-HK/1

अध्यक्ष ...जारी

बिल नम्बर 18 के पश्चात्

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरः स्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) पुरःस्थापित हुआ।

01.9.32025/1605/PB-HK/2

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

अब माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

Speaker : Anybody wants to speak? Nobody.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

01.9.32025/1605/PB-HK/3

अब माननीय शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेद विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) ध्वनिमत से पारित हुआ।"

01.9.32025/1605/PB-HK/4

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी। इसमें पहला विषय माननीय श्री केवल सिंह पठानिया का है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उसके बाद मैं इसे चर्चा हेतु सदन में रखूंगा।

श्री केवल सिंह पठानिया (उप-मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में 'संसाधन जुटाने हेतु' यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'प्रदेश में संसाधन जुटाने यानी Resource Mobilization हेतु' यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2025/1610/YK/AP/-01

अध्यक्ष जारी .....

मतदान नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे और चर्चा समाप्त हो जाएगी। मैं माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी से आग्रह करता हूं कि विषय को आप डिटेल में whatever you want to say you can express yourself in the discussions and how much time you like to take, 20 minutes, okay. माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया। Nearly 7 people from the Congress Party and equal number from the Bharatiya Janata Party also.

श्री केवल सिंह पठानिया(उप-मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए किसी नीति पर सरकार विचार करे उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इसकी अनुमति दी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पहली विधान सभा से लेकर चौदहवीं विधान सभा तक के सफर को हम देखें तो पहली विधानसभा से लेकर जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी उस समय कितना पैसा केंद्र से आता था और उस समय प्रदेश सरकार की कितनी सहभागिता उसमें होती थी। नया-नया प्रदेश जब बना, हमारा पहाड़ी प्रदेश था। रिसोर्सज न के बराबर थे जिस तरह से लंबी चर्चा विधान सभा के अंदर हुई है। यहां पर हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य, आदरणीय प्रो0 चंद्र कुमार जी हैं, जो वर्ष 1982 में विधान सभा में आए और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वर्ष 1985 में 26 वर्ष की उम्र में विधान सभा में प्रवेश किया था। आपने इस माननीय सदन में अनेकों बजट देखे हैं। बजट पास भी हुए, उनमें बहुत सी चर्चाएं भी हुईं है। जब हिमाचल प्रदेश बना, उस समय हिमाचल प्रदेश के पास 356 किलोमीटर सड़कें थीं। मेरे साथ मेरे भाई भवानी सिंह पठानिया जी बैठे हैं। जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया तो उनके पिता स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी बार-बार मुझे कहते थे कि डॉ0 वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और वह मुझे कहते थे कि अब तो जमाना आगे बढ़ गया है। जब वह चौथी या पांचवीं बार विधायक बने थे तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया

था और एक बार मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। वे कहते थे कि हम फतेहपुर से ट्रंक उठाते और रेलवे स्टेशन पठानकोट जाते थे, पठानकोट-से-अंबाला, अंबाला-से-कालका, उसके बाद परवाणु बस स्टैंड के बाद शिमला पहुंचते थे। लगभग चार-से-पांच दिन के बाद शिमला में विधान सभा का सत्र अटेंड करने आते थें। यह उस वक्त हिमाचल प्रदेश की व्यथा थी। आज कहते हैं कि देश व प्रदेश आगे बढ़े हैं।

01.09.2025/1610/YK/AP/-02

मैं बताना चाहता हूं कि चाहे डॉ0 वाई.एस. परमार जी, श्री रामलाल ठाकुर जी, श्री शांता कुमार जी, श्री वीरभद्र जी, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी, श्री जयराम ठाकुर जी या अभी के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हों, इन सब राजनेताओं का अपना-अपना बजट का प्रावधान रहा है और उससे पता लगता है कि प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश राज्य बना, देश की सरकारों का ऐसा प्रावधान था। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश था जो इस विधान सभा की चर्चा में था कि हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया जाना चाहिए, जिस प्रस्ताव को लेकर लगभग 26-27 सदस्य इस सदन में आए थे। लेकिन जब चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश बनना चाहिए या नहीं, उस समय बहुत से लोगों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य बनना चाहिए, लेकिन उनमें से 49 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बने। मैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2025/1615/AT/YK/01

श्री केवल सिंह पठानिया जारी ...

कि जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड देने का प्रश्न आया तो 3 मेंबरों की एक कमेटी बनाई। उसमें से दो मेंबरों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा है इसे राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक मेंबर की रिकमेंडेशन मानी गई और इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया।

(श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

उस समय भारत सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को 100 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड मिलती थी। अगर मैं लंबे आंकड़ों में जाऊं तो पहला बजट कितना था, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, मेरे पास सारा विवरण है। जहां से हमने सफर आरम्भ किया था तब से लेकर आज तक 1000 टाइम बजट हैं। धीरे-धीरे सरकारें भी आगे बड़ी और धीरे-धीरे बजट भी बढ़ा और जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। उस समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 34 प्रतिशत थी। आज मैं सरकारों को बधाई देना चाहता हूं कि निरंतर प्रयासों से हमने केरल को भी बाईपास किया।

स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तब देश की वैल्यूएशन हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जब वास्कोडिगामा वर्ष-1498 में भारत आया और ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब क्रिश्चियन मिशनरियों के माध्यम से केरल में शिक्षा आई। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने केरल के उस शिक्षा मॉडल को बाईपास करके अपनी नीति बनाई। नतीजा यह हुआ कि आज हिमाचल प्रदेश को 100 प्रतिशत साक्षर राज्य माना गया है।

1 नवंबर 1966 से पहले यहां एक भी कॉलेज नहीं था। केवल एक इंटरमीडिएट स्कूल जिसको आज राजकीय कन्या महाविद्यालय कहा जाता है जो लाहौर विश्वविद्यालय से संबद्ध रखता था। उस समय हिमाचल पंजाब का हिस्सा था लेकिन 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई।

01.09.2025/1615/AT/YK/02

मैं स्वयं छात्र नेता रहा हूं। उस समय केवल 15 कॉलेज थे जो बढ़कर 103 तक पहुंचे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हमेशा कहते थे कि जितना शिक्षा का विस्तार होगा उतना प्रदेश आगे बढ़ेगा। धीरे-धीरे कॉलेज खुले, सड़कें भी 356 किलोमीटर से आगे बड़ी और प्रदेश ने प्रगति की।

अब मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी 2 साल 4 महीने पहले मुख्य मंत्री बने और उन्होंने एक नारा दिया कि वर्ष- 2032 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर और ग्रीन स्टेट बनेगा। आंकडे विधान सभा के अंदर भी है और सभी अधिकारियों के पास भी हैं

उन्होंने कहा कि मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। इस दौरान उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की जनसंख्या के लिए जो फैसले लिए जायेंगे आज नहीं तो कल वह याद किए जायेंगे।

कुछ फैसलों में केंद्र सरकार का सहयोग भी जरूरी था। एन0टी0पी0सी0, 12-18-30 की बात हो और वाटर सैस का मामला इसका उदाहरण है। कई पावर प्रोजेक्ट जैसे सानन और बैरा सूल का समय पूरा हो चुका है और पूरा हिमाचल प्रदेश इन प्रोजेक्ट्स के ट्रांसफर का इंतजार कर रहा है। मुख्य मंत्री ने यह मुद्दा उठाया और बैरा सूल के मामले को भी आगे बढ़ाया।

कई लोगों ने कोशिश की कि न्यायालय या अन्य माध्यम से इन फैसलों को रोका जाए लेकिन मुख्य मंत्री ने हिम्मत दिखाई और कई कड़वे फैसले भी लिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए उन्होंने वाटर सैस लागू किया, एक्साइज पॉलिसी में संशोधन किया और कड़छम-वांगतू का मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। इससे 256 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश की जनता को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मिला है।

एम0डी0द्वारा जारी....

01-09-2025/1620/AG/MD/1

श्री केवल सिंह पठानिया---जारी :

हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। आप वाइल्ड फ्लावर हॉल की हिस्ट्री देखिए। मैं जानता हूं यह जो अभी फैसला हुआ है, यह ऐतिहासिक फैसला है। मैं उस पर भी आऊंगा जो एक सब-कमेटी बनाई थी। यह एक ऐतिहासिक फैसला था और सरकार को पूरा एक वर्ष लग गया। वाइल्ड फ्लावर हॉल की जमीन ओबरॉय क्लार्क्स को उनको पहली प्रॉपर्टी 1 रुपये की लीज पर मिली। आज मैं कहता हूं कि वाइल्ड फ्लावर हॉल की जमीन लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए की है और आज हिमाचल प्रदेश सरकार उसकी मालिक है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि केवल यही नहीं इसके साथ-साथ उन्होंने माननीय

मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में विचार-विमर्श हुआ कि हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बनें। हमारे रिसोर्सिज क्या है? पर्यटन की दृष्टि से वह जानते थे कि पर्यटन ज्यादा कहां बढ़ेगा, क्योंकि हाई एंड टूरिस्ट वहीं आता है जहां मैक्सिमम फ्लाइट आती है। उन्होंने कोशिश की और कैबिनेट में कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया। एयर पोर्ट भी आगे जाए, वह एक ऐसा इकलौता एयर पोर्ट है जहां गर्मियों में 12 से 15 फ्लाइट आती हैं और वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। मैं कहता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से चाहे टूरिस्ट विलेज की बात हो, वह भी आगे बढ़े, फिर चाहे वह पालमपुर के अंदर हो या फिर चाहे वह ट्रैकिंग रूट हो। आज कांगड़ा के अंदर कितना बड़ा जू बनने जा रहा है। लंबे समय से इधर-उधर की बात की जा रही थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय था। हम भी चाहते हैं कुछ क्लासिज वहां चलें। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश का नेतृत्व 10 वर्ष तक करते रहे, वह भी अगर कांगड़ा के अंदर उतारा है और अगर आज 90% केंद्रीय विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ चाहे वह देहरा, धर्मशाला या फिर वह शाहपुर में चले, यह बहुत बड़ा काम मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में किया गया।

पर्यटन की दृष्टि से हम कैसे आगे बढ़े? आपने जो होम स्टे की नीति को रिलैक्स किया। यही नहीं जो आपका सबसे पहले रिसोर्स मोबलाइजेशन में पर्यटन की दृष्टि से काम करने का प्रयास है। यहां पर 67% फॉरैस्ट है और यह विधान सभा में लगे प्रश्न के अंतर्गत दिया गया उत्तर है। मैं कहता हूं ईको टूरिज्म पॉलिसी पर जो संकल्प माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी यहां लेकर आए थे कि फॉरैस्ट के साथ ईको फ्रेंडली

01-09-2025/1620/AG/MD/2

रहें। बिल्डिंग्ज खड़ी करने से जो बात आती है, वह आज नहीं कल भी निकलेगी। अरबों रुपए के होटल, आप भी जानते हैं और बाघल में आते-जाते रुकते भी हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार इत्यादि वहां जाते हैं। वहां पर गाड़ी रोककर चाय पीते हैं। वन विभाग के द्वारा जो ईको टूरिज्म हम चाह रहे थे, उसमें एक साइट का निर्माण करके लोकल लोगों को इंवॉल्व करें ताकि लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले और जिससे लोकल लोगों और सरकार का भी रिसोर्स बढ़े। मैं पर्यटन की दृष्टि से यह कहना चाहता हूं कि इस पर काम करने की जरूरत है। एयरपोर्ट अगर जिस तरीके की माननीय मुख्य मंत्री

जी की मंशा है तो मैं कहता हूं कि न केवल कांगड़ा बल्कि चंबा, उन्ना, हमीरपुर, मण्डी यानी हर जिले में बनाए जाएं। इसके साथ-साथ में इंडस्ट्रीज, खासकर आई0टी0 पार्क की बात करना चाहूंगा। आज वर्क फरोम होम का चलन है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में करैरी के अंदर 100 कमरे के छोटे-छोटे कैप्सूल रूम बनाएं है। जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कि तीन वर्षों से 100 में से 80 कमरे लगे हैं। बच्चे वहीं रह रहे जैसे बेंगलुरु, चेन्नई इत्यादि राज्य के और वहीं से वर्क फरोम होम कर रहे है। उन्होंने वहीं से वाई-फाई उपलब्ध करवाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे आई0टी0 की इंडस्ट्री और खासकर मैं चाहता हूं कि जो हमारी झीलें हैं उन पर हम पर्यटन की दृष्टि से काम करेंगे तो राज्य सरकार के संसाधनों में इज़ाफा होगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हमीरपुर जिला है, उसको स्पेसिफाई कर देना चाहिए। जिस तरह से एजुकेशन हब कोटा डवलप हो सकता है क्योंकि वहां पूरे देश के लोग जाते हैं। वहां इतनी बड़ी एकेडमी है, वहां से कोचिंग लेने की सब लोग कोशिश करते हैं। वह चाहे नीट हो आई0ए0एस0 या एच0ए0एस0 का एग्जाम हो। कोटा एक बहुत बड़ा शहर है और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बन गया है।

श्रीमती के0एस0 जारी -----

01.09.2025/1625/केएस/एजी/1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी ---

मैं चाहता हूं कि हमीरपुर को भी एक एजुकेशन हब के रूप में डवलप करें। इससे भी आने वाले समय में, चाहे इंस्टिट्यूशन्ज़ हैं, स्कूल्ज़ हैं, चाहे हमारी इम्प्लॉयमेंट हैं, उनको फायदा होगा। तीसरा आई.टी. और रिसर्च सैंटर हैं। क्योंकि ये जो मैं इको-टूरिज्म की बात कर रहा हूं ये रिसर्च सेंटर फोरैस्ट में भी हो सकते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैं हावर्ड युनिवर्सिटी गया था तो वहां मैं 7-8 प्रोफैसर्ज़ और 25-30 बच्चों से मिला। वे तो यही कहते हैं कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट अब

बोस्टन के थोड़े ही हैं। कहां उन्होंने कंपैरिजन किया, मुझे प्रोफैसर्ज़ ने डेढ़ घंटे की जर्नी ऑफ हार्वर्ड युनिवसिर्टी दिखाई । कैसे वह बनी, कैसे बोर्ड ऑफ डायरैक्टर बना और कैसे उन्होंने एजुकेशन के बारे में सोच डवलप की। 1776 में अमेरिका बना, 1636 में ही हार्वर्ड युनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी। हार्वर्ड युनिवर्सिटी में जो उन्होंने कहा, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में हमारा जोगिन्द्रनगर का लड़का राजकुमार है, लोबसेंग सांगे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इन-एग्ज़ाइल रहे हैं, वे हैड ऑफ डिपार्टमैंट ऑफ लॉ रहे हैं, हमारा Shri Rajinder Kumar, Head of Department of Biotechnology, from Hamirpur, चम्बा की रहने वाली सारिका, Assistant Professor, Department of Physics है, वे दस-पन्द्रह लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि आपके यहां जो एनवायरनमैंट रिसर्च है, क्योंकि वहां पर भी अब इकालॉजी और एनवायरनमेंट वैसे नहीं रहे है। तो ये जो रिसर्च सैंटर्ज़ हैं, एजुकेशन हब हैं, जब लोग यहां आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहां जी.एस.टी. ज्यादा आएगा। हम होटल की बात क्यों करते हैं, टूरिज्म की बात क्यों करते हैं, एयरपोर्ट की बात क्यों करते हैं ताकि आने वाले समय में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने।

सभापति महोदय, जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षतामें एक कमेटी बनी है और माननीय विधायक श्री राम कुमार जी भी उसके सदस्य हैं। SEZ जोन जो बाउंडरी एरिया हैं, अभी शुरुआत की है वह चाहे इंदौरा हो, बद्दी-नालागढ़ हो या अन्य क्षेत्र हों परंतु इसकी तरह ना हो। मैं मानता हूं कि पैकेज आया, हमारे पास धन भी आया लेकिन अगर आज आप बद्दी की प्लानिंग देखें, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार हों लेकिन वहां की प्लानिंग ठीक नहीं है। नॉर्वे में इंडस्ट्रियल एरिया 1962 में शुरु किया गया था। जो आज भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पर कोई प्लानिंग नहीं हुई। पॉलिसी आई, पैसा मिला और हमने तुरंत प्लॉट अलॉट कर दिए। सड़क, पानी, बिजली, एनवायरनमैंट,

01.09.2025/1625/केएस/एजी/2

इकोलॉजी आदि कुछ नहीं देखा। आप सभी को उसके बारे में पता है। राम कुमार जी वहां से इसीलिए समय पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहां जाम की समस्या रहती है। तो ये SEZ जोन हमारे इकोनॉमिक जोन ऐसी जगह हों और आज तो इको फ्रेंडली भी बहुत सा काम है। गुज़रात ने सुनियोजित तरीके से यह काम किया है। आंदोलन भी होते हैं। वहां वैस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज़ हैं, हिमाचल की तीन इंडस्ट्रीज़ भी वहां गई हैं, उन्होंने बड़े अच्छे

तरीके से SEZ जोन पहले प्लान किए कि किस तरीके की सड़क होगी, इको एन्वायरमेंट आदि सब प्लान किया। फार्मा के बारे में मेरे चार प्रश्न लगे थे। कहा जाता है कि एशिया में हम नम्बर-1 बिजली पैदा करते हैं। मैंने जब एक्साइज के बारे में पूछा कि कितना एक्साइज़ आता है तो मुझे बताया गया कि 200 करोड़ रुपये ही आता है। क्योंकि हम तो प्रोडक्शन स्टेट है, जो हमें मिलना था वह मिल चुका और इकोलॉजी व एनवायरनमेंट हमारे खराब हो रहे हैं। सब कुछ हमारा है लेकिन हमें केवल 200 करोड़ रुपये ही आते हैं। ये जो SEZ जोन हैं, ये आने वाले समय में इस तरीके से प्लान हों, यह मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। इसी तरीके से हमारी engineering good production in Himachal Pradesh. विदेशों की इसीलिए तुलना करते हैं क्योंकि विदेशों में, कृषि मंत्री जी एक दिन कह रहे थे कि शांता कुमार जी स्विटज़रलैंड की बात करते थे। वर्ष 1977 में वे कहीं न कहीं गए होंगे, कहीं न कहीं वह रेफरेंस उन्होंने दिया होगा लेकिन जो ऑफिसर्ज़ गैलरी में लोग बैठते हैं, काम तो वे करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे कामों के लिए लोग हमको भी याद रखेंगे। औद्योगिकरण के लिए मुख्य मंत्री को, प्रधान मंत्री को निरंतर याद किया जाता है। भाखड़ा में जब भी जाओ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद किया जाता है। जय जवान, जय किसान के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसलिए याद किया जाता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

01.09.2025/1630/AV/as/1

श्री केवल सिंह पठानिया------ जारी

स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जब वे अपने दोनों कार्यकाल में लगभग 6 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे तो उस समय हिमाचल प्रदेश में काँग्रेस पार्टी की सरकार थी और उन्होंने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना।

मैं यहां दीर्घा में बैठे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आपको जो-जो जिम्मेवारियां राष्ट्रपति महोदया या राज्यपाल महोदय द्वारा प्लीज की जाती हैं यानी क्लास-IV से मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार तक जो-जो जिम्मेवारियां मिली हैं, प्रदेश के 70 लाख लोगों में से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी हैं और बहुत कम लोगों को गवर्न करने का मौका मिलता है। यहां पर हाउस के अंदर आने का भी और जो लोग एग्जिग्यूट करते हैं। यह वर्ष 1977 से चर्चा हो रही है कि ये-ये जिले हैं जिनको हमने विकसित करना है। सरकारें आती हैं और अपना-अपना थीम देती हैं परंतु उनको धरातल पर उतारने में कोई-न-कोई समस्या रहती है। इसमें मुख्य कारण यह है कि पांच वर्ष बाद सरकार चेंज हो जाती है और चेंज होने के बाद उस सरकार की प्राथमिकता भी बदल जाती है।

रिसोर्स मोबलाईजेशन कमेटी की यह सिफारिश आ चुकी है कि जो काम छेड़ा है उस काम को अंत तक ले जाना है। सरकार तो कंटीन्यूटी में रहती है। इसलिए सरकार कोई भी आए वह उस काम को आगे बढ़ाए जिससे कि 70 लाख हिमाचलियों को उसका फायदा हो।

कांगड़ा के अंदर लगभग 234 करोड़ रुपये की लागत से मिल्क प्लांट लगाया जा रहा है। इसी तरह से टाहलीवाल, ऊना में भी बहुत बड़ी इण्डस्ट्री आई है। एक दिन मंत्री जी के साथ मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। हमने अमूल के पांच प्लांट्स विज़िट किए। वे प्लांट्स लगभग 1500-1800 करोड़ रुपये की लागत से लगे हैं और उनकी ए, बी, सी और डी के हिसाब से क्लासिफिकेशन की गई है। वहां पर हमें एम0डी0 ने बताया कि हिन्दुस्तान में ए-ग्रेड चॉकलेट नहीं बिकती, वे सारी स्विटजरलैंड इत्यादि दूसरे देशों में जाती हैं। अमूल ने मार्किट ही इस तरीके से क्रिएट की है।

01.09.2025/1630/AV/as/2

हमारे पास माइनर फॉरैस्ट थे और आज भी हैं। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि टोप की पोस्ट्स को कम कीजिए, मैंने इस बारे में लिखा है। यहां मुख्य सचिव की केवल एक पोस्ट है और अतिरिक्त मुख्य सचिव की कोई पोस्ट नहीं है। पी0सी0सी0एफ0 भी एक ही है। इसी प्रकार से बिजली विभाग के अंदर भी है।

रिसोर्स मोबलाईजेशन तो हुआ नहीं परंतु जो प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने, ईको फ्रेंडली उद्योग लगाने इत्यादि के बारे में जो पोलिटिकल मेन्डेट था, वर्तमान चौदहवीं विधान सभा चल रही है लेकिन वह मेन्डेट अभी तक केवल 30 प्रतिशत तक प्राप्त हुआ है।

मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी विभाग है उनमें केवल टोप की पोस्ट्स हैं और नीचे लाइनमैन या फिटर इत्यादि कोई नहीं बचा है। मैं यहां कमेटी की सिफारिशें देख रहा हूं। इसको एक महीना पहले सब्मिट किया था और मैं तो इसको ऐसे ही ले आया था कि इसके ऊपर कम-से-कम सदन तो विचार करे कि हम कैसे आत्मनिर्भर बनें।

माननीय मुख्य मंत्री ने जो डेरी फार्म के बारे में फैसला लिया है कि गांव की आर्थिकी कैसे मजबूत हो, हम कृषि प्रधान राज्य है। यही नहीं देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक, आप यू0एन0ओ0 की स्पीच भी सुन लेना। India is a agriculture based economic country. आप चाहे माननीय पं0 जवाहर लाल नेहरु की बात सुनिए या माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की बात सुनिए, हिन्दुस्तान के प्रत्येक प्रधानमंत्री के अब तक पहले दस शब्द ये ही हैं कि India is an agriculture based economic country.

मैं आपको यहां पर स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी की बात को फिर से सुनाता हूं। वे कहते थे कि जब हम पहली बार एम0एल0ए0 बनकर आए थे तो हमारी तनख्वाह 700 रुपये थी जोकि 200 रुपये से शुरू हुई थी। फिर यहां सदन और केंद्र में संसद के अंदर कहा जाता है कि double the income of Kisaan. उन्होंने जैसे बताया कि उनकी तनख्वाह शुरू में 700 रुपये थी और जब तक वे इस सम्माननीय सदन के सदस्य रहे तब तक उनकी तनख्वाह डेढ़-पौने दो लाख रुपये तक पहुंच गई थी। पहले तोलने की यूनिट्स

1.09.2025/1630/AV/as/3

तड़ी, बट्टी, मण इत्यादि होती थीं। पहले इन यूनिट्स के अंतर्गत धान व कनक इत्यादि तोले जाते थे। इसी तरह से टोपा, दो टोपा इत्यादि चीजें चलती थीं

टी सी द्वारा जारी

01.09.2025/1635/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री केवल सिंह पठानिया... जारी

यही परंपरा चलती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारी सैलरी डेढ़ लाख रुपये हैं और मैंने चीफ सेक्रेटरी का भी रेफरेंस दिया है, मैंने मुख्य सचिव की तनख्वाह का भी उल्लेख किया है। मुख्य सचिव की तनख्वाह भी 1000 रुपये से भी कम होती थी और हम विधान सभा व लोकसभा में कहते हैं कि किसानों की इनकम डबल करेंगे। उस समय भी आना-दो आना यानी अस्सी पैसे, नब्बे पैसे और एक रुपया प्रति किलो कनक (गेहूं) थी लेकिन आज आज मुख्य सचिव की आय तो छह लाख रुपये तक पहुंच गई है जबकि वास्तविकता यह है कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य बड़ी मुश्किल से तय हुआ है। मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी मुश्किल से किसानों को समर्थन मूल्य दिया है और कनक 3 या 5 रुपये किलो बिक रही है । आज हमारी तनख्वाह 1.50 लाख रुपये हो गई है और जो अधिकारी उधर बैठते हैं उनकी तनख्वाह 6 लाख रुपये हो गई है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है और हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख है। जब हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है तो पर-कैप्टा इनकम भी उसी आधार पर होनी चाहिए। अच्छी प्लानिंग और गुड गर्वनेंस वही होगी जब हम 68 माननीय सदस्य, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी मिलकर 70 लाख लोगों को आगे बढ़ाएं।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि डेयरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य मंत्री महोदय आप अमूल मिल्क प्लांट का विजिट करके आए है और इसी तरह से यहां भी अच्छे उद्योग स्थापित हों। इसी प्रकार एनवायरनमैंटल टैक्स लगाया जाता है, विदेशों में भी है और हमारे देश में भी है। बाहर से आने वाले लोगों पर यह टैक्स लगे जिससे हमारी

इकोलॉजी और एनवायरनमैंट सुरक्षित रहे और उद्योग लगाकर हम सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा सकें। हाइड्रो प्रोजैक्ट से जुड़ी आपदाओं पर भी ध्यान देना होगा। मेरा यह विषय 20-25 दिन से लंबित पड़ा था। हमें ऐसा विकास चाहिए जो विनाश न करे। चाहे फोरलेन प्रोजैक्ट्स हो या हाइड्रो प्रोजैक्ट्स इन पर मुख्य मंत्री महोदय ने 12,18,30 की बात कही है। अगर 12,18,30 नहीं दिया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरह हमें भी स्पेशल असिस्टेंट मिलना चाहिए। अरुणाचल जैसे राज्यों में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर यह सहायता

01.09.2025/1635/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

दी जाती है। मुख्य मंत्री महोदय ने 12,18,30 की बात की है। इसी तरह खेलों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमारे पास शिलारु में केवल एक हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम है। बहुत-सी गेम्स हैं, कम से कम 29 गेम्स पर अगर हम पैसा खर्च करें तो आने वाले समय में खेल नीति और मजबूत होगी। ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां मनाली की तरह अन्य जगहों पर भी विकसित की जा सकती हैं ताकि बाहर से लोग आएं और पर्यटन के साथ खेलों को भी बढ़ावा मिले। उप-मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें 9 पॉइंट्स तय हुए थे, चाहे वह बिजली विभाग हो या एच0आर0टी0सी0 विभाग हो, इनमें 1700-1800 करोड़ रुपया आता है, लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा कहां जाता है?

अब मैं अपने संस्थान की बात करूं तो चार-चार, छह-छह गाड़ियां विभागीय प्रमुखों को आबंटित की हुई हैं। इस पर मैंने प्रश्न भी किया था लेकिन दो बार उसे पोस्टपोन कर दिया गया लेकिन अब मैंने उसको लगवा लिया क्योंकि यह मेरा मैन्डेट है। नियम सबके लिए एक होना चाहिए। एक विभाग प्रमुख को एक ही गाड़ी मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि सभी के लिए एक समान रूल्ज होने चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई विधायक एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसको गाड़ी उपलब्ध नहीं होती, जबकि विभागाध्यक्षों के पास चार-चार गाड़ियां हैं। यह संवैधानिक असमानता है। कमेटी ने इस पर सुझाव दिए हैं, लेकिन उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। माननीय सदस्य परमार साहब मैं तो आपका छोटा भाई हूं यह कहा जाता है कि विधायक मुख्य सचिव से ऊपर है तो माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है उसको नोटिफाई करना चाहिए। इसको नोटिफाई करने का आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसको अभी तक भी नोटिफाई नहीं किया गया है। एक दिन मैंने गाड़ी मांग ली तो मुझे

कहा गया कि गाड़ी उपलब्ध नहीं है लेकिन चण्डीगढ़ के 17 सैक्टर में एक सरकारी गाड़ी घूम रही थी और मैंने उसकी फोटो भी डाली थी। मैंने यह भी पूछा था कि असंवैधानिक तरीके से यह गाड़ी कैसे घूम रही थी? यही नहीं है इस माननीय सदन में पक्ष-विपक्ष में कांगड़ा के माननीय सदस्य भी हैं इसलिए मैंने एयरपोर्ट जुब्बड़हट्टी का उदाहरण दिया था।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा.... जारी

01-09-2025/1640/NS-DC/1

श्री केवल सिंह पठानिया ----जारी

फिर मैंने विधान सभा सचिवालय के बारे में भी कहा कि यह भी मैन्डेट पहले किसका है? 68 लोग जो जीत कर आते हैं उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके लिए है। यहां किसी और के लिए मैन्डेट नहीं है। उसके बाद जब टेलीफोन करते हैं तो व्यवस्था की जाती है। अब मैं डिजास्टर के तहत तीन बातें रखने जा रहा हूं। आज डिजास्टर एक्ट लागू हो गया है और उसके लिए मैं शून्य काल में विषय उठाऊंगा। मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन विषय से हट कर बोल रहा हूं क्योंकि यह 68 विधायकों की बात है। डिजास्टर जहां भी होता है तो आपने पिछले डेढ़ माह से देखा होगा कि पहला आदमी वहां कौन पहुंचता है? वहां सबसे पहले विधायक पहुंचता है। विधायक के ऊपर 24 घंटे सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हुए हैं। मैं जानता हूं कि पी0एस0ओ0 के संबंध में पूछे गए प्रश्न को विड्रो किया गया है। मैं इसके बारे में यहां तो बोल सकता हूं। मैंने कहा कि बहुत-सी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां विधायक जाता है। कहीं ऊपर-नीचे भी हो जाती है। मैंने इस बार दो पी0एस0ओ0 की बात की थी कि विधायक के साथ दो पी0एस0ओ0 होने चाहिए। विधायक की मजबूरी है और वह चला हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार आदेश करे क्योंकि यह विधायकों की संस्था की बात है। मुख्य मंत्री जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि टोप को तो एज पर कॉंस्टिच्यूशनली करेंगे जिससे टोप को तो और रिसोर्स मिलेंगे। मैंने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कमेटी बनी हुई है और बिजली बोर्ड की मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और ऐसी बहुत-सी कमेटियों का गठन किया गया है। मैं चाहता हूं कि कमेटीज की रिकोमैंडेशन पर और सदस्य भी बोलें और उनको भी बोलने का समय

मिलेगा। अगर हम उन रिकोमैंडेशन्ज को शत प्रतिशत लागू कर देंगे तो सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग लाभान्वित होंगे। यह बात ठीक है कि सरकारें आएंगी, सरकारें पहले भी आई हैं और आती-जाती रहेंगी। अगर अब हमें मौका मिला है और हम काम करके जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के लोग हमेशा याद करेंगे। मुख्य मंत्री जी को करछम वांगतू, वाइल्ड फ्लॉवर हाल जो ये दो मील के पत्थर हैं तो इनके लिए हमेशा याद करेंगे। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं जानता हूं कि जब ये फैसले लिए जाते हैं तो बहुत-सी मुश्किलें आती हैं लेकिन उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की

01-09-2025/1640/NS-DC/2

हक की बात की है। सभापति महोदय, संसाधन जुटाने हेतु हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और आगे कैसे बढ़े तो यह हमारी भी जिम्मेदारी है, प्रदेश की लगभग 70 लाख जनता की भी जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आया हूं। धन्यवाद, जय हिंद।

01-09-2025/1640/NS-DC/3

सभापति : अब श्री विपिन सिंह परमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, श्री केवल सिंह पठानिया जी "संसाधन जुटाने हेतु" यह सदन नीति बनाने पर विचार करे। इस पर मैं भी अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण व सामायिक विषय है। संसाधन बढ़ने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। लेकिन जब मैं हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य की तरफ देखता हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर जैसे हालात से गुजर रही है। मैं पढ़ रहा था कि प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां कम हैं और राजस्व व्यय अधिक है

तथा कई चुनौतियां भी हैं। अब इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं यह भी देख रहा था कि प्रदेश ने 1,00,000 करोड़ रुपये की लंबी छलांग लोन के रूप में लगा दी है यानी हिंदुस्तान के कुछ चुने हुए प्रदेशों में अब हिमाचल प्रदेश उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर सर्वाधिक लोन है। जो बच्चा यहां पर पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके सिर पर 1.12 लाख रुपये का लोन है। सभापति महोदय, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट क्या कहती है? मैं राजस्व संसाधनों का जिक्र बाद में करूंगा लेकिन पहले राजस्व रिपोर्ट का जिक्र करूंगा। राजस्व रिपोर्ट कहती है कि अगर परिस्थितियों को संभाला नहीं गया

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.09.2025/1645/RKS/DC-1

श्री विपिन सिंह परमार...जारी

तो हिमाचल प्रदेश debt trap में फंस जाएगा। अगर हमने अपने संसाधनों को सुव्यवस्थित नहीं किया तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस माननीय सदन में आंकड़े किसी भी प्रकार के रखे जाएं लेकिन हिमाचल प्रदेश debt trap के दौर से गुजर रहा है। CAG की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप भी एक विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहां विकास की गति रुक गई है, चाहे यहां हम कितने बड़े-बड़े दावे क्यों न करें। हिमाचल प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपये और व्यय 46,667 करोड़ रुपये है। इसमें हिमाचल प्रदेश को लगभग 5,558 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। मैं इन आंकड़ों का जिक्र CAG की रिपोर्ट के आधार पर कर रहा हूं। यहां जो लोन है, GSDP अनुपात 43.98 प्रतिशत है जबकि FRBM एक्ट में यह सीमा 38.98 प्रतिशत से अधिक एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश के आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में इतना अधिक कर्ज हो गया है कि अब कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। कुल

मिलाकर यहां की परिस्थितियां बहुत भयंकर हैं। राजस्व प्राप्तियां बहुत कम हैं। हिमाचल प्रदेश में टैक्स व नॉन-टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है। हमारी आय का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। हमें भारत सरकार जो अनुदान देती है उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। हिमाचल प्रदेश सरकार उन अनुदानों के सहारे चल रही है। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश को एक औद्योगिक पैकेज दिया था। यह पैकेज 2010 में समाप्त हो गया था। केंद्र में जब UPA की सरकार थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश के कई सांसद UPA सरकार में थे लेकिन वे हिमाचल प्रदेश के हक की लड़ाई नहीं लड़ सके। वर्तमान में BBNA में नया उद्योग आना तो दूर की बात है बल्कि जो उद्योग पहले से स्थापित हैं वे भी छोड़कर जा रहे हैं। फिर हमारी राजस्व प्राप्तियां कैसे बढ़ेंगी? हिमाचल प्रदेश में 30 प्रतिशत राजस्व फार्मा उद्योग से आता है। आज फार्मा उद्योग की छवि क्या हो गई है यह सबको मालूम है। यहां उत्पाद होने वाली दवाइयों को खरीदते समय लोग शंका से देखते हैं। यानी BBNA में तैयार होने वाली दवाइयों को लोग कहते हैं कि हिमाचल की दवाइयां खुद ही बीमार हैं। जब दवा ही बीमार हो गई है तो जो हिमाचल प्रदेश को

01.09.2025/1645/RKS/DC-2

30 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां कहां से आएगी? मेरा सुझाव है कि यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत भी जा सकता है लेकिन इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं यहां पर संसाधनों की वृद्धि के बारे में भी अपनी बात कहना चाहूंगा

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2025/1650/बी.एस./एच.के.-1

श्री विपिन सिंह परमार ..

और जो थोड़े से संसाधन हैं, हमें उन्हीं के बीच में रह करके अपनी बात कहनी होगी। बड़ा बनने के लिए बड़ी घोषणाएं करने की जरूरत नहीं है और ये तो अपने ही घोषणा पत्र के ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसीलिए यह वित्तीय संकट पैदा हो गया है। जो कुल व्यय है, टोटल

एक्सपेंडिचर है, उसका 9 प्रतिशत से 13 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी के ऊपर जा रहा है। प्रदेश में बिजली सब्सिडी का बोझ 35 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के रूप में जा रहा है। सब्सिडी बिना किसी निश्चित लक्ष्य और पारदर्शिता के न होने के कारण यह बोझ बढ़ता जा रहा है। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैं सरकार की एक और उपलब्धि गिनाना चाहता हूं। भारत सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं रखी है। उसका जिक्र में बाद में करूंगा। मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में योजनाओं और धन का दुरुपयोग हो रहा है जो भारत सरकार पैसा दे रही है उसे व्यय करने में डिसिप्लिन नहीं है। प्रदेश में केंद्र सरकार से मिले 31.85 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया। मैं यह रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। शिक्षा पर 510 करोड़ रुपये, कृषि पर 216 करोड़ रुपये और परिवार कल्याण पर 150 करोड़ रुपये कम खर्च किये गये हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार पैसा दे और तो और जो भारत सरकार पैसा दिया है, 2,990 करोड़ रुपये अभी तक उपयोग प्रमाण पत्र लंबित हैं। जिसकी राशि 2,795 करोड़ रुपया बैठती है। सभापति महोदय, यह सरकार जो भारत सरकार से पैसा आ रहा है उसे भी धरातल पर खर्च नहीं कर रही है जिसके कारण सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य संस्थान हो और समाज में जो आम व्यक्ति से जुड़ी हुई जरूरत हैं वह पूरी नहीं हो पा रही है। यह बात भी मैं यहां पर आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो पैसे दिए मैंने यहां पर उसके आय और व्यय का जिक्र कर दिया। मैं एक बात यहां पर और रखना चाहता हूं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने हिमाचल प्रदेश को 11,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

01.09.2025/1650/बी.एस./एच.के.-2

है, यह भी मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। इसे विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत किया गया है और हिमाचल प्रदेश का तो हक ही छीन लिया गया था। अगर इस हक को न्याय दिलवाने के लिए किसी ने काम किया है तो वह एन.डी.ए. की सरकार और श्रद्धे श्री

नरेंद्र मोदी जी ने किया है जिसमें 90/10 के तहत हिमाचल प्रदेश को विशेष कैटेगरी में रखा गया है। यह बात भी मैं यहां पर रखना चाहता हूं।

यह ठीक है कि आज प्राकृतिक आपदा है कुछ लोग एन.एच.ए.आई. को दोष दे रहे हैं, कुछ उसकी कार्यप्रणाली को दोष दे रहे हैं परंतु आज अगर जीवन की रेखाओं को, इन सड़कों को जोड़ने का काम छह एन.एच.ए.आई. के माध्यम से हो रहा है तो उसमें 42,000 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में खर्च किया जा रहा है। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैं एक बात सभापति महोदय और कहना चाहता हूं, पिछले दिनों आपदा राहत और पुनर्निर्माण में 2,006 करोड़ रुपये की सहायता बाढ़ पीड़ित और बारिश प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार ने दी। 1,504 करोड़ रुपया 0.8 करोड़ रुपया एन.डी.आर.एफ. के तहत भारत सरकार ने दिया और स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 220.10 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया।

स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, वाइब्रेट विलेज की बात हो, यू.पी.एस. (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) ऑप्शन दी है, यहां भी कुछ लोगों ने और अधिकारियों ने उसको ऑप्ट किया है। उसमें भी भारत सरकार ने क्या कहा है? मजबूरी नहीं है अब आपके लिए वह चुनौती हो सकती है, आप लागू कीजिए 1,600 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता केंद्र सरकार देगी।

श्री दिवेश पठानिया द्वारा जारी...

01.09.2025/1655/DT/HK-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

अब इतना सब कुछ आ रहा है यह हिमाचल प्रदेश की सरकार की सेहत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह बात मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बहुत सालों से यह कहा जाता रहा है कि हिमाचल प्रदेश जहाँ नदियों में, नालों में, झरनों में पानी बहता है उसकी पहले कोई रॉयल्टी नहीं मिलती थी। मुझे याद है जब 1990 में श्री शांता कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तब रॉयल्टी को दिलाने की दिशा में प्रयास

शुरू हुआ थाहालांकि उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। आज मैं यह बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश की हाइड्रो पावर क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट के आसपास है लेकिन इसका हम पूरी तरह दोहन नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़छम-वांगटू परियोजना के संदर्भ में कहा है कि जो रॉयल्टी 12प्रतिशत थी, उसे बढ़ाकर 18प्रतिश4 किया जाए। यह एक सराहनीय निर्णय है जिससे हिमाचल सरकार को राहत मिलेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और यह मामला मामला हमारे समय से ही चला हुआ था। ग*वर्नमेंट इन कंटिन्यूटी* और इसकी पैरवी हमारे समय हुई थी। आप अन्य विद्युत परियोजनाओं में भी प्रदेश को उसका हक दिलवाने की दिशा में कदम उठाएं। आप स्वयं *रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी* के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। कृपया इस बात को नोट कीजिए। इस निर्णय से हमें लगभग 150 करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त होगी। लेकिन सवाल यह है कि अन्य परियोजनाओं में भी इसी प्रकार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सभापति महोदय, बीबीएमबी की एक लंबी लड़ाई चली है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में नहीं था तब बिलासपुर पूरा इलाका डूब गया था। श्री मलेन्द्र राजन भी अपने विधान सभा क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे। जब 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो उसने मंड के पूरे इलाके को साफ कर दिया। सवाल यह है कि उस पानी का हमें क्या मिलता है? वह पानी राजस्थान जाता है, दिल्ली जाता है, हरियाणा और पंजाब तक जाता है लेकिन हिमाचल प्रदेश को केवल 3% हिस्सा मिलता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2011 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था जिसमें कहा गया कि हिमाचल को फ्री पावर मिलनी चाहिए और यह भी कहा गया कि 7.19% के हिसाब से रॉयल्टी या फ्री पावर दी जानी चाहिए। लेकिन आज तक वह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस पर व्यक्तिगत ध्यान दें और इस क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करवाएं। जब यह पैसा मिलेगा तब हिमाचल प्रदेश की आर्थिक

01.09.2025/11655/DT/HK-2

स्थिति और मजबूत होगी। सभापति महोदय, मैं शानन हाइडल प्रोजेक्ट का भी जिक्र करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि शोंगटोंग प्रोजेक्ट 2026 तक तैयार हो जाएगा। इससे 1000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होगी। यह हिमाचल की सेहत को और सशक्त बनाएगा। मैं सुझाव देना चाहता हूँ और कृपया इसे नोट किया जाए कि हिमाचल प्रदेश में

सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जाएं ताकि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकें। सभापति महोदय, हमारे चेयरमैन साहब जो नगरोटा से हैं वे यहां से चले गए। ये ADB का बार-बार उल्लेख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 ट्रेड अफेयर्ज लगे। पता नहीं यहां टूरिज्म विभाग के कोई अधिकारी उपस्थित हैं या नहीं? मुख्य मंत्री तो यहां नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश का किसी भी ट्रेड फेयर में स्टॉल नहीं लगा है। कश्मीर के पहलगांव में जो घटना घटती है वहां फिर टूरिस्ट जा रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री चेन्नई, मुंबई, मद्रास, कोलकाता और दिल्ली जाते हैं।

श्री एन0 जी0द्वारा जारी

01.09.2025/1700/वाई.के.-एन.जी./1

श्री विपिन सिंह परमार........जारी

लेकिन यहां का कोई भी व्यक्ति या अधिकारी नहीं जाता। पर्यटन विभाग के चेयरमैन साहब को तो पता ही नहीं है कि इस प्रकार के टी0टी0एफ0 व प्रदर्शनियां कब-कब लग रही हैं। यहां पर तो पालमपुर की उस जमीन पर नज़र रखी हुई है कि इसे जल्दी-से-जल्दी दे दो। वहां पर रोप-वे बनना चाहिए और उसकी तरफ कोई नज़र नहीं है। आज माता चामुण्डा जी के मंदिर के क्या हालात हैं? जिस ठेकेदार को उस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य दिया हुआ है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभी कुछ माह पहले नवरात्रों में जब लोगों ने मंदिर को देखा तो कहा कि इसकी हालत कितनी बदतर कर दी गई है। माता हिमानी चामुण्डा जी का मंदिर हज़ारों फीट की ऊचांई पर स्थित है। किसी दानी सज्जन ने विकास में जन सहयोग योजना के तहत सोलर लाइट्स लगवाई तो आदेश दिए गए कि इन लाइट्स को काट दो। इस प्रकार से रिसोर्स मोबेलाइजेशन कैसे होगा? इसी प्रकार पालमपुर कृषि विश्वद्यालय की जमीन पर भी नज़र बनाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह जमीन, 'चांदी की तस्तरी पर कौड़ियों के भाव', किस को बेचने के लिए यह योजना बनाई जा रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अरली हियरिंग के लिए केस डाल दिया गया है और उसके लिए बड़े-बड़े वकीलों को लगाया गया है। मैं पालमपुर विधान सभा क्षेत्र

के माननीय विधायक से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजनीति की दीवारों को तोड़ कर अपने इलाके की बात करना चाहते हैं और आप भी पालमपुर के रोप-वे की बात कीजिए। इसी प्रकार माता हिमानी चामुण्डा जी के रोप-वे की बात कीजिए। यहां पर घोषणा की जाती है कि हम कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी अधिसूचना कहां पर है? बहुत सारे लोग होटल बनाने के लिए धारा-118 की अनुमति प्राप्त करने के लिए आपके (माननीय मंत्रिगणों को देखकर कहा) दफ्तरों के चक्कर काटते हैं।

01.09.2025/1700/वाई.के.-एन.जी./2

मैं बताना चाहता हूं कि बी0बी0एन0डी0ए0 के इलाके में 156 मामलों में सी0ओ0 ने ही change of land use कर दिया। इस विषय पर कभी प्रस्ताव आएगा और आप मुझे यदि चर्चा का समय देंगे तो मैं विस्तार में अपनी बात रखुंगा। यह घटना बद्दी-बरोटीवाला की है और ऑन रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। हमारे माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि एक अनुमति दी गई है और शेष के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। यह बात रिकॉर्ड पर आई हुई है। यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि क्यारी बंग्ला पर्यटन विभाग ने बनाया है। मुझे नहीं पता कि स्पैशल सेक्रेटरी टूरिज्म कौन हैं? उन्होंने एम0डी0 साहब को चिट्ठी लिख दी कि वर्ष 2021 में निविदाएं मांगी गई थी और श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने उन्हें कैंसिल कर दिया था, उन्हीं निविदाओं को कंटिन्यू किया जाए कि यह जो क्यारी घाट का होटल है, इसको हम पट्टे पर देना चाहते हैं। आपको कौन रोक रहा है कि आप कोई योजना लेकर आएं जिसमें जो सरकारी सम्पतियां या 10 होटल्स हैं, उन्हें लीज़ या पट्टे पर दिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट में फैसला लिया जाता है कि 10 सम्पतियों को पट्टे पर दिया जाएगा और पर्यटन विभाग के चेयरमैन कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कैसी सरकार है? मैंने कल अख़बार में पढ़ा कि 10 होटलों में,

जिसमें धर्मशाला का कश्मीर हाऊस भी शामिल है, बुकिंग्स बंद कर दी गई हैं। आप कोई योजना लेकर आइए और यदि वह प्रदेश के हित में होगी तो उस पर सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। आप योजना के तहत लेकर आइए कि सरकार घाटे में चल रही सम्पतियों को कुछ पैरामीटर्स पर 30-60-90 साल के लिए पट्टे पर देना चाहती है। आप इस पर हिम्मत कीजिए। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सम्पतियों को (***) से बेचने का काम किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को बेचना भी सहन नहीं करेंगे। मुख्य मंत्री जी के पास एक आई0टी0 एडवाइज़र हैं और

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

01.09.2025/1700/वाई.के.-एन.जी./3

पता नहीं वे कौन-सी दुनिया में रहते हैं? अगर टूरिज्म विलेज बनाना बहुत जरूरी है तो उसे चाय के बगिचों में बना दीजिए।

माननीय श्री आशीष बुटेल व इनके परिवार के पास चाय के बहुत सारे बगिचें हैं।...(व्यवधान) मैं इनके पीछे नहीं पड़ा हूं। यह हमारे साथी हैं और मैं एक सुझाव दे रहा हूं। सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री, श्री चन्द्र कुमार ने भी पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को टूरिज्म विलेज को न देने के लिए तार्किक रूप से अपनी बात रखी थी।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

01.9.32025/1705/PB-YK/1

श्री विपिन सिंह परमार...जारी

वर्ष 2024-25 में लगभग 1.80 करोड़ घरेलू पर्यटक और 83 हजार विदेशी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए हैं और ये संख्या कम हो रही है। ...(घण्टी) ऐसी स्थिति में प्रदेश का राजस्व कैसे बढ़ेगा? प्रदेश में होम-स्टे, इको-टूरिज्म और साहसिक पर्यटन पर कुछ-न-कुछ नवीन पहल की जानी चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सेहत को लॉटरी के माध्यम से ठीक करना चाहते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या लॉटरी के माध्यम से ठीक होगी? शानन हाइडल प्रोजैक्ट की 100 वर्षों की लीज़ अवधि समाप्त हो गई है। आपको पंजाब सरकार के समझ अपना पक्ष रखना चाहिए। उस प्रोजैक्ट में 110 मेगावाट बिजली तैयार होती है लेकिन हमें क्या मिलता है? हमें उसमें उत्पादित कुल बिजली का लगभग 500 किलोवाट ही प्राप्त होता है। हमें इसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी क्योंकि उस प्रोजैक्ट में हिमाचल प्रदेश का पानी और जमीन इस्तेमाल हो रही है। ऐसा करने से प्रदेश में अपने आप संसाधन बढ़ जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, स्कींइग और साहसिक गतिविधियां बढ़ाइए तथा आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन में अत्यधिक काम कीजिए। इसके साथ-साथ अपने व्यय कम भी कीजिए। यहां पर हमारे छोटे भाई केवल सिंह पठानिया जी ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया था कि अफसरों की गाड़ियां कम करनी चाहिए। उन्होंने यह अच्छी बात कही है क्योंकि हमेशा नज़रें नेताओं पर रहती हैं और अधिकारी जो मर्जी करें किसी का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। आप उनके लिए एक गाड़ी फिक्स कीजिए। विभागों में 10-12 प्रतिशत गाड़ियों को कट लगाइए। अधिकारियों की गाड़ियां घूमती रहती हैं लेकिन नज़रें नेताओं पर रहती हैं क्योंकि हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। अधिकारी कहते हैं कि हम तो सरकारों को देखते हैं कि पांच साल आप हैं और पांच साल कोई और होगा। उन्हें प्रमाण पत्र कोई नहीं देता लेकिन हमें देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि विभागों में गाड़ियां 12-13 प्रतिशत कम की कीजिए।

01.9.32025/1705/PB-YK/2

सभापति महोदय, जिन विभागों के दफ्तर किराए पर लिए गए हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित कीजिए जहां पर सरकारी भवन खाली पड़े हैं। इससे हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ा है वह कम होगा। प्रदेश के

घाटे में चल रहे उपक्रमों को बंद कीजिए। सभापति महोदय, मैं संक्षेप में कुछ और बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

Chairman : Please wind-up.

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, आप बहुत योग्य हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कुर्सी को सुशोभित करें। हमारे ज्वालामुखी और सुलह के क्षेत्र साथ-साथ में है और हमारा एक ही जिला कांगड़ा भी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 27 बोर्ड कॉरपोरेशन्ज में से लगभग 12 घाटे में चल रहे हैं। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बोर्ड 6454.47 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे हैं। सरकार इसके लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाती? विपक्ष के सभी सदस्यों से क्यों सुझाव नहीं लिए जाते? हिमाचल प्रदशे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में भी 3246.97 करोड़ रुपये का घाटा है, एच0आ0टी0सी0 में 1966.13 करोड़ रुपये का घाटा है और एच0पी0एम0सी0 की दुकानों में घोटाला हुआ है। प्रदेश में 91.20 करोड़ रुपये का डेफिसिट है और वित्त विभाग में 180.97 करोड़ रुपये का घाटा है। यानि वित्त विभाग ही बीमार है तो बाकी विभागों की क्या हालत होगी? वन विभाग में 10.42 करोड़ रुपये और पॉवर ट्रांसमिशन में 105.13 करोड़ रुपये का घाटा है। मैं ये सारे तथ्य इसलिए यहां पर रख रहा हूं ताकि आप इस बारे में विस्तार से योजना बनाएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस विषय में विस्तार से योजना बनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्बन क्रैडिट पर भी योजना बनाई जानी चाहिए। हमें ग्रीन कार्बन बेचने के लिए

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2025/1710/AG/AP/-01

श्री विपिन सिंह परमार जारी .....

वन संपदा के रूप में हम शुरू करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कई बार फील्ड में हम देखते हैं कि तहसीलदार साहब तो बहुत हैं लेकिन पटवारी की पोस्टें खाली पड़ी हैं। आपने बड़े-बड़े अधिकारों की फौज कर दी लेकिन उनको फील्ड का ज्ञान ही नहीं है। उन दफ्तरों में बैठकर प्रदेश की सेहत को ठीक करने के लिए अपनी कलम चलाते हैं परंतु धरातल पर जिसका जिक्र हमारे सभी साथियों ने किया, हमारे माननीय सदस्य श्री रणधीर जी ने भी कहा कि बिजली का विषय है ट्रांसफार्मर, एल.टी. लाइन बढ़ा दी गई, 33 के.वी. स्टेशन बढ़ा दिए गए, लेकिन फील्ड में वर्कर नहीं हैं। आप इनमें मित्र ही लगा दीजिए हमें इसमें कोई दुख नहीं है। मित्र लगाइए, प्रदेश की सेहत ठीक कीजिए यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि कैटेगरी-1 ऑफिसरों में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सभापति महोदय, अगर इसको रेशनलाइज करने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यह जो सुझाव मैंने आपको दिए हैं, इन सुझावों के माध्यम से अवश्य हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य सुधरेगा, सुधरेगा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश मजबूत होगा। शराब नीति पर हमने प्रश्न पूछा है उसका तो उत्तर ही नहीं आता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है क्या हो जाएगा? जो आपकी नीति थी उसको सार्वजनिक कीजिए। उस नीति से आपके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई उसे सार्वजनिक कीजिए। यह हिमाचल प्रदेश की सेहत के लिए अच्छा होगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो कमेटी आपने बनाई है उसमें हमारे भी सुझाव लीजिए ताकि आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन की स्ट्रैटेजी को तैयार करके आप इस माननीय सदन में प्रस्तुत करें। सभापति महोदय, अब मैं पोंग डैम की बात करना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी और मेरा एक ही जिला है। दो साल पहले जब पानी छोड़ा गया था उस समय मंड का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। उस समय इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तीन प्रतिशत के हिसाब से हमें फ्री बिजली मिलती है। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। हम यह चाहते हैं कि 12 प्रतिशत

01.09.2025/1710/AG/AP/-02

रॉयल्टी और 40 साल पूरा होने के बाद जो एम.ओ.यू. में प्रावधान किया गया है वह प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश में बैस्ट होनी चाहिए यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति : माननीय परमार साहब Please wind up.

श्री विपिन सिंह परमार सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार बहुत सहायता कर रही है। श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश की काफी सहायता कर रहे हैं। जैसे भारत सरकार की आयुष्मान योजना है... (व्यवधान) सुनिए ज़रा, आयुष्मान योजना में टांडा मेडिकल के लगभग 20 करोड़ रुपये पेंडिंग हैं। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप खैर-खबर हिमाचल प्रदेश की रखें। जो आदमी अपने उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहा है और हम सरकार और मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए हरियाणा का ज़िक्र कर रहे हैं यह इलाके के लोगों के साथ अन्याय है। यह अन्याय है और मैं अन्याय ही कहूंगा। सच्चाई की बात करिए, जो लंबित भुगतान हैं, उनको पूरा कीजिए।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2025/1715/AT/AG/01

श्री विपिन सिंह परमार जारी :

आजकल जब हम बिलासपुर जाते हैं तो वहां रेल के पिलर खड़े हैं लेकिन काम बंद पड़ा है। मैंने श्री त्रिलोक जामवाल जी से पता किया तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने जो पैसा जमा करवाना था वह जमा नहीं करवाया गया और भारत सरकार से आया पैसा कहीं और खर्च कर दिया गया। यह क्या हो रहा है? मैं निवेदन करता हूं कि हमारी योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। वातें तो बहुत हैं करने के लिए परन्तु मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एच0पी0पी0टी0सी0एल0 का कार्यालय हिमफेड की बिल्डिंग में 17 लाख में चलता था। लेकिन अब एच0पी0पी0टी0सी0एल0 ने भट्टा कुफर में

नया दफ्तर ले लिया है जिसका किराया भी लगभग 17 लाख है। ...(व्यवधान) यहां पर हमारे साथी और वरिष्ठ मंत्री श्री चंद्र कुमार जी , चोहान साहब, शिक्षा मंत्री आप इसको हंस कर नहीं टाल सकते। यह आखिर नजराना किसको पेश किया गया है? मैं इसका विरोध करता हूं। हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों के साथ धोखा हो रहा है और फिर कह रहे कि आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना है लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से लोग विरोध कर रहे हैं। यह कोई एक घटना नहीं है बल्कि कई घटनाएं हैं जहां मित्रों के सामने तोहफे पेश किए जा रहे हैं।

Chairman: Please wind-up.

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, जब मैं स्पीकर था, तब करोना की आपदा आई थी। तब हम कहीं बाहर नहीं जा सके परन्तु मैं और श्रीमान हंस राज जी एक साथ एक प्रिजाइडिंग ऑफीसर सम्मेलन में सरदार सरोवर डैम देखने गए थे। वहां देखा कि किस तरह पर्यटन बढ़ाने के लिए टेंट विलेज बनाए गए, राफ्टिंग हो रही थी, बर्मा ब्रिज बने थे और लोकल व्यंजन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा परोसे गए। अगर टुरिजम बढ़ाना है तो यहां से एक कमेटी को वहां भेजी। जब हमें वहां के गांव में घुमाया गया तो वहां के हमें लोकल व्यंजन खिलाए गये। मैं कहना चाहता हूं कि बी0बी0एम0बी0 (BBMB) की खाली पड़ी जमीन पर भी हम ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बना सकते? इससे हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा। अब ये गाड़ी उतराई की ओर है और मेरे यह सुझावों

01.09.2025/1715/AT/AG/02

का आप आदर करिये और नर्मदा डैम की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई थी। एक पर्यावरणविद ने कहा था कि इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन आज वह ट्राइबल जिला खुशहाल है और वहीं सरदार वल्लभभाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है जहां करोड़ों लोग पर्यटन के लिए आते हैं। वहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं।

इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी सोच और योजनाएँ लागू की जाएं परंतु एच0पी0पी0टी0सी0एल0 का जो मामला है उसमें एक नौजवान चीफ इंजीनियर की मृत्यु भी हुई है और (***)

Chairman: Parmar ji, Please wind-up. आपने वहुत समय ले लिया है ।

श्री विपिन सिंह परमार : मैं उनका नाम ले रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि वाइंड अप कर दीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को न्याय दिलाना है और यहां की संपदा को कुछ लोग लूट न सकें। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अनगिनत सहायता दी है चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो। इसलिए इस सहायता और संपदा का सही उपयोग होना चाहिए।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

एम0डी0द्वारा जारी....

01-09-2025/1720/AS/MD/1

श्री विपिन सिंह परमार---जारी :

सभापति महोदय, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को असीम सहयोग दिया है, चाहे वह सड़क अवसंरचना हो, स्वास्थ्य संस्थान हों, वाइब्रेंट विलेज योजना हो,एन0डी0आर0एफ0 और सी0आर0एफ0 की सहायता हो, या फिर नाबार्ड जैसी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग हो। इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार को सदैव केंद्र सरकार का ऋणी होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि यहां से कभी इसकी सराहना के शब्द सुनाई नहीं देते। मैं संसाधन जुटाने के संदर्भ में सुझाव देना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग के साथ-साथ यदि हमसे भी राय ली जाए तो हम उपयोगी सुझाव दे सकते हैं। राज्य को संसाधन जुटाने की दिशा में और गंभीर प्रयास करने होंगे। हिमाचल प्रदेश वह भूमि है जहां से डॉ0 वाई0एस0 परमार जी ने विकास की नींव रखी। उनके बाद ठाकुर रामलाल जी ने इसे आगे बढ़ाया। स्वर्गीय

श्री वीरभद्र सिंह जी ने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रदेश के लिए कार्य किया। श्री शांता कुमार जी ने जल के क्षेत्र में योगदान दिया, श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने सड़क निर्माण पर बल दिया, और श्री जय राम ठाकुर जी ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। लेकिन, विश्वविद्यालय के मित्रों, आपने हिमाचल प्रदेश को "डेब्ट ट्रैप" में डाल दिया है। अब इसे बाहर निकालना समय की मांग है। मैं निवेदन करता हूं कि प्रशंसा उतनी ही कीजिए, जितनी जनता को स्वाभाविक और सच्ची लगे। बनावटी फूल कभी खुशबू नहीं देते, खुशबू केवल प्राकृतिक फूलों में होती है। हम प्राकृतिक हैं, आप बनावटी हैं। आप मजबूर हैं, और हम मजबूत हैं।सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

01-09-2025/1720/AS/MD/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय कृषि मंत्री जी भाग लेंगे।

कृषि मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने बहुत सी अच्छी बातें रखी हैं और कहा कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हिमाचल प्रदेश को काफी धनराशि भेजी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार ने पहले भी 90 प्रतिशत ग्रांट और 10 प्रतिशत लोन के आधार पर स्वीकृत किया है। जब हमारी सरकार थी, तब राजीव गांधीवित्तीयकरण योजना के तहत भी 90 प्रतिशत ग्रांट और 10 प्रतिशत लोन के रूप में धन मिला। आज दूर-दराज के इलाकों में जो बिजली के पोल, कंडक्टर और ट्रांसफार्मर आप देखते हैं वह सब इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आया। शाह नहर, सिद्धाथा नहर, भघौर साहब जैसी कई बड़ी परियोजनाओं को भी भारत सरकार ने इसी पैटर्न पर स्वीकृत किया था। जब मैं इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर था, तब नाबार्ड से 3—4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेकर हजारों ट्यूबवेल लगाए गए, कई नहरों के लिए फंड उपलब्ध कराए गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे 60-40 प्रतिशत हो या 90-10 प्रतिशत भारत सरकार की अलग-अलग योजनाओं में ऐसे प्रावधान पहले भी होते आए हैं। अतः यह कोई असाधारण या नई बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं धन्यवाद।

श्रीमती के0एस0 जारी -----

01.09.2025/1725/केएस/एएस/1

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी भाग लेंगे।

श्री आशीष बुटेल : सभापति महोदय, यह सच है कि प्रदेश आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है और आज नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव श्री केवल सिंह पठानिया जी लाए हैं, यह शायद आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी भी हो जाता है । जिस तरह से हमारे राज्य के इन्कम के साधन बहुत कम होते दिखाई दे रहे हैं लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो आज रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जहां बात आए उसके साथ-साथ optimum utilization of resources की भी बात की जाए। मुझसे पहले माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने यहां पर अपना वक्तव्य रखा। मैं इनके भाषण का बहुत मुरीद हूं। कहां से शुरू हुआ और कहां पर आ कर वह भाषण खत्म हुआ और जिस-जिस को इन्होंने लपेटना था, उसमें हमारे समेत इन्होंने सभी को लपेट लिया। परमार साहब, वाकई में आपसे यह कला सीखनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुज़र रहा है लेकिन इसमें केवल इन ढाई सालों का ही नहीं, पिछले पांच साल रही सरकार की भी उतनी ही योगदान है। विपक्ष हम पर यह जिम्मेवारी थोपने की ज़रूर कोशिश कर रहा है लेकिन जनता सब कुछ जानती है। जब आप लोग यहां से गए थे उस समय हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में जनता जानती है। मैं किसी सरकार को यह नहीं कहूंगा कि आपने जो लोन लिया, उसका कुछ नहीं किया या वह पैसा आपने बर्बाद कर दिया। सभापति महोदय, सबकी अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और अगर देखा जाए तो केवल हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही लोन नहीं है। 2024-25 के बजट एस्टिमेट्स के अनुसार केंद्र सरकार के ऊपर भी आज 180 लाख करोड़ रुपये से ऊपर का ऋण है। वे भी चलो डवलपमेंट में ही लगा रहे हैं और जैसा विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार को भी कुछ पैसा दे रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश की हालत यह हो गई है कि एक तो आर्थिक संकट ऊपर से आपदा। तो

गरीबी में आटा गीला वाली कहावत यहां पर ठीक बैठती है। किस तरह से हिमाचल प्रदेश के हित को बचा कर रखना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा।

01.09.2025/1725/केएस/एएस/1

सभापति महोदय, अभी परमार साहब ने भी यहां पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि पूंजीगत व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार का फिस्कल डेफिसिट आज 10,337 करोड़ रुपये तक पहुंचा है उसके लिए आज की सरकार ही जिम्मेवार नहीं है। पिछली सरकारें भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी आज की सरकार होगी। अगर आप देखें तो जो सार्वजनिक ऋण की लोन की रीपेमेंट है, लगभग 10 रुपये तो वही है। जनरल सर्विसिज़ और सोशल सर्विसिज़ जिनके अंदर आपकी सैलरी और पैंशन भी आती है वह 100 रुपये में से 70 रुपये के लगभग है। अगर देखा जाए तो कोई नए एसेट्स जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वे 100 रुपये में से सिर्फ 7 रुपये के कैपिटल एसेट्स हम यहा पर क्रिएट कर रहे हैं जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आज हम सभी को इस प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्सड इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक मिश्रण है जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी इंवेस्टमैंट करता है परंतु समाजवादी राज्य के साथ-साथ हम लोग वैल्फेयर स्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं। हमें लोगों और उनके हितों के लिए भी काम करना ज़रूरी है लेकिन शायद अब वह समय है कि जब हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

01.09.2025/1730/AV/dc/1

श्री आशीष बुटेल------ जारी

एक समय था जब हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना तो उस समय शायद मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं होती थीं। समय बदला और सरकारें आईं। यहां पर अभी जैसे माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार कह रहे थे कि किसी मुख्य मंत्री ने पानी के ऊपर काम किया और किसी ने सड़क व बिजली के लिए काम किया। लेकिन धीरे-धीरे करके आज हमारी स्थिति उस समय की तुलना में बहुत बेहतर हुई है। पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, मैं यह मानता हूं और ऐसा कहना भी चाहता हूं। मूलभूत सुविधाएं देना तो सरकार की प्राथमिकता है ही, परंतु बहुत सारे स्थान ऐसे भी हैं जहां पर हमने मूलभूत सुविधाएं पूरी भी की हैं। मैं कह सकता हूं कि सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन सुविधाएं इत्यादि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली प्राथमिकताएं हैं। परंतु प्रश्न यह है कि ये सुविधाएं सरकार द्वारा कहां तक दी जानी चाहिए। हमें इन मूलभूत सुविधाओं को आगे लेकर कहां तक जाना है, हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न यह है।

सभापति महोदय, अब यह भी जरूरी हो गया है कि हम इस प्रकार के कदम उठाएं जिनसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए एक पोलिटिकल विल की आवश्यकता होती है। यहां पर जो हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, I think they should watch the larger interest of the State. इसी तरह से हमने अपनी सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के अंदर, जैसे यहां पर माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया ने वॉटर सैस, वाइल्ड फ्लावर हॉल, सोलर प्लांट्स इत्यादि के बारे में बताया है। हमारी सरकार ने इन सब पर काम किया है कि हम किस तरीके से अपने रिर्सोसिज को और अच्छे तरीके से मोबलाइज करें और उनका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकें।

मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार का काम बिजनैस करना नहीं होता। मेरी समझ के अनुसार बहुत सारी कॉर्पोरेशन्ज ऐसी हैं जोकि बिजनैस करने के लिए खोली गई थीं। ठीक है, जहां तक उनकी आवश्यकता हैं, वे वहां तक चलें। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजनैस करने के लिए नहीं बैठी है। अगर सरकार को किसी कॉर्पोरेशन को चलाना है और वह लॉस में भी जा रही है परंतु हमें चलाना पड़ रहा है। हम यह भी देख रहे हैं कि जहां-जहां पर भी हम ऑस्टेरिटी मैजर्स

01.09.2025/1730/AV/dc/2

लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारी कॉर्पोरेशन्ज ऐसी हैं जैसे अभी माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार भी कह रहे थे कि वे लॉस में चल रही हैं। हमें उनके बारे में सोच-विचार करना पड़ेगा। हमें जहां पर ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेशन हमारी अपनी ही आमदनी में से कुछ खा रही है तो शायद उनको बंद भी करना पड़ सकता है। हम जो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछली सरकार ने जाते-जाते जगह-जगह पर स्कूल व कॉलेज खोल दिए थे, वहां पर बच्चा चाहे एक भी न हो। ...(व्यवधान) हमारे मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री ने जब यह देखा कि कई स्कूल्ज में एक भी बच्चा नहीं है तो इन्होंने इस तरह के 600 स्कूल्ज बंद करने का निर्णय लिया। आपने कहा कि ये स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि रिसोर्स मोबलाइजेशन क्या होता है? आपने उस टीचर की सैलरी देनी है जहां पर एक भी बच्चा नहीं है, उसकी सैलरी तो हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है तो वह टीचर क्यों न ऐसे स्कूल में जाए जहां पर बच्चे भी हों। आज तक केवल क्वांटिटी की बात की जाती रही है कि इस गांव में स्कूल खोल दो, उस गांव में खोल दो मगर क्वालिटी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी की वजह से आज प्रत्येक गांव में सरकारी स्कूल है लेकिन बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने शायद यह सुनिश्चित नहीं किया कि जो सुविधाएं बच्चों को प्राइवेट स्कूल्ज में मिल रही हैं वे आप उनको सरकारी स्कूल्ज में दें। हमारे पिताजी के समय में एक स्कूल पालमपुर के अंदर होता था। उसके बाद कॉलेज जालन्धर और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए लाहौर या दिल्ली जाना पड़ता था। उससे बच्चों को एक्सपोज़र भी मिलता था। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि हर जगह पर स्कूल या स्वास्थ्य संस्थान न हो।

टी सी द्वारा जारी

01.09.2025/1735/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री आशीष बुटेल.. जारी

लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें एक्स्पोज़र कहां दे रहे हैं और उन्हें तैयार कहां कर रहे हैं यानी हमें यह तय करना होगा कि दुनिया के साथ जंग लड़ने के लिए हम अपने बच्चों को कहां तैयार कर रहे हैं? इस विषय को हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। जहां तक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सवाल है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को बंद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। मुख्य मंत्री जी, आपको और मंत्रिमंडल के सभी साथियों को प्रदेश-हित में कठिन और कड़े निर्णय लेने होंगे।

आप लॉटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। पिछली सरकार ने हम 5-6 लोगों को सिक्किम राज्य का मॉडल देखने के लिए सिक्किम भेजा था। लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री राकेश जम्वाल जी और मैं श्री राकेश पठानिया जी की अध्यक्षता में सिक्किम राज्य में गए थे। वहां से जो रिकमेंडेशन आई वह यह थी कि हिमाचल प्रदेश को भी लॉटरी और केसिनो खोलने चाहिए। सिक्किम में केसिनो हैं लेकिन वहां का कोई प्रदेशवासी उसमें नहीं जा सकता। केवल टूरिस्ट आधार कार्ड बेस्ड एंट्री से जा सकते हैं। अगर हिमाचल में भी ऐसा होता है और आमदनी किसी और प्रदेश के व्यक्ति से बढ़ती है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है तो वह तो चलता ही रहेगा।

सभापति महोदय,मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरह की चोरी, चाहे बिजली की हो, टैक्स की हो या किसी अन्य प्रकार की, प्रदेश-हित में नहीं है, उस पर ठोस कदम उठाने होंगे। तभी रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकेगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टर्स के लिए सरल व्यवस्था लागू करनी होगी। प्रदेश की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके लिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा । माननीय सदस्य श्री केवल सिंह जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 68 प्रतिशत क्षेत्र फॉरेस्ट से आच्छादित है लेकिन इतने बड़े फॉरेस्ट कवर से हमें कुल इनकम का केवल 5 से 6 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। क्यों न हम इसे और बढ़ाएं। हमारे पेड़ गिर जाते हैं, सड़ने के

01.09.2025/1735/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

लिए छोड़ दिए जाते हैं। हम जंगल से कोई उत्पाद निकालना चाहें तो परमिट नहीं मिलता और इतनी सख्ती होती है कि फॉरेस्ट से आमदनी ही नहीं हो पाती। हाल ही में एक एन0जी0ओ0 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर फॉरेस्ट सैक्टर को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाए तो 8000 करोड़ रुपये तक की इकॉनमी बढ़ाई जा सकती है। 8000 करोड़ रुपये कोई छोटी राशि नहीं है। इसको हम टूरिज्म और वनों में सड़े-गले स्टंप्स के उपयोग से सकते हैं। आज हम कहते हैं पॉपलर का पेड़ लगाओ और 10 वर्ष बाद काटो लेकिन 10 वर्ष बाद यह सुनिश्चित नहीं होता कि सरकार काटने की अनुमति देगी या नहीं। यह जो अनसर्टेनिटी है, हमें इसे समाप्त करना पड़ेगा।

माननीय सदस्य श्री केवल सिंह जी ने आई0टी0 सैक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज, हैल्थ सैक्टर और वैलनेस सेक्टर की बात पहले ही कर दी है। परमार साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पालमपुर और वहां के टी-टूरिज्म की चर्चा की।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा.... जारी

01-09-2025/1740/NS-HK/1

श्री आशीष बुटेल ----जारी

मेरा मानना है कि बीड़ से लेकर धर्मशाला, शाहपुर का जो एरिया है वहां चाय की पैदावार होती है और सिर्फ इतने से इलाके के अंदर हम 3,000 करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट दो वर्षों के भीतर ला सकते हैं अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे।

सभापति महोदय, हम एच0पी0टी0डी0सी0 की बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एच0पी0टी0डी0सी0 एक कॉरपोरेशन है और मुझे ऐसा बताया गया है कि अब यह प्रोफिट में चल रहा है, मुझे इस बात का पूरा ज्ञान तो नहीं है पर बताया गया है कि यह प्रोफिट में बहुत वर्षों के बाद आया है। इसमें एक बात सोचने वाली है। उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस कॉरपोरेशन का पैसा बर्बाद किया है। अगर हम कोई होटल बनाते हैं और जब

वह नहीं चलता है तो उसको बंद कर देते हैं। हमारे पास इसका उदाहरण शिमला से पालमपुर जाते हुए रास्ते में देखने को मिलता है। वहां पर कम-से-कम तीन जगहें ऐसे होटल्ज हैं जो खाली पड़े हुए हैं और उनको बंद कर दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि उन लोगों को गंभीर होना पड़ेगा जो ये पॉलिसी बनाते हैं। यह नहीं होना चाहिए कि आशीष बुटेल के पास आज इतनी पॉवर है कि अगर कहीं पर एक होटल बनाए तो उस जगह पर बना दे जहां का वह विधायक है। वोट की राजनीति के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सरकार व जनता का पैसा है और यह ठीक जगह पर लगना चाहिए तथा हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसैसिंग इण्डस्ट्री बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है। इसके ऊपर मंत्री जी ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं फ्लोरिकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में फ्लोरिकल्चर बहुत अच्छा बिजनैस पहले भी रहा है। अगर इसको हम और एक्सपैंड करने के लिए हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। हमारी मार्केटिंग अच्छी हो। मेरे ध्यान में दो फैक्टरीज हैं। एक हमारी नाहन की फाउंडरी बंद हो गई है और बटाला में वही लोग सेम डिजाइन को बेच कर हिमाचल प्रदेश में पैसा कमा रहे हैं। सिल्क की इण्डस्ट्री नूरपुर में होती थी और वह भी बंद पड़ी हुई है क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।

01-09-2025/1740/NS-HK/2

सभापति महोदय, हमें सरकारी भवनों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात ठीक है कि जहां जरूरी है वहां करना पड़ेगा। लेकिन जहां जरूरत नहीं है तो हम सरकारी भवनों के ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों करें? हम 2-3 करोड़ रुपये के भवन बना देते हैं और वहां पर बैठने वाले 10 आदमी होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि विशेष तौर पर अगर ये सब पी0पी0पी0 मोड पर बने तो सही रहेगा। मैं विपक्ष के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि हम लोग तो कह रहे हैं लेकिन शहरी विकास मंत्री जी से भी वे लोग मिले हैं। एन0बी0सी0सी0 केंद्र सरकार की एक कॉरपोरेशन है जो बिल्डिंग बनाने का काम करती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के लिए घर बनाने थे। उन्होंने एक होटल को 6

एक्कड़ जमीन दी। मान लीजिए अगर वहां पर 15 एक्कड़ की कोई जमीन थी तो उसमें से केंद्र सरकार की कॉरपोरेशन एन0बी0सी0सी0 ने एक होटल बनाने के लिए 6 एक्कड़ जमीन दी। उस जमीन से जो पैसा आया तो वहां पर आज उस पैसे से अधिकारियों के फ्लैट बने हुए हैं। यह मोतीबाग और आर0के0पुरम के पास लीला बाग होटल के पास फ्लैट बने हुए हैं। आप भी ऐसी पॉलिसी ला सकते हैं। यह बात ठीक है कि सरकार अपना पैसा क्यों लगाए? इससे लैंड पुलिंग भी नहीं होगी। अगर हम इस पर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से और हम सब जितने भी विधायक यहां बैठे हैं तो हम सबके योगदान से इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे कहा गया है कि हम हिमाचल प्रदेश को कुछ वर्षों के अंदर नम्बर वन स्टेट बनाने की कोशिश में है तो उसमें आप सबका भी साथ चाहिए होगा।

सभापति महोदय, यहां पर टूरिज्म विलेज की बात की गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह चर्चा रोज होती है कि टूरिज्म विलेज पालमपुर में हो या न हो और कहां पर हो, किसकी जमीन पर हो? मैं कहना चाहता हूं कि एक बार इकट्ठे होकर सब बैठ जाते हैं और उसके ऊपर चर्चा कर लें। हो सकता है कि मुझे ऐसा लगे कि ऐसा होना चाहिए और किसी और को कुछ और लगे। हम लोग बैठ कर उसके प्रोस एंड कोन्स तो देखें। ...(व्यवधान) देखिए, अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की चर्चा बार-बार नहीं होगी तो विपक्ष के सुझावों को हम कैसे इनकॉरपोरेट करेंगे? आप अच्छे सुझाव देंगे तो हम उनको इसमें शामिल करेंगे और आप सबको इस चर्चा में जरूर भाग लेना चाहिए क्योंकि यह हमारे प्रदेश की बात है, आगे आने वाली पीढ़ियों की बात है। सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, जय हिंद। सभापति महोदय ......आर0के0एस0 द्वारा----जारी

01.09.2025/1745/RKS/HK-1

सभापति : मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिक और भाजपा की ओर से कम सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने के लिए अपने नाम दिए हैं। इसलिए मैं 2:1 के अनुपात में बोलने का अवसर दे रहा हूं। अब माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी ने नियम-130 के अंतर्गत संसाधन जुटाने जैसे एक महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इस विषय पर 10-15 बिंदुओं में अपनी बात रखना चाहूंगा। मुझसे पहले इस विषय पर माननीय विपिन सिंह परमार, श्री आशीष बुटेल, और श्री केवल सिंह पठानिया जी ने अपने-अपने विचार रखे हैं। अगर मैं टूरिज्म क्षेत्र की बात करूं तो परवाणू से सोलन तक के एरियाज के में हर शनिवार और रविवार को निचले क्षेत्रों से हज़ारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। ये लोग अक्सर सड़कों पर शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर नदी का किनारा भी है और वे लोग वहां खूब आनंद लेते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार वहां स्थानीय बेरोज़गार युवाओं को 5-5 या 10-10 बिस्वा भूमि अलॉट करे ताकि वे वहां छोटी-छोटी हट्स, ढाबे या रेस्टोरेंट खोल सके। इसमें यह भी तय किया जाए कि इनसे होने वाली आय का एक निश्चित प्रतिशत सरकार को मिले। इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और युवाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। परवाणू में टूरिज्म का शिवालिक होटल काफी समय से बंद पड़ा है। पहले यहां HRTC की बसें रुकती थीं लेकिन अब वहां कोई बस नहीं रुकती है। यहां का चाय ढाबा और मुख्य रेस्टोरेंट दोनों ही बंद पड़े हैं। यदि इसे फिर से चालू किया जाए तो इससे सरकार को अच्छी आमदनी हो सकती है। मैंने माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जी को सुझाव दिया था कि नानकपुर से ऊपर कालूझंडा पंचायत जहां अटल शिक्षा कुंज है, वहां से कसौली तक रोपवे की व्यवस्था की जाए। इससे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। पर्यटक यहां आकर सड़कों पर शराब पीते हैं और चले जाते हैं। यदि वहां एक बड़ा होटल और 1,000 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम हो जाए तो यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकता है। इस रोपवे से कसौली तक के एरिया में जो होम स्टे बने हैं वे भी अच्छे से चलेंगे जिससे सरकार को भी काफी राजस्व प्राप्त होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो शाही क्षेत्र का रोड बना है वह बहुत मशहूर है। वहां की हवा बहुत शुद्ध है। जब वर्ष 2012 से 2017 तक

01.09.2025/1745/RKS/HK-2

कांग्रेस सरकार थी तब स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस सड़क को रामशहर से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए थे। यह रोड बहुत सुंदर है। मैं चाहूंगा कि

सरकार ऐसे प्वाइंट्स को चिन्हित करे ताकि वहां पर्यटक जा सके। बद्दी एरिया में लगभग 4-5 लाख लोग रहते हैं लेकिन उनके लिए आउटिंग का कोई बढ़िया स्थान नहीं है। अगर यहां किसी स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो यह लोगों के लिए भी अच्छा होगा और सरकार को भी इससे काफी राजस्व प्राप्त होगा। हमने BBND के माध्यम से चंडीगढ़ क्लब की तर्ज पर एक होटल बनाया था। इसमें 17 हट्स और 2 ए0सी0 हॉल्स बनाए गए थे जिनमें 1,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। हमारी मंशा थी कि इसको चंडीगढ़ क्लब की तरह विकसित करें जिसमें इंडस्ट्री के लोग 50 हजार या 1 लाख रुपये की फीस देकर सदस्य बनें ताकि BBND को आमदनी हो। लेकिन पिछली सरकार ने इस होटल को औने-पौने दामों पर किसी व्यक्ति को 10 साल के लिए लीज पर दे दिया। इस पूरी योजना को भी इन्होंने खराब कर दिया है। आज प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति दयनीय है उसके पीछे पिछली सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि मेरे और श्री हरदीप सिंह बावा जी के क्षेत्र में लगभग 5,000 बीघा जमीन सरकार ने बिना कोई राजस्व लिए मात्र 1 रुपये में आबंटित कर दी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2025/1750/बी.एस./वाई.के.-1

श्री राम कुमार जारी...

लगभग 5,000 बीघा जमीन इस सरकार ने बिना कोई रेवेन्यू लिए मात्र एक रुपये में अलॉट किया। एक एम्युशन की फैक्ट्री बननी थी उसको लखनपुर बखेड़ा में जमीन दी गई। मैं एक इंडो फार्म की बार-बार बात करता हूं जिसको डेढ़ सौ बीघा जमीन का पैच जो हमारी रत्ता नदी है वहां पर 250 रुपये में आबंटित किया गया और 160 बीघा जमीन कृपालपुर में उसको दी गई। अगर उस जमीन की बाजारी कीमत देखें तो वह जमीन लगभग 1.50 करोड़ रुपये जो हमारा मलकू माजरा का एरिया वह है। मैं हाउस के माध्यम से, आपके

माध्यम से मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वह इंडो फार्म जमीन सरकारी जमीन है उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए अलॉट की गई थी लेकिन आज वह इंडस्ट्री न लगा करके उस जमीन को बाजार में 10,000 रुपये प्रति मीटर बेच रहा है और उसकी बाजारी कीमत लगभग 15,000 रुपये प्रति मीटर है और जो हमारे लोकल आदमी हैं वे इस रेट पर इसे लेने के लिए तैयार है। यदि इसके छोटे-छोटे प्लॉट्स बनाए जाएं तो लोग लेने के तैयार बैठे हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी किया है कि जो सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का जमीन घोटाला है इसकी इंक्वारी भी मार्क की जाए, इसकी एक कमेटी गठित हो और जो इस जमीन में लगभग एक अरब रुपए की स्टांप ड्यूटी चोरी हुई है उसकी भी रिकवरी उन लोगों से की जाए। उनको डर इस चीज का है कि अगर सरकार ने जमीन के आबंटन को रद्द कर दिया तो जो हमारी सेटिंग्स हुई है वह सेटिंग हमें वापस करनी पड़ेगी इसीलिए लोग घबरा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि 10 साल के लिए उस जमीन में इंडस्ट्री लगाने के लिए उन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिजली तीन रुपये पर यूनिट देनी पड़ेगी। उनको ऐसी-ऐसी सुविधाएं विशेष तौर पर थाली में परोस कर दी गई थी। सभापति महोदय, इस चीज की जरूरत तब होनी थी जब यह औद्योगिक क्षेत्र बसने जा रहा था। वहां वर्ष 1984 और 1990 में इंडस्ट्री लगी उसके बाद 2002 में इंडस्ट्रियल पैकेज आया उसके बाद लगभग 2000 इंडस्ट्रीज वहां स्थापित हो गई और उसके बाद यह पैकेज दिया गया।

सभापति महोदय, एक और विशेष बात में कहना चाहता हूं कि इनको समय सीमा तय की गई थी उस समय सीमा में इनको उद्योग लगाने थे। उस समय सीमा में आज तक

01.09.2025/1750/बी.एस./वाई.के.-2

वे उद्योग नहीं लगें हैं। मेरा निवेदन है कि जिसने जितनी जगह में उद्योग लगाए हैं उसको छोड़ कर बाकी जमीन का समझौता रद्द करके उसको बाजार में बेचा जाए लगभग 5000 एप्लीकेशन हमारे उद्योग विभाग के पास हमारे इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों की हैं और ये सारी पेंडिंग पड़ी है। मैं समझता हूं 1000 करोड़ रुपये के लगभग सरकार को इस जमीन से रेवेन्यू आएगा।

दूसरा, सैटलाइट टाउन जिसकी मुख्य मंत्री जी से काफी दिनों से मैं चर्चा कर रहा था कि बद्दी में लगभग एक 1000 बसों के माध्यम से और हजारों लोग जो चंडीगढ़ पंचकुला, जीरकपुर और मोहाली से हमारे यहां काम करने आते हैं अगर वहां पर हमें सैटलाइट टाउन बसाते हैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने अपना नोट दिया है, तीन मंत्री और मुझे भी उसमें मेंबर बनाया गया है उसके माध्यम से जमीन की संभावना तलाशने के लिए अभी हमने विजिट किया और अभी 28 तारीख को उसकी मीटिंग भी हमने विधान सभा परिषद में की जिसके माध्यम से मुख्य मंत्री का मैसेज था कि लगभग 10,000 बीघा जमीन का अरेंज हो ताकि हम चंडीगढ़ की तर्ज पर बड़ा सैटलाइट टाउन बना सकें। मैं बताना चाहूंगा कि इसका प्रबंध मैंने कर दिया है, जमीन तलाश ली है और उसको पी.पी.पी. मोड पर जैसे पंजाब में हमारे जमीदारों के साथ लैंड पूलिंग के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को सरकार 6 महीने के अंदर अगर करती है तो हजारों करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू आएगा। क्योंकि इसमें हमारा जो जंगल का एरिया है वह पंजाब के साथ लगता है उसमें भी लगभग 3-4 हजार बीघा जमीन हमें मिलेगी और उसकी किस्म भी शामलात है, जंगल उसकी किस्म नहीं है उसको हम आबंटित कर सकते हैं।

माननीय धर्माणी जी से निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्र अमली जमा जहनाए जाने के लिए आप एक मीटिंग या एक विजिट अवश्य करें, आदरणीय नेगी जी वहां पर जा कर आए हैं, आप और आदरणीय विक्रमादित्य जी अभी नहीं आए। आप कृपया सेशन के बाद इसके टूअर की डेट फिक्स करें। ताकि इसको हम अमली जमा पहना सकें।

दूसरा, सभापति महोदय, जैसे आदरणीय बुटेल साहब ने बात की कि बद्दी में टैक्स की बहुत बड़ी चोरी हो रही है। उसमें मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि सिगरेट के ऊपर लगभग एक साल का 3-5 करोड़ रुपया केवल सिगरेट के ऊपर टैक्स की चोरी है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक उड़नदस्ता बनाया जाए।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

1.9.2025/1755/डी0टी0/वाई के0-1

श्री राम कुमार जारी....

जो ब्रांडेड सिगरेट है बिना किसी चेकिंग के सरेआम बिकती है। हमारे क्षेत्र में कई दुकानें जाहं पर यह ब्रांडेड सिगरेट मिलती हैं। इसकी बारे में मैंने एक्साइज कमिशनर के साथ चर्चा भी की थी। उन्होंने इस संबंध में अपने सबऑरडिनेट अधिकारियों को निर्देश तो दिए हैं लेकिन अगर सरकार इस तरह के मामलों पर रोक लगाना चाहती है तो नालागढ़-बद्दी-बरोटीवाला क्षेत्र में एक्साइज का एक स्पैशल सैल बनाने की आवश्यकता है और अगर ऐसा होता है तो सरकार को कई करोड़ों रुपये की सालाना इंकम प्राप्त होगी और प्रदेश मे टेक्स चोरी के मामले भी कम हो जाएंगे।

ई0सैटेलाइट टाउन, जो मुख्य मंत्री जी का एक कांसेप्ट है और मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है इसके लिए यह जरूरी है कि ट्राई सीटि पंचकुला-चण्डीगढ़-मोहाली के साथ हिमाचल प्रदेश के सीमावर्तीय क्षेत्रों को मेट्रो से जोड़ने का का प्रपोशल केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए, इससे भी प्रदेश सरकार की आय में इजाफा होगा।

बद्दी को मैं प्रदेश की फाइनेंशियल सिटि कहूंगा। जैसा माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी ने भी कहा कि फार्मा उद्योगों से प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की आय हाती है, यह बात ठीक है। लेकिन फार्मा के साथ मेरे क्षेत्र में जो अन्य इंडस्ट्रीज लगी हैं उनमें उत्पादित प्रोडक्टस के हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं और फार्मा के हम कंज्यूमिंग स्टेट नहीं हैं। फार्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य इंडस्ट्रीज जो वहां लगी हैं उनमें कोई गत्ता बना रहा है, कोई बोतल के ढक्कन बना रहा है, कोई रेपर बना रहा है, कोई बोतल बना रहा है, इन उद्योगों से भी प्रदेश को 100 प्रतिशत टेक्स मिलता है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2022-2023 में केवल बद्दी क्षेत्र से ही, इसमें नालागढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, एक्साइज के रूप में जो सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है वह वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 756 करोड़ रुपया और वर्ष 2024-2025 में 693 करोड़ रुपया और वित्तीय वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही में तक ही 113 करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त हो चुका है। जी0एस0टी0 जो केंद्र सरकार नहीं दे रही उसकी लड़ाई तो हमारी केंद्र सरकार से है, लेकिन इंडस्ट्रीज के बारे में यह कहना कि इनसे

1.9.2025/1755/डी0टी0/वाई के0-2

प्रदेश को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, इस बात से मैं असहमत हूं। लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बद्दी में लगे उद्योग रोजगार दे रहे हैं। हमारे दो निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 10000 ट्रक्स हैं। एक ट्रक के द्वारा लगभग 10 परिवार का भरण-पोषण होता है, इसमें कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई टायर पंक्चर वाला है, कोई ढाबा चलाने वाला है, कोई गाड़ियों के स्पेयर पार्टस बेचने वाला है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट से ये चेन जुड़ी हुई हैं। हमारे क्षेत्र के गांवों में जो छोटे-से-छोटा परिवार है उन परिवारों की भी मासिक कमाई 15 से 20 हजार रुपये के लगभग है और वह इसलिए है कि इन क्षेत्रों के उद्योगों में काम कर रहे लोग इनसे मकान किराए पर लेते हैं और इन्हीं मकानों में रहने वाले लोगों को वहां के स्थानीय किसान दूध, सब्जी आदी बेचकर भी अपनी इंकम कमाते हैं। मैं कह सकता हूं इस तरह वहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारा विद्युत विभाग जिसका लगभग 8000 करोड़ का टर्नओवर रहता है और इस टर्नओवर में से लगभग 2000 करोड़ रुपये का राजस्व इस विभाग को केवल बद्दी से ही प्राप्त होता है। हम यह बिजली जिन बाहर के राज्यों को बेचते हैं उन राज्यों ने अभी तक पिछला भुगतान नहीं किया है।

मैं एस0वाई0एल0 जो वर्तमान में बंद पड़ी है क्योंकि पंजाब उसका पानी हमारे प्रदेश के लिए निकलने नहीं दे रहा, माननीय मुख्य जी इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले ही माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने गये थे तो उस समय मैं भी उनके साथ था। उनके साथ वाटर सैस पर बात हो रही थी, मैंने अपना सुझाव वहां पर दिया था आज वही सुझाव मैं इस माननीय सदन में भी दे रहा हूं। एस0वाई0एल0 का पानी अगर हम नालागढ़-बद्दी और स्वारघाट के पास से नहर बनाकर लिंक कर देते हैं, इसमें करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि यह नहर जिन-जिन स्थानों से निकाली जाएगी वहां पर अधिकतर सरकारी लैंड है, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और अगर सरकार ऐसा करती है तो 1000 से 1200 करोड़ रुपये की सालाना इंकम सरकार को इससे हो सकती है, अगर सरकार इस परियोजना पर काम करती है तो।

1.9.2025/1755/डी0टी0/वाई के0-3

मेरा एक सुझाव यह भी है कि धारा 118 में कुछ सांसोधन सरकार को अवश्य करना चाहिए। इसमें जो बाहरी राज्यों के लोग हैं उन्होंने अगर प्रदेश में उद्योग लगा लिया और किसी कारण उद्योग नहीं लगा उस व्यक्ति की डेथ हो गई या वित्तिय स्थिति खराब हो गई, उसको हम तीन साल से पांच साल का वक्त दे रहे हैं। ऐसे में कई मामलों में देखा गया है कि सरकारी अधिकारी का उस व्यक्ति को समय पूरा होने के कारण यह कहा जाता है कि आपकी जमीन सरकार के पास वेस्टिड हो गई और अब आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसके अनुसार किसी की प्राइवेट लैंड को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं उन लोगों को किसी न किसी कोर्ट से रिलीफ मिलता है और उस रिलीफ को मिलने में काफी वर्ष लग जाते हैं और तब तक उस जमीन के दाम 10 गुणा बढ़ जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि इसकी एक्पेंशन के लिए

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

01.09.2025/1800/ए.जी.-एन.जी./1

श्री राम कुमार........जारी

सरकार एक फीस फिक्स करे और यदि उसे 2-3 साल की एक्सटेंशन दी जाती है तो इससे भी सरकार का राजस्व जनरेट होगा।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार ने यहां पर बी0बी0एन0डी0ए0 के चेंज ऑफ लैंड यूज़ की बात कही है। बी0बी0एन0डी0ए0 वर्ष 2006 में गठित हुआ है। इसका कोई अपना इंकम सोर्स नहीं है। इसमें सरकार ने डायरेक्टर की पॉवर्स सी0ओ0 को दी हैं ताकि वे सी0एल0यू कर सकें। उससे प्राप्त आय से उनके दफ्तर में काम करने वालों की सैलरी व अन्य खर्चों का वहन किया जाता है।...(घण्टी)...

सभापति महोदय, यहां पर जंगलों पर बात की गई और मैं कहना चाहता हूं कि जंगलों के संसाधनों का दोहन करना भी अतिआवश्यक है। मैं खैर की बात करना चाहता हूं और माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल ने इस पर काफी चीज़ों को कहा है। जब हम जंगलों में जाते हैं तो देखते हैं कि खैर के बहुत-बहुत मोटे-मोटे पेड़ खड़े हुए हैं। खैर की फसल धान की तरह होती है जो बार-बार उगती रहती है। मेरा सुझाव है कि जहां पर भी पुराने खैर खड़े हैं, इसके लिए पूरे प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। अभी वन विभाग का एक सैट फार्मुला है कि इस वर्ष एक बीट खोल देते हैं और दूसरे वर्ष अगली बीट खोल देते हैं। मेरा निवेदन है कि खैर के पुराने पेड़ों का सर्वेक्षण करवा जाए और उनके कटान के लिए सरकार अनुमति प्रदान करे। मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार को इसके माध्यम से करोड़ों रुपयों की आय प्राप्त होगी। इसके अलावा हमारी जंगली बुटियां या अन्य जो चीज़ें हैं, उनका भी सर्वेक्षण करवा कर चिन्हित किया जाए ताकि जंगली बुटियों का अन्य राज्यों से व्यापार किया जा सके।

01.09.2025/1800/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रदेश में वाइन की इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। हमारे प्रदेश में करोड़ों रुपयों का सेब हर वर्ष सड़ जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनलगी औद्योगिक क्षेत्र में किसी ने वाइन की एक छोटी-सी इंडस्ट्री लगाई है। इसके अलावा मैं अखिल भारतीय वाइन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष से भी मिला हूं और उन्होंने मुझे कहा है कि यदि आप हिमाचल प्रदेश में इस इंडस्ट्री को खोलते हैं तो हम आपके सड़े हुए सेब, जिसको आप नाले में फेंक रहे हैं और उससे प्रदूषण हो रहा है, को ९ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद लेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर कोई पॉलिसी बनाएं और मेरा मानना है कि इससे प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपयों की आय प्राप्त होगी तथा हमारा प्रदूषण भी कंट्रोल होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में भारत में वाइन का ज्यादा चलन नहीं था और अब लोगों का रूझान वाइन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश को शराब के ठेकों की निलामी से ही सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है। पूर्व सरकार तो हर वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाकर इन ठेकों को रिन्यू करती रही लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने शराब के ठेकों की ओपन ऑक्शन करके एक साल में लगभग

500 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय अर्जित की है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से वर्तमान प्रदेश सरकार बनी है तब से प्राकृतिक आपदाओं से झूझ रही है और मेरा विपक्ष के साथियों से निवेदन है कि इस मामले में टांग खीचने के बजाय सरकार का साथ दीजिए तथा प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित करवाएं। इस बरसात में पूर्व मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है और राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। माननीय मुख्य मंत्री व प्रदेश सरकार ने सोशल वैल्फेयर में जो काम किया है वह पूरे भारत वर्ष में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। हमारे राहत मेन्युअल को संशोधित करके राहत राशि को कई गुणा बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार ने मकान के लिए 7 लाख रुपये का पैकेज दिया है।लोगों की जमीन बह जाने पर उन्हें जमीन नहीं मिलती थी लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों के मकान गिर गए हैं या जमीन बह गई है, उन्हें 3-3 बिस्वा जमीन दी जाएगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

01.09.2025/1800/ए.जी.-एन.जी./3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज भाग लेंगे।

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, आपने विशेषाधिकारों का उपयोग किया...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, डॉ0 हंस राज, एक मिनट रुकिए क्योंकि माननीय सदस्य, श्री राम कुमार कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम कुमार : सभापति महोदय, एक बात कहना रह गया है और इसे रिकॉर्ड पर लाना बहुत जरूरी है। यहां पर किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न लगाया था और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में बद्दी से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। मैं इस रिकॉर्ड को (कुछ कागज़ात दर्शाते हुए) सभा पटल पर रख रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के दौरान बद्दी से 310 इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। इसके जो मर्जी कारण.

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

01.9.32025/1805/PB-AG/1

श्री राम कुमार ....जारी

विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं।

सभापति : माननीय सदस्य आप इन्हें ले कर दीजिए।

श्री राम कुमार : सभापति महोदय, मैं इन कागज़ातों को सभापटल पर रखता हूं।

सभापति : अब माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज इस चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

Chairman: Please don't make a noise. Don't disturb.

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, आपने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए सत्ता पक्ष को डबल प्रायोरिटी दी है। हम यहीं पर समझ सकते हैं कि रिसोर्सिज की मोबिलाइजेशन कैसे होगी? यह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं।

सभापति : माननीय सदस्य आपकी तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्यों के नाम कम थे इसलिए दो-एक की रेशो करनी पड़ी। सत्ता पक्ष से सात और विपक्ष से तीन माननीय सदस्य थे।

डॉ हंस राज : आप तीन से पहले बुलवा लेते। यह आपका अधिकार है इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा।

सभापति : माननीय सदस्य, चलिए कोई बात नहीं।

उद्योग मंत्री : माननीय सदस्य, आप सभापति महोदय के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। यह गलत है।

डॉ0 हंस राज : मैं इनके फैसले को क्यों चुनौती दूंगा? सभापति महोदय, मेरे मित्र हैं। इसे सभापति महोदय अन्यथा न लें क्योंकि मैं तो इस संदर्भ में इनका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि हमारे दो और माननीय सदस्यों के नाम भी थे। चलो जो हो गया वह हो गया।

01.9.32025/1805/PB-AG/2

माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया बहुत रिलेवेंट विषय लाए हैं परंतु इनकी हड़बड़ाहट ऐसी होती है जैसे पटरी पर रेलगाड़ी भागती है लेकिन इनका कंटेंट बहुत अच्छा था। मैं उसकी सराहना करता हूं। जब इन्होंने मुलाज़िमों की गाड़ियों की बात की तो इन्होंने कई लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। एक मुलाज़िम तीन-चार विभाग संभाल रहा है तो उसे चार-चार गाड़ियों की क्या जरूरत है? वे उसमें क्यों अपने बच्चों और कुत्तों को घुमा रहे हैं? माननीय सदस्य आप ऐसे ही कहना चाहते थे परंतु ये सीधे तौर पर नहीं कह पाए इसलिए इनकी तरफ से मैं यह कह देता हूं। यह विषय सच में बहुत गम्भीर है।

सभापति महोदय, मैं एक छोटे उदाहरण के साथ आपके सामने सारी परिस्थिति रखता हूं। जब मैं विधायक बना तो हमारे क्षेत्र में किसी विभाग का कोई डिवीजन नहीं था। आप इसका रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हो। वहां पर न पी0डब्ल्यू0डी0 का डिवीजन था और न ही आई0पी0एच0 का। बिजली बोर्ड का डिवीजन तो खुलवा कर भी चला गया क्योंकि इस सरकार द्वारा उसे डिनोटिफाई कर दिया गया। मुझे जब लोग मिलने आए तो उन्होंने कहा कि हम जिस जगह से रेत को पिकअप के द्वारा सड़क तक लाते हैं, उस के लिए 7000 रुपये खर्चा आता है। उस रेत को यदि हमें अपने गांव तक पहुंचाना होता है तो हमें लगभग 45-50 हजार रुपये का कैरेज लग जाता है क्योंकि वह सामान खच्चरों पर ले जाया जाता है। आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे हो। आप कहते हो कि पक्के मकान होने चाहिए, गांव में स्वच्छता आनी चाहिए लेकिन वर्ष 2012-13 में शौचाल्य नहीं हुआ करते थे। यह मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बाद उस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला जो 40 वर्षों से राजनीति में थे। उस समय मैं विपक्ष में था, यह वर्ष 2012 की बात है। हमने पहले जोर आजमाइश की कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डिवीजन खुल जाए। हमने दो-तीन सत्र में कोशिश की और डिवीजन खुलवाए। जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 के डिवीजन खुलने से हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद

डी0पी0आ0 और एस्टिमेट बनने शुरू हुए तथा धरातल पर चीजें होंने लगी। परंतु उसके लिए फंड कहां से आता? स्टेट तो यही थी। फिर हमने दिमाग लगाया कि हम विधायक निधि और मनरेगा को कंवर्ज करते हैं और मेरे पास जो भी रिसोर्सिज हैं मैं उन्हें वहां

01.9.32025/1805/PB-AG/3

मोबिलाइज करता हूं। मुख्य विषय तो सड़क बनाने का है। सड़क बनने से पहले वर्ष 2012 में पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति के घर के दो-चार पक्के कमरे 15-20 लाख रुपये में बन रहे थे तो सड़क बनने से अब वहां 7-8 हजार में पिकअप घर तक सामान पहुंचा देती है। मेरा यह

रेवेल्यूशन काम आया। हमने लगातार दस वर्षों में 246 सड़कें बनाईं और हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा।

सभापति महोदय, वहां के लोग मक्की पैदा करते थे। यदि 5-6 बीघा में मक्की पैदा होती है तो वह मक्की 40-50 हजार रुपये में बिकती है। हमने उन्हें कहा कि गांव भराड़ा में लोग हर वर्ष मटर की नई फसल पैदा करते हैं। हमारे क्षेत्र में अब राजमा खत्म हो गया है। हमारे क्षेत्र का ऐसा पर्यावरण को गया है कि राजमा की पैदावार पहले जैसी नहीं हो रही है। अन्यथा हमारे क्षेत्र में राजमा, शहद और घी का उत्पादन बहुत होता था। हम मक्की का उत्पादन इसलिए करते हैं क्योंकि वह चारे के काम आती है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2025/1810/AS/AP/-01

डॉ0 हंस राज जारी .....

चारा हम पंजाब से भी ला सकते हैं हमारे घासनिया हैं वे पहाड़ों से भी काट लेते हैं। तो क्यों नहीं यहां पर मटर की बिजाई की जाए। जहां से हम 40 से 50 हजार रुपये कमा रहे थे अब

वहां से डेढ़ से दो लाख रुपये कमा रहे हैं इसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। मैं अगर भारत सरकार की तरफ देखूं या हिमाचल सरकार की तरफ देखूं इस बार की स्थिति बहुत व्यापक हुई है। अब पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है। मुझे तो आज के दिन यह चर्चा भी प्रासंगिक नहीं लग रही है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर चर्चा होनी चाहिए। अब तो रिसोर्सेस और घटेंगे। क्योंकि जिस तरह की आपदा पूरे प्रदेश में आई है आपने देखा कोई हमारा जिला इस त्रासदी में अछूता नहीं रहा है। कोई गांव नहीं रहा जहां पर आपदा न हुई हो। हमीरपुर में कल हम चबूतरा गांव की बात कर रहे थे जहां घर पूरे-के-पूरे धंस गए। हमीरपुर, कांगड़ा बहुत प्लेन इलाके हैं, वहां कम से कम हम लैंडस्लाइड की कल्पना नहीं कर सकते। लाहौल-स्पीति, चंबा, किन्नौर या हम कहें कि जो सिरमौर, मंडी और शिमला वाले इलाके हैं इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की संभावना हो सकती है। लेकिन प्लेन क्षेत्रों में इस तरह की कोई संभावना नज़र नहीं आती। अब बेसिक थ्रैट और बढ़ गया है, सरकार की जिम्मेदारी तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं जब अन्य वक्ताओं के विषय सुन रहा था, जैसे माननीय श्री राम कुमार जी कह रहे थे, पर मुझे वह सत्संग समझ नहीं आया। मैं सच बताऊं, वह किसके लिए कह रहे थे स्ट्रेट, किसी मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी के लिए कह रहे थे, किसको सुनाना चाह रहे थे और किस तरह की रिसोर्सेस और किसके लिए मोबिलाइज करना चाहते हैं। मैं यहां पर किसी के लिए व्यंग्य नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस संदर्भ में हमारी शंका तो इतनी है कि अब हमें हिमाचल प्रदेश के लिए सच में सोचना चाहिए। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, उन्होंने मुझे तीन बार जिताया है। कल वे मुझसे प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे कि तुम चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हमको क्या लेना-देना। मुझे मेरे घर द्वार के पास पक्की सड़क चाहिए, गांव के बगल में सरकारी स्कूल चाहिए कॉलेज व पॉलीटेक्निक और हायर स्टडीज़ के लिए हमारे बच्चों को गांव के बाहर जाना पड़ता है

01.09.2025/1830/AS/AP/-02

वह मेरे गांव में ही होना चाहिए। इन सबके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं, चाहे मुझे आपसे लड़ना पड़े या आपके सामने गिड़गिड़ाना पड़े। लेकिन सत्ता में बैठा जो मुख्य व्यक्ति है उसको पूरे प्रदेश के लिए सम्मान दृष्टि रखनी चाहिए। उसको अपने प्रदेश का

पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। अब लिखने को तो मैं बड़ी टर्म्ज भी लिख सकता था। उसमें पठानिया जी बोलेंगे उनका यह विषय है कि कहां से पैसा आएंगे, कहां से पैसे डबल होंगे, पूंजी क्या है, पूंजी का निवेश क्या है और पूंजी का टर्नआउट क्या आएगा वह यह बताएंगे। वह हमारा विषय नहीं है क्योंकि हम आर्ट्स के बच्चे हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़कर यहां तक आए हैं। हमारा टेक्निकल काम ही नहीं है। हां, चाचा जी भी समझ सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और वे अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जिस छोटी-सी मेरी ग्रामीण इकोनॉमिक्स को मैं जानता हूं, वे वह कहती है कि अगर मैंने कर्ज उठाया अपने घर को बनाने के लिए, 50 लाख रुपये का कर्ज मैंने भी लिया और मुझे भी लगा कि अब मैं हररोज कुर्सी और बर्तन कहां से ढूंढता रहूंगा तो मुझे घर बनाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। हमने कर्ज उठाया, मुझे पता था कि इतने सालों में इसको मैं भर दूंगा। एक तथाकथित व्यक्ति अगर अपने लिए इंडिविजुअल लोन लेता है, वह भर देता है, वह पूरा कर देता है, वह करता है या उसकी आने वाली पीढ़ी कर देती है। लेकिन 10-20 सालों में वह ठीक कर देता है। फिर स्टेट का मुखिया 5 साल के लिए सत्ता में बैठता है। आपकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि हम खर्चों का सुधार नहीं कर पाते और सोचते है कि खर्चों का सुधार कैसे होगा? अब चुनावों में हमने बड़ी घोषणाएं कर दीं ओ.पी.एस. लागू कर दिया। वह हमारे गले की फांस बन गई। अब जिन लोगों ने विचार-विमर्श कर सत्ता हासिल करनी है, उसके लिए कुछ भी बोल देना है और उसके निर्वहन के लिए स्टेट के असेट्स को तोड़-मरोड़ करके इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं है पांच साल बाद फिर कोई व्यक्ति सत्ता में आएगा, वह भी प्रदेश का ही व्यक्ति होगा। कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान से नहीं होगा। वह भी तो इस प्रदेश का बंदा है।

श्री ए0 टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2025/1815/AT/AS/01

श्री हंस राज जारी...

जैसा बुटेल साहब कह रहे थे कि हमने संस्थाओं को डी-नोटिफाई किया है। अब इन्हें क्या पता कि जो तन लगे सौ तन जन है। मान लीजिए मेरा पांच-छह साल का बच्चा, पांच-छह

किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल जाता है तो यह वेलफेयर स्टेट में अन्याय नहीं है। हमने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को चुना है और जब आप कहते हैं we are a democratic State. तो वेलफेयर करना आपका कर्तव्य और दायित्व है। यह आपको करना ही पड़ेगा।

आप लोग खामखाह वहां से छुपते हैं। जो इलाके पहले से ही डेवलप्ड थे वहीं पर बड़े-बड़े महाविद्यालय और संस्थान खड़े कर दिए गए जबकि उनकी फीडिंग के लिए बच्चों की संख्या ही नहीं है। तो वहां संस्थान खड़े करने का क्या औचित्य है? अगर कटौती करनी है तो वहां करो और जहां सुविधाएं नहीं पहुंची हैं वहां तक पहुंचाओ।

अब जैसे मैं चुराह की तरफ देख रहा हूं। हमारी मुख्य सड़क जो पांगी तक जाती है वही जिला की मेजर रोड है। मैं परसो भी कह रहा था कि अगर पांगी के लिएर अभी राशन नहीं पहुंचा तो बाद में मुश्किल हो जायेगा, क्योंकि समय तो अभी है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यह बता रही है कि अरब सागर में कोई घटना हुई है पर मैं बता नहीं पा रहा... (व्यवधान)।

पूरे साल यहीं बैठे रहो और गप्पे मारते रहो, फील्ड में काम मत करो। यह तो यही चाहते है कि मानसून का सत्र ऐसे ही चलता रहे ताकि आपको लोगों को फेस न करना पड़े। लेकिन जनता का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। दो , तीन, चार दिन आप विधानसभा में छुप सकते हो लेकिन जिन स्कूल और यूनिवर्सिटीज को डी-नोटिफाई किया है उसके लिए लोग आपसे पूछेंगे कि रोहित जी आपको प्रदेश का मंत्री बनाया गया था सिर्फ कोटखाई का नहीं।.....(व्यवधान) कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने यहीं पर कहा था कि अगर प्रदेश में केवल एक बच्चा भी होगा ...(व्यवधान) उनकी आत्मा आज ऊपर से यह सब देखकर इनको कोस रही होगी कि इन लोगों ने प्रदेश का कितना बुरा हाल कर दिया है। आज जो बारिश हो रही है वह उनके आंसू हैं जो बादल बनकर हम पर बरस रहे हैं, वह पुण्य आत्मा थी ।

01.09.2025/1815/AT/AS/02

मेरा सरकार से आग्रह है कि अब सरकार में चेतना आ जानी चाहिए। आपको रिसोर्सेज का सही उपयोग करना होगा ...(व्यवधान) मैं आपको नहीं बोल रहा हं। (***) मेरा आपसे

निवेदन है कि सरकार की मंशा को सही दिशा में ले जाया जाए। श्री केवल सिंह पठानिया जी की मंशा बहुत साफ और सही है।

मान लीजिए मेरी एम.डी.आर. रोड बह गई और हमने जो भी लिंक रोड बनाए वो भी बह गए। उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए एडिक्वैट फंड्स चाहिए। हालांकि उसमें भी (***)होगी। लेकिन हमारे लिए तो वे सड़कें ही जीने का साधन हैं।

अब रोपवे की बात करें। आपने कई जगहों पर रोपवे बना दिए जहां इतनी जरूरत ही नहीं थी। हमने कहा था कि बनौड़ी से पांगी तक 26 किलोमीटर रोपवे बने। इस बार माननीय नितिन गडकरी जी से आदरणीय जयराम ठाकुर जी जब मिले हम भी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के साथ थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जितने भी रोपवे प्रोजेक्ट लाओ सब स्वीकृत होंगे। हमने डी.पी.आर. भी तैयार की है और प्रपोजल सबमिटीड है। इसमें साथ चलना होगा। जैसे चंडीगढ़ से शिमला तक रोपवे बनेगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग आपकी तरफ और आएंगे। आप टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को आकर्षित कर सकते हैं।

कृषि और बागवानी में हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। फ्लोरीकल्चर की बात बुटेल साहब ने बिल्कुल सही कही। फ्लोरीकल्चर की शुरुआत चुराह विधान सभा क्षेत्र से हुई थी। लेकिन सही ट्रांसपोर्टेशन न होने से इसका उपयोग ठीक से नहीं हो पाया और हमारे किसान कर्ज में चले गए। अब हमें कुछ करना होगा। अगर हमारे पास 10 रुपये हैं और उसे 100 रुपये बनाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। जैसा आदरणीय सोदान जी कहते हैं कि हम लोग चवन्नी लेकर धंधा करते हैं। हर्षवर्धन जी चवन्नी इधर से उठाते हैं उसे मुख्य मंत्री साहब के पास देते हैं और वही मुख्य मंत्री साहब उनके पास लौटा देते हैं।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया। **एम0डी0द्वारा जारी....**

01-09-2025/1820/DC/MD/1

डॉ0 हंस राज---जारी :

ये लोग खर्चा दोनों तरफ से बराबर करते रहते हैं और इनकी कोई आउटकम आती नहीं है। आपने कहा कि हम नई इंडस्ट्रीज को सिंगल विंडो पर क्लीयरेंस दे रहे हैं। कितने डाटा सेंटर वाले लोग आपसे कई बार राफता कर चुके हैं कि हमें उसकी क्लीयरेंस दो लेकिन हम उसको कभी एक ऑब्जैक्शन में फंसा देते हैं और कभी दूसरे में फंसा देते हैं। मेरा यह निवेदन है सरकारों से बहुत सारे इन्वेस्टर हिमाचल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपको उनको व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी और उनकी तरफ जाना पड़ेगा ताकि युवाओं को रोजगार मिले यही स्वावलंबन, रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन होती है। आपके पास कुदरत दी हुई है। जो जंगलों की बात कर रहे थे कि जंगलों में लॉटस के नाम पर अवैध कटान चल रहा है। लॉटस अलॉट होते हैं पर वह सिर्फ सड़े-गले और सूखे हुए पेड़ों के लिए होते हैं। लेकिन उसकी आड़ में लोगों क्या-क्या लूट मचाई हुई है वह नदियां बता रही है। परसों चंबा में जो बाढ़ आई उस दिन लोगों ने बालू ब्रिज के नीचे देखा तो वहां पर पेड़ों के और वह भी देवदार के पेड़ों के हजारों पता नहीं कितने नग आए हुए हैं। सही मायनों में सबसे बड़ा इनकम का रिसोर्स कभी जंगल हुआ करते थे और आज भी जंगल ही है। उसमें जड़ी-बूटियों और जो औषधीय पौधों को विकसित कर सकते हैं और उनकी खेती कर सकते हैं। वह हाई एल्टीट्यूड में सात-आठ हजार फीट की हाइट के ऊपर होते हैं। बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनको उगाया जा सकता है। अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरैस्ट या कॉरपोरेशन वाले कोई भी उसमें एफट्र्स लगाएं तो वह रिसोर्सेस डेवलप हो सकते हैं । लेकिन हम लोग उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभापति महोदय, आपने यहां माननीय सदन में यह कहना है की चर्चा के लिए कोई विषय लाया है और मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करना है जिसमें सत्ता और अपोजिशन ने बोलना है। इन्होंने रिकॉर्ड करना है और यह विषय केवल यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसको अंगीकार करना चाहिए और इस पर पॉलिसी बननी चाहिए। यहां पर कोई भी विधायक जो-जो सॉलिड चीजें कहता है उनको आपको उसमें अक्षरशः लाना चाहिए। यहां पर जो माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने कहा, मैं सच कह रहा हूं कि इन्होंने यहां पर आज आंखें खोलने वाला अभिभाषण दिया है। एक

01-09-2025/1820/DC/MD/2

चीज जो 5 लाख रुपये में चल सकती है, आप उसके लिए 17-17 लाख रुपये दे रहे हैं। मैं यह कहूं कि जो-जो रिक्रूटमैंट, शायद हमारी मजबूरियां होती हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों की या माननीय मुख्य मंत्री की, लेकिन कई भर्तियां हमने बेवजह की हुई हैं। सरकार के नाम पर उन्हें गाड़ी और बंगला दिया है। उनके खर्च बीयर कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। जब हम अपनी सैलरी की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमारे हालात बहुत खराब हैं। लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम कड़वी घूंट पी रहे हैं। लेकिन जो विधायक निधि है या जो आप अब फंड्स देंगे, एस0डी0आर0एफ0 रिलीफ फण्ड, बैकवर्ड एरिया सब प्लान इत्यादि का पैसा जो आप दे रहे हैं, वह लोगों तक पहुंचना चाहिए और उससे आउटकम भी आनी चाहिए। कई लोगों ने इन चीजों को धंधा बना लिया है। शिमला में आते हैं और किसी से भी डी0ओ0 साइन करवाते हैं। उन्होंने उसके लिए प्रसेन्टेज रखी हुई है, कमाल हो गया और लोग कहते हैं कि हम करवाते हैं। वहां से और गांव में आकर के एक डंगा 26 बार लग जाता है। आपका एक पनिहारा जहां पर पानी आता है, वह नेचुरल रिसोर्स होता है। वहां पर एक ही पनिहारा सात बार बन जाता है। यह जो पैसे का दुरुपयोग है, इसको अगर हम नहीं रोकते हैं तो आप चाहे निवेश जितना बड़ा ले आएं। अगर घर में लीकेज है तो वह आपका टैंक कभी नहीं भरेगा। हमारे पास जो संसाधन हैं, जैसे हाइड्रो पावर में कितना बड़ा पोटेंशियल है। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री चंबा में आए और वहां पर हाइड्रो पावर में दो प्रोजैक्ट का शिलान्यास करके गए। एक का काम चला और दूसरे का चलाया ही नहीं, उसमें कहा गया कि यह रोप-वे पर बनेगा। मैंने कहा इधर रोप-वे क्यों बनानी। रोप-वे चांजु जो हमारा दयोथल प्रोजेक्ट है, जो अभी शुरू ही नहीं हुआ जैसे उसमें भी फंडिंग पड़ी है। वहां भी कई लोगों को रोज़गार मिल सकता था, उसमें भी कहा गया कि यह प्रोजैक्ट रोप-वे के बुते ही चलेगा। वह रोपवे के बुते नहीं चल सकता, वहां सड़क पहुंच सकती है। कई डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जैसे खुंडी माता की यात्रा है, वहां के लिए जा सकते हैं। चुराह में लोग गडाहसरू महादेव के लिए जाते हैं, वहां पर कर सकते हैं। साच-पास सबसे रमणीय स्थल है। वहां पर हमें 12 महीने बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि वह चंबा में है और वहां से प्रतिनिधित्व कोई खास ताकतें नहीं करती हैं तो इसलिए उनकी चर्चा नहीं होती। मैं भनोड़ी

की बात कर रहा हूं, इससे टूरिस्ट तो आएगा लेकिन उसके साथ-साथ जैसे अभी क्लाउडब्रस्ट हुए या बड़ी भारी बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रहा है। वह जो

01-09-2025/1820/DC/MD/3

स्विट्जरलैंड की कंपनी थी, उसने कहा था कि आप 12 महीने इस रोपवे का इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्होंने इतना तक कहा था और भारत सरकार पैसे दे रही है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें जाना चाहिए।

श्रीमती के0एस0 जारी -----

01.09.2025/1825/केएस/डीसी/1

डॉ0 हंस राज जारी ----

मैं तो विक्रमादित्य सिंह जी से बात करुंगा कि वे हमारे साथ चलें। यह उनको ही कहा था क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी.उनके पास है। भद्रवाह, भलेशा, जम्मू-कश्मीर में हजारों करोड़ रुपये के नेशनल हाईवे और फोर लेन बन गए लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि हम सभी लोगों ने यहां पर जो विषय रखे हैं और जो लोग और भी विषय रखने वाले हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को सही मायने में प्रयास करने चाहिए। हैल्थ टूरिज्म बहुत बड़ा टूरिज्म हो सकता है। जैसे यहां पर हम लोग पालमपुर, बैजनाथ, चम्बा, खजियार की बात करते हैं, वहां पर हैल्थ टूरिज्म का काफी स्कोप है। केरल, सिक्किम और अन्य राज्य हैल्थ टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहां लोग पूरे-पूरे पैकेजिज़ बना कर जाते हैं और एक-दो महीने तक वहां पर रहते हैं। हमारा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट कम हुआ है, उसको हम इस तरह से अपनी

ओर आकर्षित कर सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने इस पर बहुत अधिक काम किया है और उसी तरह से हमें भी कार्य करना चाहिए।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि लाइमस्टोन में चम्बा में भी बड़ा पोटेंशियल है। हमारी सिकरी जिसके बारे में पता नहीं कितने सालों से हम जनता को ठग रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सारी सरकारें कहती हैं कि हमें इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है लेकिन आप स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से बात तो करो। इन्वेस्टर क्या वहां सब लोग आएंगे। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सभापति महोदय, यह बहुत रिलेवेंट विषय है लेकिन चूंकि अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भारी बारिश से तबाही हो रही है और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो हमारा सोचने और समझने का स्तर सिर्फ उसी तरफ चला गया है। अगर इस तरह की भयावह परिस्थितियां हिमाचल में और बन गईं तो हम जो विकसित हिमाचल की कल्पना करते हैं, उस तरफ हम बहुत कदम पीछे रह जाएंगे।

01.09.2025/1825/केएस/डीसी/2

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति : रिकॉर्ड से(*******) शब्द निकाल दिया जाए। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी भाग लेंगे।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

01.09.2025/1825/केएस/डीसी/3

श्री भवानी सिंह पठानिया : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत चल रही चर्चा में मैं अपने आपको शामिल करता हूं। जब मैंने अपना नाम दिया था उस समय मैंने यह सोचा था

कि मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं करुंगा लेकिन दो-तीन बातें हैं जो बोलनी ही पडेंगी। मैं पहले पोलिटिकल बात कर लेता हूं उसके बाद मैं प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमैंट पर आ जाऊंगा। शुरुआत मैं एक छोटे से शेर के साथ करना चाहूंगा कि :-

तू इधर उधर की बात ना कर,
तू इधर उधर की बात ना कर,
यह बता काफ़िला क्यों लूटा।

और यह कौन सा काफ़िला लूटा है, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के अंदर केंद्र में जो सरकार आई थी, उसके समय में भारत का टोटल डैट 50 लाख करोड़ रुपये था। आज 11 साल के बाद वह 200 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है यानी 4 गुना बढ़ गया है और हिमाचल का डैट वर्ष 2014 में 35 हजार करोड़ रुपये था जो आज लगभग 98 हजार करोड़ रुपये है जो लगभग 2.8 गुना बढ़ा है। अब किसने किसको डैट में डाला because the State is the reflection of the Country. जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी, उसी प्रकार से बाकी राज्यों की अर्थव्यवस्था भी चलेगी। तो एक भ्रांति जिसमें यह कहा जाता है कि राजा वीरभद्र सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोन लिया, अगर उन्होंने लोन नहीं लिया होता तो आज हम ऊंट की पीठ पर बैठकर अपने गांव से मेन रोड पर आते और वहां से पीठ पर ट्रंक उठाकर निकटतम स्टेशन/मोड़ पर जाते और वहां से बस पकड़ कर चार या पांच दिन के बाद शिमला पहुंचते। जो भी डवलपमेंट हुई है, यह लोन के सिर पर हुई है वह चाहे नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक या किसी अन्य प्रकार का लोन हो। Loan taken for productive work is not to be treated as loan. अगर उससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप कर रहे हैं, उससे अगर आप अर्थव्यवस्था या आर्थिकी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो it is not considered as bad loan. इसके बाद मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ आता हूं। हमारे पास पांच मुख्य सेक्टर्ज़ हैं जिनमें से मैं सिर्फ दो या तीन के ऊपर ही बात करुंगा। क्योंकि बाकियों के ऊपर बात हो चुकी है। हिमाचल एक पावर राज्य है। हिमाचल के अंदर हमारे पास माइनिंग और मिनरल का एक बहुत बड़ा खजाना पड़ा है। औद्योगिकरण के क्षेत्र में हमारे पास एक बहुत बड़ी सम्भावना है। टूरिज्म के बारे में प्रत्येक सदस्य ने बात की

01.09.2025/1825/केएस/डीसी/4

है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करुंगा और पांचवी चीज़ है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा समय स्पेंड करना चाहूंगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

01.09.2025/1830/AV/hK/1

श्री भवानी सिंह पठानिया------ जारी

मैंने जैसे आपको पावर के अंदर बोला है, हमारा बिजली बोर्ड पिछले महीने काफी समय के बाद प्रोफिट में आया है और पावर सेक्टर के इतिहास के अंदर आज तक हमारा बिजली बोर्ड शायद केवल चार बार ही प्रोफिट में आया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पावर सेक्टर को लाभ में लाने के लिए जो-जो कदम उठाए हैं, उनके परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। उसमें चाहे सब्सिडी की बात हो या फिर इण्डस्ट्री के अंदर सब्सिडी के रेशनेलाइजेशन, पावर प्रोजैक्ट्स के अंदर हमारे हिस्से की बात या फिर शानन पावर प्रोजैक्ट सहित दूसरे प्रोजैक्ट्स के अंदर हमारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनमें हिमाचल का पक्ष रखने की बात हो। यानी ये जो भी कार्य हो रहे हैं इनमें आज परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पावर सेक्टर के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है जिसको माननीय मंत्री श्री राजेश धर्माणी हैड कर रहे हैं और उसका मैं भी एक छोटा-सा हिस्सा हूं। इस सब-कमेटी की जब सिफारिशें आएंगी तो पावर सेक्टर के अंदर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे।

पर्यटन के क्षेत्र में यदि आपने पूरे हिमाचल प्रदेश की जिलावाइज पर कैपिटा इन्कम देखनी है तो वह सबसे ज्यादा सोलन जिला की है। दूसरे नम्बर पर शिमला और तीसरे नम्बर पर आपके बाकी जिले आते हैं। परंतु सबसे कम पर कैपिटा इन्कम जिला कांगड़ा की है। अब अगर आपने जिला कांगड़ा की पर कैपिटा इन्कम को बढ़ाना है तो वहां पर आपको खास डायरेक्शन देनी पड़ेगी। माननीय मुख्य मंत्री ने वह डायरेक्शन टूरिज्म के अंदर दी है। आपने कांगड़ा को 'टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल' डिक्लेयर किया है। इस बारे में न केवल डिक्लेयरेशन हुई है अपितु आप यह सोचकर आगे बढ़ रहे हैं कि वहां पर ज्यादा-से-ज्यादा टूरिस्ट्स आएं जोकि वहां कम-से-कम 7-8 दिन तक रुकें। माननीय मुख्य मंत्री

द्वारा उस क्षेत्र में इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम कहें तो सबसे पहले टूरिज्म विलेज कहां बनेगा या कैसे बनेगा, वह जब बनेगा तब बन जाएगा परंतु टूरिज्म विलेज पर्यटन क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी मूव है। इसके बाद बोटेनिकल पार्क, जुओलॉजीकल पार्क और देहरा में आप जो जू बना रहे हैं, वह इसके अंदर एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त कंवैंशनल सेंटर्ज तथा हेलीपोर्ट्स इत्यादि बन

01.09.2025/1830/AV/hK/2

रहे हैं। ये सारी-की-सारी चीजें न केवल टूरिज्म को बढ़ाएंगी परंतु हरेक टूरिस्ट जो हिमाचल के अंदर आएगा, वह अगर एक पानी की बोतल भी खरीदता है तो उसकी जी0एस0टी0 की कीमत हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार का एक दूरदर्शी स्टैप है।

अब मैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल ईकोनॉमी की बात करना चाहूंगा। हम जो भी कार्य करें वे ऐसे होने चाहिए जिसके कारण हमारे साथ जनता जुड़ जाएं और वह कार्य पक्का सिरे चढ़ता है। आप देखिए, मैं अगर इण्डस्ट्रीयलाजेशन की बात करूं तो इण्डस्ट्री के साथ बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप बाकी सेक्टर भी देखिए, उनके साथ बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं लेकिन ग्रामीण आर्थिकी एक ऐसी चीज है जिसके साथ हिमाचल की 65 से 70 प्रतिशत जनता जुड़ी हुई है। अगर हम इनको किसी तरीके से कैप्चर कर लें तो न केवल हिमाचल की आर्थिकी अपितु हरेक व्यक्ति जोकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, वह रातों-रात तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन 5-6 वर्षों के बाद उनकी इन्कम न केवल दुगनी अपितु तीन या चार गुणा हो सकती है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आंकड़ों पर आता हूं। हमारी पैकेज जूस की जो मार्किट है और इसमें मैं केवल प्योर जूस की बात कर रहा हूं। मैं इसमें फ्रूटी को नहीं गिन रहा हूं जोकि एक बेवरेज है और न ही मैं इसमें बाकी ड्रिंक्स माज़ा इत्यादि को गिन रहा हूं। मैं इसमें केवल-और-केवल फ्रूट जूस की बात कर रहा हूं। हिन्दुस्तान की पैकेज फ्रूट जूस मार्किट 15000 करोड़ रुपये की है जोकि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमारे पास एच0पी0एम0सी0 एक ऐसा संस्थान है जोकि फ्रूट जूस बनाता है,

इसका आज तक का सबसे बेस्ट टोटल टर्न ओवर 102 करोड़ रुपये रहा है। आप यह चीज देखिए कि हम एक फ्रूट उत्पादक स्टेट है, हमारे पास न केवल आम है बल्कि सेब इत्यादि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे पल्पिंग की जा सकती है। लेकिन हमारा यह संस्थान केवल 102 करोड़ रुपये के ऊपर बैठा है जबकि इसकी ऑपुरचुनिटी 15000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की है। अब अगर 15000 करोड़ रुपये का टोटल यूनिवर्स है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं क्योंकि 15000 करोड़ रुपये तो टोटल मार्किट है। अगर हम इसके 10 प्रतिशत तक जाने की भी कोशिश करें और मैं अगर 1500 करोड़ रुपये की बात करूं तो उसके लिए हमें क्या-क्या स्टैप लेने चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा

01.09.2025/1830/AV/hK/3

सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे पास 8 मेन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स उपलब्ध हैं यानी हमारे पास पूरे-का-पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जिससे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर हम जो सेब और बाकी फ्रूट्स खरीद रहे हैं। हमें यह करने की जरूरत है कि जिस चीज की हमारे पास एक्सपर्टीज उपलब्ध नहीं है, वह माल बेचने की नहीं है। हम बैस्ट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं परंतु उसको बेचना कैसे व कहां है, उसकी ब्राडिंग कैसे करनी है और कौन-सी मार्किट में बेचना है। मेरा कस्टमर कैसे दिखेगा या मेरा चैनल कैसा होगा, हमें यह सब करने की जरूरत है। इसको हम कैसे सैटअप कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा।

टी सी द्वारा जारी

01.09.2025/1835/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री भवानी सिंह पठानिया ... जारी

लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य चार प्रोडक्ट्स की बात करूंगा जिनमें लहसुन पाउडर की मार्किट लगभग 22,000 करोड़ रुपये की है। प्याज पाउडर की मार्किट लगभग 12,500 करोड़ रुपये की है। सूखी अदरक पाउडर यानी सौठ की मार्किट लगभग 1,27,000 करोड़ रुपये की है और हल्दी पाउडर की मार्किट लगभग 22,000 से 25,000 करोड़ रुपये

की है। जूस की मार्किट का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं कि यह 15,000 करोड़ रुपये के आसपास है। इस प्रकार पूरे देश में इन प्रोडक्ट्स की कुल मार्किट लगभग 2,50,000 करोड़ रुपये की है। अब यदि हमें इस मार्किट तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें किसान को प्रोत्साहन देना होगा ताकि वह पारंपरिक गेहूं, जौ, मक्की और दालों की खेती से हटकर कैश क्रॉप्स की ओर आए तो Government policy on diversification of the crop pattern हमने इसकी शुरुआत कर दी है और प्राकृतिक रूप से जो किसान गेहूं और मक्की उगा रहे हैं, इस पर पहले से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया है। पहली बार हल्दी पर 90 रुपये प्रति किलो का मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज पर भी सपोर्ट प्राइस दिया जाए। यह कदम न केवल किसानों की आर्थिकी को मजबूत करेगा बल्कि इससे प्रदेश का टर्नओवर भी बढ़ाएगा। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा।

दूसरा कदम क्लस्टर एप्रोच एडॉप्ट करनी पड़ेगी जैसे सिरमौर क्षेत्र लहसुन और अदरक के लिए उपयुक्त है, देहरा और जसवां-परागपुर क्षेत्र हल्दी के लिए उपयुक्त हैं और टमाटर उत्पादन अपर हिमाचल में अच्छा होता है। इन क्लस्टर्स में सहकारी समितियां बनाई जाएं। इन्हें 25 से 30 लाख रुपये की लागत से प्रोसैसिंग यूनिट उपलब्ध कराई जाए। इन यूनिट्स में सुखाने, पल्पिंग और पैकेजिंग का कार्य किया जा सकेगा। इनके लिए किसानों को सीड और बाकी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और सरकार को उनके प्रोडक्ट्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद कर अपने प्रोसैसिंग यूनिट पर लाना है। उसके बाद वहां इसकी पल्पिंग, ड्राई पाउडर और पैकेजिंग का कार्य होगा। तत्पश्यपत् यह प्रोडक्ट आउटसोर्स पार्टनर को पी0पी0पी0 मोड पर हैंडओवर किया जा सकता है। कंपनीज के पास एक्सपर्टीज होती है कि आपको मार्किट

01.09.2025/1835/टी0सी0वी0/एच0के0-2

तक कैसे पहुंचना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर जैसी बड़ी कंपनियों के पास मार्किट तक पहुंचने का अनुभव है। यदि हम इनके साथ टाई-अप कर लेते हैं तो हमारा काम केवल सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग तक सीमित रहेगा जबकि मार्किटिंग का काम ये कंपनियां हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए करेंगी। मुनाफे में से 10 प्रतिशत हिस्सा सरकार के पास रहेगा इसका 50 प्रतिशत सहकारी समितियों को और 50 प्रतिशत सरकार के

राजस्व के रूप में जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, यह 250 लाख करोड़ रुपये की मार्किट है। यदि हम अपने पहले कार्यकाल में ही 5,000 से 8,000 करोड़ रुपये का टारगेट लें तो यह कोई कठिन लक्ष्य नहीं है क्योंकि 5000 रुपये की प्रोडक्शन नहीं करनी है बल्कि प्रोडक्शन पर सेल करनी है और किसी राज्य के लिए एम0आर0पी0 के आधार पर यह 5000 रुपये बहुत ज्यादा राशि नहीं है इसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। जब भी आर्थिक मंदी का दौर होता है तो Government spends in the right direction and that is the best way to get an economy out of depression. यदि हम ग्रामीण आर्थिकी को इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो अगले 5 से 10 वर्ष में हिमाचल का हर नागरिक इसका लाभ पाएगा और आपको आशीर्वाद देगा।

इसके बाद मैं माइनिंग के विषय पर बात करना चाहूंगा। माइनिंग मेरा पसंदीदा विषय है। माइनिंग हमारा कोर सैक्टर है। यदि माइनिंग लीगली होती है तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं लेकिन यदि माइनिंग इल्लीगली होती है तो उसका किसी को कोई फायदा नहीं।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा.... जारी

01-09-2025/1840/NS-YK/1

श्री भवानी सिंह पठानिया ----जारी

अगर माइनिंग अवैध तरीके से हो रही है तो उसका क्या फायदा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई 100 परिवार ऐसे हैं और उनकी कोशिश यह है कि मेरी गाड़ी फॉर्चयुनर है और अगले साल मेरे पास डिफैंडर आ जाए, डिफैंडर गाड़ी बेंटले में बदल जाए तथा बेंटले हेलीकॉप्टर में बदल जाए। 100 परिवारों के लिए यह पॉलिसी मुझे ठीक नहीं लगती है। ये 100 परिवारों के लिए पॉलिसी क्यों है? क्योंकि ये 100 परिवार आर्थिक रूप से सशक्त परिवार हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना में एक धारणा यह भी है कि अगर खड्डों की माइनिंग नहीं करेंगे तो खड्डें भर जाएंगी। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि माइनिंग कौन करेगा? मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 तक सरकार की माइनिंग के लिए

शोर्ट टर्म लीज पॉलिसी होती थी। यह शोर्ट टर्म लीज लोकल व्यक्ति को दी जाती थी। उसको हम कहते थे कि अपनी ट्रॉली में चार बंदे साथ ले और अपने फावड़े व गैंती लेकर उस खड्ड में माइनिंग कर ले क्योंकि उसको 50 मीटर की छोटी-सी माइनिंग लीज दे देते थे। उसके अंदर वह 3 फुट तक माइनिंग कर सकता है। इसका जो प्रोफिट होगा वह तेरा होगा और मुझे एक वर्ष का 30,000 रुपये दे दे। अब इस पूरी पॉलिसी को हमने बायपास करके अपनी माइनिंग पॉलिसी चेंज कर दी है। माइनिंग पॉलिसी में माइनिंग लीज, बड़े-बड़े क्रशर्ज और ये खलीफा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गए हैं। मुझे इनसे भी कोई समस्या नहीं है। मुझे समस्या यह है कि आप माइनिंग कहां कर रहे हैं? आप माइनिंग लीज के ऊपर कुछ नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि वहां पर जितने भी गरीब लोग हैं चाहे वे गुज्जर हैं या हमारे एरिया में अन्य लोग हैं तो आप उनकी जमीनें कच्ची लीज पर ले रहे हैं। उस कच्ची जमीन का रेवेन्यू न मेरे को आ रहा है और न किसी और को आ रहा है। आप उसके ऊपर 10 या 15 फुट खुदाई करके हमें फ्लड का रिस्क बढ़ा रहे हैं तथा उसका प्रोफिट आप खा रहे हैं या फिर दो नम्बर की डिस्ट्रिब्यूशन हर डिपार्टमैंट को हो रही है या वहां पर पैसा जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश का कहां से फायदा हो रहा है? आप व्यक्तिगत विशेष को अमीर बना रहे हैं and where the hell is the benefit for Himachal Pradesh in this one? मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ड्रेजिंग या डिसिल्टिंग आप शोर्ट टर्म लाइसेंस के बेस पर करवाइए। हमारे पास इस समय हजारों

01-09-2025/1840/NS-YK/2

युवा बेरोजगार बैठे हैं जिनके पास अपने एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्ज हैं। आप उनको लीज दीजिए। ये खुद खुदाई करें और मैन्युअल खुदाई करें फिर क्रशर वाले के पास जाकर क्रशिंग करवाएं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रशर वाले ने जहां माल बेचना है वह उसको बेचे। लेकिन विशेषकर सरकारी खड्डों में खुदाई का काम इन बेरोजगारों से करवाया जाए। आप प्राइवेट लैंड पर खुदाई का काम अलाउ कर दें जिसके पास गैर मुमकिन खड्ड है और जो लगभग 250 किल्ले के ऊपर बैठा है तो आप उसको बोलिए कि आपको माइनिंग अलाउड है लेकिन माइनिंग शोर्ट टर्म लीज के हिसाब से अलाउड है और उसका रेवेन्यू सीधा सरकार को आना चाहिए। आप उसको 3 या 4 फुट तक खुदाई अलाउ कीजिए और

क्रशर वाले ने जहां पर क्रशिंग करनी है वहां पर करता रहे। ऐसा करने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरा, बेरोजगारी का इश्यू भी कम होगा। तीसरा, हम कहते हैं कि पंजाबी आकर हमारी खड्डों को खोद रहे हैं और माल ले जा रहे हैं। जब आप उस पंचायत के युवाओं को यह पॉवर दे देंगे कि यह खड्ड तेरी है और इसकी खुदाई आप करेंगे तथा इसके बाद अगर कोई बाहर वाला माइनिंग करने आया तो अपने शरीर का अंग वहां छोड़ कर वापिस जाएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं आएगा, न रेवेन्यू चोरी का इश्यू आएगा और न ही बेरोजगारी का इश्यू आएगा तथा जो दो नम्बर में काम कर रहे हैं तो उनको हर हफ्ते अपने ट्रैक्टरों का चालान भी नहीं करवाना पड़ेगा। मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा कि आज मुझे इसके ऊपर बात करते हुए तीसरा वर्ष है और अगर आप इसके ऊपर शोर्ट टर्म लीज की पॉलिसी बना पाएं तो अच्छा होगा। अगर आपने इसको एक्पेरिमैंट के तौर पर करना है तो इसको फतेहपुर में लागू करके देख लें। हम इसको 'implement to a T' करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं।

सभापति महोदय, मैं तीन मिनट का समय और लूंगा। अब मैं इण्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन और पॉवर का टाई अप है। मैं मान कर चलता हूं कि हमने इण्डस्ट्री के लिए पॉवर के ऊपर जो भी कन्सेशन दी हैं हमें उनके ऊपर दोबारा रिवीजन करना चाहिए। लेकिन दो इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जो टोटली पॉवर हंगरी इण्डस्ट्रीज हैं जिनका लगभग 50 से 60 प्रतिशत खर्चा पॉवर है। इतना खर्चा पॉवर पर होने के अलावा इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि ये एकदम लेबर इंटेंसिव

01-09-2025/1840/NS-YK/3

कंपनीज हैं। एक-एक कंपनी में 10 से 15,000 युवा अब्सॉर्ब हो सकते हैं। पहला टैक्सटाइल इण्डस्ट्री और दूसरा, आयरन स्टील इण्डस्ट्री है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा, यद्यपि हमारी एक इण्डस्ट्रियल पॉलिसी डिफाइन है। लेकिन पॉवर प्वाईंट ऑफ व्यू से आप एक स्पैशल पैकेज टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.09.2025/1845/RKS/एचK-1

श्री भवानी सिंह पठानिया ...जारी

एक स्पेशल पैकेज तैयार करें क्योंकि अगर हम केवल एक भी बड़ी कंपनी को हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं तो 25 से 30 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिल सकता है। इन कंपनी का more than 50 per cent of the expenditure या उनका जो खर्च है वह लगभग 50 प्रतिशत पावर पर है। अगर हम पावर टैरिफ में इन्हें रियायत देते हैं तो इससे हमें केवल रोज़गार का ही नहीं बल्कि इसके साथ all are revenue from industries alongwith अन्य सेक्टर्स में भी आर्थिक लाभ मिलेगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सिरमौर, पांवटा, फतेहपुर या इंदौरा में फ्लोर मिल्स स्थापित की जा सकती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारे पास कनक की अच्छी उपलब्धता है। चाहे वह ITC जैसी कंपनियां हों या अन्य बड़ी कंपनियां इनके लिए हमें एक विशेष पैकेज बनाना चाहिए क्योंकि इसका कच्चा माल हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। अगर इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए तो हम एक माह के भीतर 50 से 75 करोड़ रुपये की आय अर्जित कर सकते हैं। अब मैं एक और व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। अगर हम सरकारी वाहनों की बात करें तो इनके नंबर आमतौर पर 1 से 9 के बीच होते हैं। मुझे सरकारी गाड़ियों की कुल संख्या का आंकड़ा तो ज्ञात नहीं लेकिन मेरा बिंदु यह है कि यह वी0आई0पी0 नंबर किसलिए चाहिए? गाड़ियों के ऊपर बत्ती लगी होती है जिससे यह साफ हो जाता है कि उसमें कोई वी0आई0पी0 ही बैठा है। अगर हम इन वी0आई0पी0 नंबरों को ऑक्शन कर दें तो इससे 50 से 100 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हो सकती है। इसी सदन के सदस्यों ने भी 12-12 लाख रुपये देकर ऐसे नंबर खरीदे हैं। So auction of all VIP numbers of the Government vehicles is done तो यह बिल्कुल शोर्ट-टर्म में हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार में रहते हुए हमें वी0आई0पी0 या सिंगल नंबर की कोई आवश्यकता होनी चाहिए। जितने भी वी0आई0पी0 नंबर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास हैं उन्हें ओपन ऑक्शन के माध्यम से आबंटित किया जाए तो यह एक प्रैक्टिकली सोर्स मोबेलाइजेशन का सुझाव हो हो सकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

001.09.2025/1845/RKS/एचK-2

उद्योग मंत्री : सभापति महोदय, श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने माइनिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। आपने जो शॉर्ट-टर्म उपायों की बात की है, उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जिनके पास छोटे-छोटे मटेरियल्स और मिनरल्स हैं उनके लिए रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आज पर्यावरण से जुड़े मामलों में बहुत लिटिगेशन हैं। सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और हाई कोर्ट में माइनिंग को लेकर काफी केस चल रहे हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति पी0आई0एल0 फाइल कर देता है। अगर रूल-33 के तहत कोई लीगल रास्ता है तो हम कहते हैं कि ऑक्शन कर लीजिए लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पर भी रोक लगा दी है। नालागढ़ में जो माइनिंग यूनिट्स और क्रशर्ज स्थापित हैं उनके खिलाफ NGT में केस चल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जेनुइन यूज के लिए व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने भी यही कहा है और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि माइनिंग के लिए माइनिंग एनवायरनमेंट प्लान बनाना होता है,पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मंजूरी लेनी होती है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग से भी एन0ओ0सी0 चाहिए होती है। आज ये लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी अधिक हो गई हैं कि जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूरा करना बहुत कठिन हो गया है। आपने कहा कि माइनिंग में धनासेठ बैठे हैं और यह बात सही है। अगर कोई आम व्यक्ति माइनिंग यूनिट या क्रशर लगाना चाहे तो करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और आम आदमी के लिए यह संभव नहीं है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

यहां कल ड्रेजिंग पर चर्चा हो रही थी। ब्यास नदी से अगर आप कुल्लू या मंडी में मटेरियल उठाना चाहें तो वहां Forest Conservation Act लागू हो जाता है। लेकिन अगर वही ब्यास नदी हमीरपुर या कांगड़ा में बहती है तो वहां एफ0सी0ए0 लागू नहीं होता। यानी एक ही नदी के लिए दो तरह का कानून है और हमें इसका हल निकालना होगा। यदि हम ड्रेजिंग नहीं करेंगे तो रिवर बैड उठने से लोगों को काफी नुकसान होगा। माननीय

सदस्य आपने बहुत वाजिब बात कही है और हम इसमें रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2025/1850/बी.एस./ए.जी.-1

उद्योग मंत्री जारी....

हम इसमें वाजिब रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को भी फायदा हो जाए और जो लीगल एंगल है उसमें से भी रास्ता निकल जाए। हम क्या करते वर्ष 2017 में हम क्या करते थे गवर्नमेंट लैंड को भी हम लीज पर दे देते थे। व्यक्ति अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, पैरामीटर पर अगर ठीक बैठता होगा तो हम दे देते थे। सबसे बड़ी बात है मीनिंग के लिए हाई कोर्ट की एक कमेटी ने आज से 20 साल पहले पैरामीटर डिसाइड किए हैं कि आपका क्रेशर है, चाहे आपकी मीनिंग रिलीज है उसका डिस्टेंस स्कूल से, हेल्थ संस्थान से, रोड से और ब्रिज से कितना-कितना होना चाहिए? इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है और आपकी जो सजेशन है हम इस पर विचार कर रहे हैं ताकि जेनुइन यूज के लिए तो कम-से-कम आदमी को परमिशन दी जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दीप राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संसाधन जुटाना के ऊपर अपने पक्ष रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सत्ता पक्ष की बातें सुनकर लगता है कि उन्हें इकोनामी का परम ज्ञान हो चुका है लेकिन प्रश्न तब खड़ा होता है कि क्या यह परम ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सदन में भाषणों के लिए रखा गया है जब मुख्य मंत्री जी प्रदेश का बजट बनाते हैं तो आप यह परम ज्ञान की प्रति जो आपको हुई है यह परम ज्ञान उस समय उनकी टीम को और इन्हें क्यों नहीं देते? क्या यह प्रश्न चिह्न नहीं खड़ा करता जो बात कह रहे थे भाई साहब की हाथी के दांत खाने के और और दिखाने के और। इसका जीता जागता उदाहरण हमने अभी-अभी सदन में देखा है।

अध्यक्ष महोदय, संसाधन का अर्थ होता है साधन प्लस शक्ति प्लस उपयोगिता लेकिन किस तरह से सरकार ने पिछले समय का नारा लेकर वर्तमान में कोई निर्णय न लेकर किस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग किया है उसके में कुछ उदाहरण आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं। सबसे पहले संसाधन जो हमारे पास है वह है

01.09.2025/1850/बी.एस./ए.जी.-2

प्राकृतिक संसाधन अगर हम अपने प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो इनमें आते हैं जल, वायु, मिट्टी, खनिज और जंगल। वर्तमान स्थिति जो आज हमारे प्रदेश की हो चुकी है, जल, वायु, मिट्टी, खनिज और जंगलों से जो हमारी आय के साधन है वे एक लंबे समय तक हमारे प्रदेश में नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमें वर्तमान को लेकर जो है चिंता करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस तरह से अधिकतर कई जगह बादल फट रहे हैं, कई जगह बढ़ जा रही हैं, कई जगह जंगल जो है काट कर बह कर नीचे आ जा रहे हैं, किस तरह से हम इन संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे? और तो और जो मिट्टी है। अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में मात्रा और मात्र 38 प्रतिशत एग्रीकल्चर लैंड है, जब हमारे पास जमीन ही नहीं है तो हम किस तरह से कृषि पर निर्भर हो सकते हैं? हमारे प्रदेश में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास दो बीघा से ऊपर भी जमीन नहीं है तो किस तरह से जो खेती की बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं जिन योजनाओं की बात आप सदन में कर रहे हैं उन्हें किस तरह से धरातल पर उतार पाएंगे?

इसके बाद में दूसरे संसाधनों की बात करूं तो हमारे पास आते हैं मानव संसाधन। अगर हिमाचल प्रदेश में मानव संसाधनों की बात करूं तो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग जो उधर अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इन बुद्धिजीवी लोगों पर भी है कि क्या आप लोग इतने सक्षम नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूं क्या यह बुद्धिजीवी लोग इतने सक्षम नहीं, सरकारें तो 5 वर्ष के लिए आती है 5 वर्ष के बाद बदल जाती हैं लेकिन अधिकारी तो परमानेंट 60 वर्ष के लिए हैं। मुख्य मंत्री जी आप ही ने कहा था तो क्या ये 60 वर्ष के कार्यकाल में भी इतने लंबे समय से ये कर्ज को देखते आ रहे हैं तो क्या यह एक पॉलिसी नहीं बन पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश

के लिए जिससे कि हिमाचल प्रदेश कर्ज मुक्त हो सके? यह इनकी कार्यप्रनाली पर,इनकी दूरदर्शिता पर और इनकी सोच पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है।

01.09.2025/1850/बी.एस./ए.जी.-3

दूसरी बात की जाए कि मनुष्य में अगर श्रमदान की बात की जाए तो अधिकतर जो कर्मचारी, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं जोकि सरकार के लिए अपना श्रम करते थे वे कर्मचारी तो आपने शराब के टेकों में शराब बेचने के लिए लगा दिए तो किस तरह से इन संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

तीसरा है, कौशल मनुष्य का जो कौशल है जब हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल अपने बंद कर दिए बड़े-बड़े संस्थान बंद कर दिए उसके अलावा अपने नौकरियां खत्म कर दी जब यह सब चीज ही नहीं होंगी तो हमारे भी हिमाचल प्रदेश का युवा किस तरह से अपने कौशल को दिखा पाएगा? इसी की वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा दिल्ली में जॉब कर रहा है या बेंगलुरु में जा रहा है या हैदराबाद जा रहा है और हमें इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से हमारे प्रदेश के युवा को हिमाचल प्रदेश में वापिस लाया जाए।

इसके अलावा आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधन में आते हैं हमारे धन, पूंजी, मशीन और प्रतियोगिकी और अगर बात करूं मैं धन की बात करूं धन की तो पहली बार जब से मैं सदन में चुनकर आया हूं तब से सिर्फ और सिर्फ मैंने आर्थिक तंगी का रोना देखा है। क्या यह प्रदेश के मुखिया का दायित्व नहीं कि वह पूरे समय के लिए एक दूरदर्शिता के साथ काम करें

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

1.9.2025/1855/डी0टी0/ए0जी0-1

श्री दीप राज जारी..

अगर आप इस कुर्सी पर बैठे हैं तो जब से यानी 2022 के बाद आपकी ऐसी दूरदर्शिता होनी चाहिए थी क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली को ही लोगों ने देखना था। इस मामले में

कहना चाहूंगा कि इन संसाधनों का भी आपने दुरूपयोग किया है। इसके अतिरक्ति जो धनराशि केंद्र सरकार से दो वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी है, उस धनराशि का उपयोग भी आप उचित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सी0एस0आर0 के अधीन जो मेरे विधान सभा क्षेत्र करसोग-बखरोट और रामपुर विधान सभा क्षेत्र के ननखड़ी में जो पैसा आया है उस राशि का उपयोग भी आप नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कहूंगा कि जो प्रदेश विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि प्राप्त हुई है उसका भी उपयोग राज्य सरकार सही ढंग से नहीं कर पाई है। इसके बाद मैं शैक्षिणिक संस्थानो की बात करना चाहूंगा। इसमें चाहे हम इस शैक्षिणिक संस्थानों में पुस्तकों की उपलब्धता की बात करूं, चाहे मैं शिक्षकों की बात करूं, पुस्तकालय हैं, चाहे उसमें विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं चाहे स्कूल्ज ही हैं। हिमाचल प्रदेश का बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है। लेकिन इतना बजट खर्च करने के बावजूद भी पिछले अढाई वर्ष में सरकार ने क्या किया? आपने प्रदेश में पहले खोले गए स्कूल्ज को बंद कर दिया, विश्वविद्यालय बंद कर दिए। संस्थानों को बंद करने के बाद भी सरकार क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरेंस प्रदेश में नहीं कर पा रही जबकि इस क्षेत्र में इतना अधिक बजट का प्रावधान है। वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या रिफार्म लाए गए? क्या सरकार के द्वार शिक्षा प्रणाली की कार्यप्रणाली के क्षेत्र में कोई नई योजना जोड़ी है? सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई योजना नहीं चलाई गई। आपने इस सदन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के सदस्या को भाषण करवाया और अपने पक्ष के सदस्यों से अपने पक्ष में तालियां बजवाई।

अब मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा संसाधनों को कुप्रबंधन किस प्रकार से हो रहा है। वन प्रबंधन के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वनो के कटाव का कुप्रबंधन देखा। यह सारी चीजे आपके समय में हो रही हैं क्योंकि इस समय आप सत्ता में हैं। अगर इस क्षेत्र में ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर सरकार ने क्या निर्णय लिए, दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, सरकार को इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है।

1.9.2025/1855/डी0टी0/ए0जी0-2

अगर मैं जल संसाधन की बात करूं तो जल संसाधन में सैस की बात की जाती है। लेकिन हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारे डैम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिसके कारण हमारे हाइड्रो प्रोजैक्टस हैं वह स्लोडाउन हो चुके हैं। किसी प्रोजैक्ट का काम 2 साल में शुरू होना था तो वह 10 साल में बनकर तैयार हो रहा है। पानी खारा होने के कारण बिजली नहीं बन पा रही है। इस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है।

आर्थिक संसाधन और ऋण के बारे में मैं क्या कहूं? इसमें प्रबंधन का जीता जागता उदाहरण संसाधन जुटाने की जगह आपदा में जो प्रबंधन हुआ उसमे कितना बड़ा मिस-मेनेजमेंट हुआ। क्या उस मिस-मेनेजमेंट को लेकर हम विपक्ष के सदस्यों ने बार-बार इस सदन में कहा कि प्रदेश में संसाधनों को दुरूपयोग हो रहा है।

अध्यक्ष : श्री दीप राज जी कृपया आप दो मीनट बैठ जाइए, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दीप राज जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कॉरेक्शन्ज करना चाहता हूं। अगर आप अपनी पूरी बात कह देंगे तो आपको इन कॉरेक्शन्ज को सुनने में मजा नहीं आएगा। आप हमारी सरकार के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारी सरकार जब प्रदेश में बनी तो हमने प्रदेश के लिए एक नई दिशा तय की और दिशा को लेकर हम आगे बड़े। आप कह रहे हैं कि सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, विश्वविद्यालय बंद कर दिए, लेकिन क्यों बंद किए? जब उन स्कूल्ज में बच्चे ही नहीं है तो क्या उस स्कूल को वैसे ही खुला रखें? इसलिए माननीय सदस्य आप इस बात का भी अध्ययन करना इन स्कूल्ज को बंद या मर्ज क्यो किया गया? दूसरी बात यह है कि हमने जो निर्णय पहले बजट में लिए थे उसके परिणाम अब सामने आने शुरू हो गये हैं। आर्थिकी मजबूती कैसे होगी, दो बीघे वाला भी गाय रखेगा तो उसको दूध के 53 रुपये मिलेंगे। अगर

1.9.2025/1855/डी0टी0/ए0जी0-3

उसके पास 5 बीघा जगह होगी तो वह 90 रुपये हल्दी, 60 रुपये गेहूं और 40 रुपये प्रति किलो मक्की बेचेगा। श्री भवानी सिंह पठानिया जी भी काफी अच्छे सुझाव दे रहे थे और

आप आगे-आगे देखिए कि क्या होता है। हमारी जो सोच थी हमने उसे धरातल पर उतारने का कार्य किया और इसके लिए स्वाभाविक रूप से समय लगता है। ये चीजें धरातल पर आ चुकी है लेकिन इन्हे कैसे स्पीड देनी है उसके बारे में हम आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे कि कितनी स्पीड से यह कार्य हो रहा है। श्री केवल सिंह पठानिया जी संसाधन जुटाने के लिए प्रस्ताव लाएं हैं। आप इस बारे में हमें और सुझाव दीजिए। जो माननीय सदस्य बिजली की बात कर रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। आपको तो विरोध करना है लेकिन विरोध का तरीका भी तर्क के साथ होना चाहिए।

अध्यक्ष : सदन का समय 07.00 बजे तक निर्धारित किया गया था लेकिन माननीय सदस्य श्री दीप राज ने अपनी बात कंक्लूड करनी है,

एन0जी0 द्वारा जारी

01.09.2025/1900/ए.एस.-एन.जी./1

अध्यक्ष........जारी

माननीय सदस्य, श्री दीप राज, इससे पहले कि मैं आपको अपना वक्तव्य देने के लिए कहूं, आप इसे पूर्ण करने के लिए कितना समय लेंगे?

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट में दे दीजिए।

अध्यक्ष : ठीक है। अब इस माननीय सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

(माननीय सदन की बैठक 7:10 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गाय का दूध 53 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, उसमें सरकार ने सैंकड़ों वेटरनरी संस्थान बंद कर दिए हैं। जब गाय को टीका ही नहीं

लगेगा तो उसका दूध कैसे ठीक आएगा? हिमाचल प्रदेश की लगभग सभी सड़कें इस समय बंद पड़ी हैं। लोगों को 2-2, 5-5 लीटर दूध अपने-अपने घरों के बाहर फेंकना पड़ रहा है। आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? यहां पर 5 बीघा की बात की गई कि 5 बीघा में खेती की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत लोगों के पास 2 बीघा से भी कम जमीन है और मैं यह सब तथ्यों के साथ कह रहा हूं। यहां पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम हल्दी खरीदने की बात की गई है। हल्दी उगाने के लिए पहले जमीन भी तो होनी चाहिए। हमारे अधिकतर किसानों के पास माकूल जमीन ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 67 प्रतिशत फोरेस्ट लैंड है और केवल 32 प्रतिशत प्राइवेट लैंड है तो किसानों के पास कहां से इतनी ज्यादा जमीन आ जाएगी? नालों के किनारे किसी की 2 बीघा या किसी की 1.5 व 2.5 बीघा जमीन थी और वे भी बरसात के पानी बह गई हैं।

01.09.2025/1900/ए.एस.-एन.जी./2

आप कौन-सी जमीन पर हल्दी की खेती करने की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसके लिए तो जमीन मित्र लगाने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने किस प्रकार से पंचायतों के संसाधानों का दुरुप्योग किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक प्रधान ने स्कूटी के माध्यम से करोड़ों रुपयों की सड़कें बना दी हैं। उस व्यक्ति को सरकार में बड़े पद पर भी बिठाया गया है। क्या यह संसाधनों का दुरुप्योग नहीं है? क्या यह प्रदेश के लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? जब सरकार इस प्रकार के निर्णय लेगी तो किस तरह से प्रदेश के हित की बात करेगी?

अध्यक्ष महोदय, अगर हमें आपदा के क्षेत्र में कहीं सबसे भ्रष्ट प्रबंधन देखने को मिला है तो एच0पी0एम0सी0 में देखने को मिला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज भी सेब से भरी हुई बोरियां सड़ रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या यह प्रदेश के संसाधनों का दुरुप्योग नहीं है? मेरे पास ऐसे कईं उदाहरण है लेकिन

समय की कमी के कारण बता नहीं सकता। जब भी चर्चा होती है तो यह बात हमेशा आती है। लेकिन प्रदेश हित में जो भी अच्छे निर्णय होते हैं वे हमें बजट में देखने को नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी की बजट बनाने वाली टीम अलग है और यहां पर भाषण देने वाले सत्ता पक्ष के लोग अलग हैं। यह बिल्कुल तथ्यों के साथ सिद्ध हुआ है। हमारे प्रदेश पर बहुत कर्जा है और हमें इसके लिए बड़ा सोचना होगा। यह चवन्नी-चवन्नी बचा कर लाखों करोड़ों रुपयों का कर्जा वापिस नहीं दिया जा सकता और कब तक चवन्नी घीसते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एच0पी0एम0सी0 के साथ फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएं और उन्हें मिनी पी0एस0यू0 घोषित कर दिया जाए। उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा इंवेस्ट करवाए जाएं।

01.09.2025/1900/ए.एस.-एन.जी./3

इससे सरकार के आय के साधन बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार ने जो झूठी गारंटियां दी हैं, उनके लिए भी दो-चार पैसे इक्ठे हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मिल्क प्लांट की बात की गई। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा मिल्क उस क्षेत्र में होता है जहां पर घास अच्छी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि आनी, करसोग, सिराज, रामपुर, रोहड़ू और नाचन विधान सभा क्षेत्रों में दूध बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन क्षेत्रों से दूध को मिल्क प्लांट्स तक तो पहुंचाना पड़ेगा और यह डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से नहीं होगा। इसके लिए तो मिल्क फेड की गाड़ियां ही लगेंगी। लेकिन मेरे इलाके में तो यह दुर्दशा बनी हुई है कि दूध इक्ट्ठा करने के लिए खाली ड्रम भी नहीं है और सरकार मिल्क प्लांट की बात कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एग्रीकल्चर लैंड की बात की गई और मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि जब जमीन ही नहीं है तो कृषि कहां से होगी? मुख्य मंत्री जी, मेरे कुछ सुझाव हैं और यदि आप इन्हें इम्पलिमैंट करेंगे तो अच्छा होगा। हर व्यक्ति समय के साथ चलता है और समय के साथ चलते हुए आगे बढ़ता है। आप प्रदेश के मुखिया हैं और आपका दायित्व भी बड़ा है। आज हमें यदि सीखने की जरूरत है तो उससे सीखना चाहिए जो पूरी दुनिया में नम्बर-1 पर है। मैं आई0टी0 की बात करना चाहता हूं क्योंकि आई0टी0 इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वे तेजी से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो हालात बने हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है कि लम्बे समय तक हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट नहीं आएगा और सरकार की आय भी नहीं बढ़ेगी। हमारे प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें मार्किट तक ले जाने में भी बहुत मुश्किल होगी। मेरा सुझाव है कि हमें हिमाचल प्रदेश में डेटा सेंटर्स बनाने चाहिएं।

01.09.2025/1900/ए.एस.-एन.जी./4

लाहौल-स्पिति एक ऐसी जगह है जहां पर डेटा सेंटर्स बनाए जा सकते हैं या एक आई0टी0 इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है क्योंकि डेटा सर्वर्स ऐसी जगहों पर लगते हैं, जहां पर ठण्डी जगह होती है या अत्याधित कूलिंग स्पेस होता है। यदि वहां पर बिजली की दिक्कत आती है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

01.9.32025/1905/PB-AS/1

श्री दीप राज ...जारी

यदि वहां पर बिजली की दिक्कत आती है तो आप उसके लिए सोलर प्लांट लगाइए। आपने पेखुवाला में इतना बड़ा सोलर प्लांट यह कह कर लगा दिया कि हम बिजली बेचेंगे। आपने वहां पर इतना ज्यादा (***) कर दिया। अगर आप इसकी जगह ऐसे स्थान में सोलर प्लांट लगाते जहां आई0टी0 इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश होती।

अध्यक्ष : (***) शब्द रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, आप वहां पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते तो उससे प्रदेश की आय के साधन भी बढ़ते जिससे हमारा प्रदेश कर्ज मुक्त हो सकता है। इसके अलावा सदन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत बात की जाती है कि इ-व्हीकल के लिए लोगों को सब्सिडी दी गई। आपने इंसेंटिव को सब्सिडी का नाम दे दिया। मुझे नहीं पता कि अधिकारी आपको कैसी सलाह देते हैं? सब्सिडी और इंसेंटिव में बहुत फर्क होता है। मैंने इस बारे में प्रश्न भी पूछा था और मेरे पास उसका उत्तर भी है। ...(घण्टी) मेरे पास समय कम है इसलिए मैं उसे यहां दिखा नहीं सकता। अगर हिमाचल प्रदेश में हम बैटरी, लाइटें बनाने वाली इंडस्ट्रीज या मिनी पी0एस0यू0 को सैटअप करें तो इससे हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ेगी। हमारे प्रदेश के ब्रिलियंट युवा हिमाचल से बाहर बैंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली और अमरीका में अपना कारोबार कर रहे हैं। अगर हम यहां साधन उपलब्ध करवाएं तो हमारे ब्रिलियंट युवा बाहर नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग ज्यादा इंटेलिजैंट होते हैं और यहां का हवा-पानी भी अच्छा है।

सभापति जी, हिमाचल में राज्य सहकारी बैंक स्थापित है। हम एक ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारियों या विधायकों द्वारा ऑनलाइन प्रोसैसिंग की जाती है क्यों न इन सबकी सैलेरी, इंशोरेंस स्टेट कॉपरेटिव बैंक में डाली जाए। हमें पी.एन.बी., एच0डी0एफ0सी0, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक इत्यादि में इतनी ट्रांजैक्शन करने की क्या जरूरत है? इन बैंकों द्वारा हर ट्रांजैक्शन पर एक से डेढ़ रुपये चार्ज किए जाते हैं। शायद मुख्य मंत्री जी ने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा कि यूको0 बैंक द्वारा हर ट्रांजैक्शन पर तीन रुपये चार्ज किए जाते हैं और ए0टी0एम0 के कार्ड स्वाइप पर 1.5 रुपये चार्ज

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

01.9.32025/1905/PB-AS/2

किए जाते हैं। हमारा हिमाचल सर्वश्रेष्ठ हिमाचल तभी बनेगा जब हम बैंक सैक्टर हों या आई0टी0 इंडस्ट्री पर काम करेंगे। जैसे हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं वैसे ही हमें मेड इन हिमाचल पर काम करना होगा। यह भाषण और एक-दूसरे के लिए तालियां बजाकर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बजट बनाते समय जिन बड़े

अर्थशास्त्रियों ने मुख्य मंत्री जी को सलाह दी है उन्हें मुख्य मंत्री जी बुलाएं और इन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें।...(घण्टी)... मुझे लगता है कि वे वास्तव में मुख्य मंत्री जी को कोई ज्ञान नहीं देते हैं और इन्हें गलत गाइड करते हैं। अगर आप मेरे सुझावों को सही दिशा में यूटिलाइज करेंगे तो किसी-न-किसी तरह से हिमाचल प्रदेश का कर्ज खत्म हो जाएगा नहीं तो अगली बार फिर से इसी विषय पर भाषण होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक कल मंगलवार, 02 सितम्बर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**

दिनांकः 01.09.2025 **सचिव**